चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

मूल्य 5 रुपये

1986 से प्रकाशित

04 नवंबर–10 नवंबर 2013

चुनावी सर्वे लोगों को भ्रमित करते हैं

आम आदमी पार्टी का दावा है कि वह दिल्ली में सरकार बनाएगी. इस दावे का आधार आम आदमी पार्टी द्वारा किया गया सर्वे है. अगर सर्वे ही चुनाव के मापदंड होते तो सिर्फ़ भारत ही क्यों, दुनिया के किसी भी देश में लोग चुनाव के नतीजे का इंतज़ार नहीं करते. अरविंद केजरीवाल का दावा है कि आम आदमी पार्टी को 32 फ़ीसद वोट मिलेंगे और 70 में से 46 सीट पर उनकी पार्टी के उम्मीदवार जीत दर्ज कराएंगे. वैसे इस तरह का दावा करना राजनीतिक तौर पर तो ग़लत नहीं है, लेकिन हक़ीक़त यह है कि एक ही दिन, एक ही इलाक़े में अगर दस सर्वे एक साथ होते हैं, तो ये मान कर चलिए कि इन सभी के नतीजे अलग-अलग होंगे. इसलिए सर्वे के आधार पर ख़ुद को विजयी घोषित करना भ्रम फ़ैलाने की पराकाष्ठा है. भारत में पहली बार किसी राजनीतिक दल ने चुनावी सर्वे को ही चुनावी प्रचार व प्रोपेगैंडा का हथियार बनाया है. इसलिए आम आदमी पार्टी की सर्वे की सच्चाई को समझना ज़रूरी है.

सभी फ़ोटो–*प्रभात पाण्डेय*

मनीष कुमार

अरविंद केजरीवाल ने इंडिया टीवी के कार्यक्रम आपकी अदालत में एक खुलासा किया कि टीवी चैनलों पर हाल के दिनों में दिखाया गया चुनावी सर्वे एक घोटाला था, जिसमें 4–5 टीवी चैनल शामिल थे. सर्वे में आम आदमी पार्टी को तीसरे नंबर पर दिखाया गया था. फिर उन्होंने यह दावा किया कि उनके द्वारा किए गए सर्वे के मुताबिक, आम आदमी पार्टी दिल्ली में बहुमत लाएगी. साथ ही उन्होंने सब टीवी चैनलों को यह चैलेंज किया कि सर्वे का रॉ डाटा सार्वजनिक करें, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जो सर्वे कराया है, उसकी सारी जानकारी उन्होंने सार्वजनिक कर दी है. सर्वे का रॉ डाटा आम आदमी पार्टी की वेबसाइट पर है. चौथी दुनिया ने इस आम आदमी पार्टी की वेबसाइट से रॉ डाटा निकाला, प्रश्नावली निकाली, उसका अध्ययन किया तो कुछ चौंकाने वाली जानकारी सामने आई.

अगर कोई सर्वे पिछले चुनाव नतीजे की पुष्टि नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि सर्वे में कुछ न कुछ गड़बड़ है. सर्वे के नतीजों का संकलन करते वक्त इसका ध्यान रखना चाहिए. आम आदमी पार्टी के सर्वे की प्रश्नावली में सवाल नंबर पांच दिलचस्प है. इसमें लोगों से यह पूछा गया था कि 2008 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में आपने किस पार्टी को वोट दिया था. पहले यह जान लेते हैं कि पिछली विधानसभा चुनाव में किस पार्टी कितने वोट आए थे. दिल्ली के 2008 के चुनावों में कांग्रेस पार्टी को 40.31%, भारतीय जनता पार्टी को 36.34%, बहुजन समाज पार्टी को 14.05% और अन्य को 9.3% वोट मिले हैं. अब जरा आम आदमी पार्टी के सर्वे के नतीजों को देखते हैं. आम आदमी के तीसरे सर्वे के मुताबिक, 2008 में कांग्रेस पार्टी को 45.58%, भारतीय जनता पार्टी को 26.24%, बहुजन समाज पार्टी को मात्र 2.79%, मिले हैं. इसके अलावा सर्वे में 22.88% लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया. जिन लोगों ने जवाब नहीं दिया अगर उनके वोटों को भी इसी अनुपात में बांट दिया जाए तो फाइनल नतीजे इस प्रकार हैं. कांग्रेस पार्टी को 55.93%, भारतीय जनता पार्टी को 32.59%, बहुजन समाज पार्टी को 3.43% मिले. सर्वे के नतीजे और 2008 दिल्ली चुनाव के नतीजे के आंकड़े मेल नहीं खाते. चुनाव के वास्तविक परिणाम में कांग्रेस और बीजेपी में वोटों का फ़र्क़ क़रीब 4% का था, लेकिन आम आदमी पार्टी के सर्वे के मुताबिक यह फ़र्क़ क़रीब 23% का है. बहुजन समाज पार्टी के बारे में जो इस सर्वे से पता चलता है वो तो हास्यास्पद है. वास्तविकता में बसपा को 14.05% वोट मिले, जबकि आम आदमी पार्टी के सर्वे के मुताबिक, इसे 2008 में सिर्फ़ 3.43% मिले. अगर सर्वे करने वालों ने अपने सर्वे की इस सच्चाई को देखा होता तो शायद सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करते. अगर पिछले चुनाव के बारे में भी कोई सर्वे सही आकलन नहीं कर सकता है तो इसका मतलब यही है कि यह सर्वे विश्वसनीय नहीं है.

मज़ेदार बात यह है कि आम आदमी पार्टी के सर्वे की प्रश्नावली का सवाल नंबर 8 भी वही है जो सवाल नंबर 5 है. जिसके बारे में पहले ज़िक्र किया गया. सवाल नंबर 5 व 8 में पूछा गया है कि 2008 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में आपने किस पार्टी को वोट दिया था. दोनों ही सवाल एक ही हैं. अब ज़रा देखते हैं कि इस बार इस सर्वे का नतीजा क्या है. इस बार कांग्रेस पार्टी को 42.72%, भारतीय जनता पार्टी को 24.31%, बहुजन समाज पार्टी को 2.40%, मिले. और 28.79% ने कोई उत्तर नहीं दिया. कहने का मतलब यह है कि अगर एक ही सवाल को दो मिनट के अंतराल में पूछा गया तो इस सर्वे के मुताबिक कांग्रेस और बीजेपी के दो–दो फ़ीसदी वोट कम हो गए. एक ही सर्वे में एक ही सवाल पर अलग–अलग नतीजे इस बात को दर्शाते हैं कि यह सर्वे हड़बड़ाहट में जैसे–तैसे तैयार किया गया है. लगता है कि आम आदमी पार्टी को नंबर वन दिखाकर इसका चुनाव प्रचार में इस्तेमाल करने के लिए तैयार किया गया है.

वैसे जब आम आदमी पार्टी के लिए सर्वे कराने वाली एजेंसी सिसरो के डायरेक्टर धनंजय जोशी से यह सवाल किया गया कि एक ही सर्वे में एक ही सवाल दो–दो बार क्यों हैं, तो उन्होंने पूछा कि सर्वे में ऐसा कौन सा सवाल है जो दो बार है. इसका मतलब यह कि डायरेक्टर साहब इस बात से पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं. उन्हें जब सवाल नंबर 5 और 8 बताया गया तो उन्होंने झट से जवाब दिया कि लगता है कि गलती हो गई होगी. वैसे एक सवाल विधानसभा के लिए था तो दूसरा सवाल लोकसभा के लिए था. ऐसा जवाब देकर उन्होंने सर्वे की और भी फज़ीहत कर दी. क्योंकि दिल्ली के चुनावों में कांग्रेस और बीजेपी का अंतर 20 फ़ीसदी नहीं था, जो इस सर्वे में बताया जा रहा है. अरविंद केजरीवाल ने ऐसे सर्वे पर विश्वास कर अपनी साख़ भी दांव पर लगा दी है. अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि किसने उन्हें रॉ डाटा को सार्वजनिक करने का सुझाव दिया था.

2008 विधानसभा चुनाव दिल्ली

सच्चाई और सर्वे का फ़र्क़

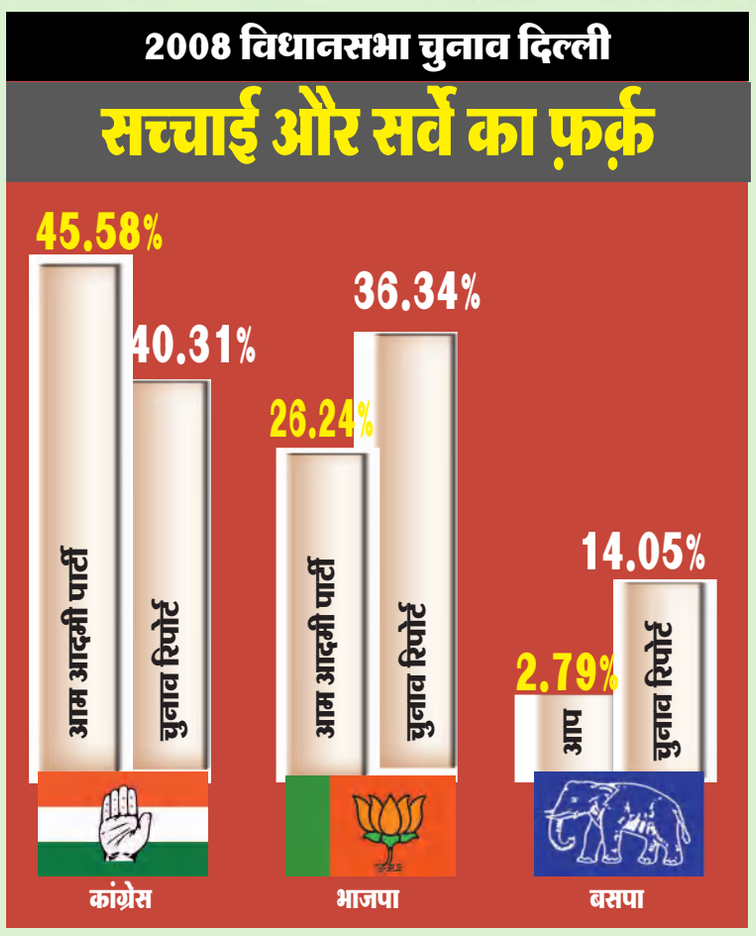

आम आदमी पार्टी का दावा है कि वो ईमानदारी के लिए लड़ रही है. लेकिन ज़रा एक नज़र डालते हैं इस सर्वे की ईमानदारी पर. आम आदमी पार्टी द्वारा किए जाने वाले दूसरे सर्वे में उन्होंने लोगों से कहा कि वो दिल्ली की संस्था ग्लोबल रिसर्च एंड एनालिटिक्स से आए हैं. जब सर्वे कराने वाली एजेंसी सिसरो के डायरेक्टर धनंजय जोशी से बात हुई तो उन्होंने पहले यह बताया कि यह संस्था दिल्ली के साकेत में है. जहां इसे बहुत ढूंढा गया, लेकिन इस संस्था का पता नहीं चला. इसकी कोई वेबसाइट भी नहीं है. इंटरनेट पर जब ढूंढा तो पता चला कि इस नाम की संस्था एस एंड पी यानि स्टैंडर्सड एंड पुअर्स की एक शाखा है. भारत में जिसकी ब्रांच मुंबई, गुड़गांव, चेन्नई और पुणे में है. आपको बता दें कि स्टैंडर्ड एंड पुअर्स एक अमेरिकी वित्तीय सेवा कंपनी है. यह शेयरों व वित्तीय मामले की अनुसंधान और विश्लेषण प्रकाशित करती है. इसकी रिपोर्ट से देशों की सरकारें हिल जाती हैं. अब यह समझ के बाहर है कि आम आदमी पार्टी के सर्वे का इस एजेंसी से क्या रिश्ता है. अगर रिश्ता है तो परेशानी की बात है और नहीं है तो इसका मतलब है कि सर्वे करने वाली एजेंसी ने झूठ की बुनियाद पर यह सर्वे किया. वैसे सिसरो के डायरेक्टर ने बड़े ही संदिग्ध तरीक़े से पूछा कि ग्लोबल रिसर्च एनालिटिक्स के बारे में आपको कैसे पता चला. जब उन्हें बताया गया कि यह जानकारी कहीं से हाथ लगी है तो उनका जवाब था कि कहीं से हाथ लगी जानकारी के बारे में कुछ नहीं कह सकता है. डायरेक्टर साहब को शायद पता नहीं था कि यह जानकारी आम आदमी पार्टी की बेबसाइट पर है. आम आदमी पार्टी के दूसरे सर्वे की प्रश्नावली के पहले वाक्य में यह लिखा हुआ है और इन दस्तावेज़ों को डायरेक्टर साहब के नाम के ज़रिए उसे प्रमाणित बताया गया है. बातचीत में सिसरो के डायरेक्टर ने यह भी बताया कि सर्वे का ग्लोबल रिसर्च एंड एनालिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है. हम साथ में आम आदमी पार्टी के सर्वे की प्रश्नावली भी इसलिए छाप रहे हैं.

आम आदमी पार्टी के सर्वे में दूसरा झूठ लोगों से यह बोला गया कि यह सर्वे अख़बारों के लिए लेख तैयार करने के लिए किया जा रहा है और इस सर्वे का किसी पार्टी या सरकार से कोई ताल्लुक नहीं है और जो जानकारी वो देंगे वो किसी को बताई नहीं जाएगी और उनकी पहचान गुप्त रखी जाएगी. आम आदमी पार्टी ने सिर्फ़ लोगों की पहचान को गुप्त रखा और बाक़ी सारे वादे तोड़ दिए. जो लोग मर्यादा की बात करते हैं, ईमानदारी की बात करते हैं, उन्हें शायद अपने गिरेबान में भी झांककर देखना चाहिए. यह सर्वे आम आदमी पार्टी के लिए किया जा रहा था. इसकी जानकारी न सिर्फ़ सार्वजनिक की गई, बल्कि इसका इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने चुनावी प्रोपेगैंडा के लिए किया. हैरानी की बात तो यह है कि अरविंद केजरीवाल ताल ठोंक कर यह भी कह रहे हैं कि सिर्फ़ वो हैं जिन्होंने सर्वे का रॉ डाटा सार्वजनिक किया है. सही बात है. दुनिया की कोई सर्वे एजेंसी रॉ डाटा को सार्वजनिक नहीं करती है, क्योंकि यह सर्वे करने वालों के एथिक्स के ख़िलाफ़ है. सवाल यह है कि इस सर्वे के सूत्रधार योगेंद्र यादव जी ने 20 सालों में अब तक के किए हुए सर्वे का रॉ डाटा सार्वजनिक क्यों नहीं किया?

इस सर्वे में एक ऐसी बात है कि जिसे समझना ज़रूरी है कि किस तरह सर्वे को भी ट्विस्ट किया जा सकता है. जैसे अगर आप किसी से पूछें कि क्या कोयला घोटाले में मनमोहन सिंह जेल जाएंगे? तो ज़्यादातर लोग जबाव देंगे कि नहीं, क्योंकि लोग इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे कि प्रधानमंत्री भी जेल जा सकते हैं. दूसरा सवाल अगर यह पूछें कि यूपीए के बाकी मंत्री जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उन्हें सज़ा मिलेगी या बच जाएंगे? ज़्यादातर लोग कहेंगे कि बच जाएंगे. फिर आप यह सवाल करें कि क्या देश से भ्रष्टाचार ख़त्म होगा तो ज़्यादातर लोग कहेंगे कि नहीं. भ्रष्टाचार तो ख़त्म हो ही नहीं सकता है. पूरा

(शेष पृष्ठ 2 पर)

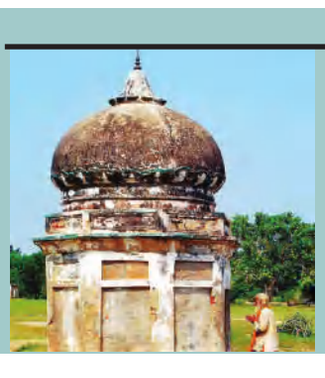

नीतीश के लिए क़ानून व्यवस्था अब भी चुनौती है 03

राजनीतिक दलों में विकास मॉडल की होड़ 05

सपना पीछे छूटा विवाद आगे बढ़ा 06

साई की महिमा 12

चुनावी सर्वे लोगों को भ्रमित करते हैं

पृष्ठ एक का शेष

देश ही भ्रष्ट है. तो इस सर्वे का रिज़ल्ट आएगा कि देश के लोगों का मानना है कि भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं हो सकता है. अब ज़रा दूसरा तरीक़ा अपनाते हैं. यदि सवाल पूछा जाए कि क्या लालू यादव की तरह और भी नेताओं को भ्रष्टाचार के मामले में जेल होगी? तो लोग कहेंगे हां. ये तो अभी शुरुआत ही है. क्या आपको सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास है और क्या आप चाहते हैं कि सभी भ्रष्ट नेताओं को जेल भेजना चाहिए, इसका भी जवाब हां होगा. इसके बाद अगर ये सवाल पूछा जाए कि क्या देश से भ्रष्टाचार ख़त्म होगा. तो लोग कहेंगे कि हां. भ्रष्टाचार ख़त्म करना बिल्कुल संभव है. इसका जवाब होगा कि देश में भ्रष्टाचार ख़त्म किया जा सकता है. आम आदमी पार्टी ने अपने सर्वे में जिस तरह से सवाल बनाया है, उससे यही लगता है कि इस सर्वे का मक़सद आम आदमी पार्टी का प्रचार है, क्योंकि ज़्यादातर सवाल पार्टी से जुड़े हैं और इसमें कांग्रेस व बीजेपी के बारे में इक्का-दुक्का सवाल हैं.

बीजेपी ने सबसे पहले इस तरह सर्वे कराने की प्रथा की शुरुआत की. बीजेपी ने चुनाव के लिए सबसे पहले 1999 के लोकसभा चुनाव में सर्वे कराया था, लेकिन उस वक्त इसे ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया. लेकिन एनडीए सरकार बनने के बाद और जबसे अरुण जेटली पार्टी की चुनावी रणनीति के केंद्र में आए, तब से बीजेपी में सर्वे का महत्व बढ़ गया. लेकिन बीजेपी अपने सर्वे को सार्वजनिक नहीं करती थी. इस सर्वे का मक़सद ज़मीनी हक़ीक़त जानने के लिए किया जाता था. मुद्दे क्या हैं. लोगों का मूड क्या है. उम्मीदवार कैसे होने चाहिए. प्रचार-प्रसार का तरीक़ा क्या होना चाहिए. इन महत्वपूर्ण मुद्दों को समझने के लिए ऐसे सर्वे कराए जाते थे. चुनाव से जुड़े फ़ैसले में ऐसे सर्वे का बहुत महत्व होता था. मज़ेदार बात यह है कि बीजेपी के ज़्यादातर सर्वे ग़लत साबित हुए और सर्वे के आधार पर लिए गए कई फ़ैसले ग़लत साबित हुए. कुछ तो ऐसे ख़तरनाक साबित हुए, जिसकी वजह से बीजेपी जीती हुई बाज़ी गंवा बैठी.

ऐसा कई बार देखा गया है कि सर्वे की सच्चाई सबसे पहले इस पर निर्भर करती है कि सर्वे करने वाले फील्ड-वर्कर ने कितनी ईमानदारी से सर्वे किया है? क्या वो सचमुच लोगों के घर गए? सही ढंग से सवाल किया या फिर किसी तरह से प्रश्नावली को भर दिया? वैसे हक़ीक़त यह है कि ज़्यादातर सर्वे झूठे इसलिए भी साबित होते हैं, क्योंकि प्रश्नावली को लेकर फील्ड-वर्कर लोगों के पास जाता भी नहीं है. ग्रुप बनाकर ये लोग किसी होटल या रेस्टोरेंट में बैठ जाते हैं और अपने हिसाब से उसे भर देते हैं. दिमाग़ इसमें यह लगाया जाता है कि प्रश्नावली को इस तरह से भरा जाए, जिससे वो पकड़े नहीं जाएं. इसलिए ज़्यादातर सर्वे सही नतीजे देने के बजाय कन्फ्यूज करते हैं. सर्वे कराने वाली एजेंसियां दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू युनिवर्सिटी, दिल्ली युनिवर्सिटी के कालेजों व मीडिया इंस्टीट्यूट के छात्रों का इस काम में इस्तेमाल करती हैं, जिन्हें फील्ड वर्क और रिसर्च का अनुभव होता है. ये छात्र इस अनुभव का इस्तेमाल फ़र्ज़ीवाड़े से फार्म भरने में करते हैं. अब सवाल यह है कि जब प्रश्नावली ही जब फ़र्ज़ीवाड़े से भरा गया हो तो सर्वे का परिणाम तो ग़लत ही होगा. अब चाहे कोई रॉ डाटा सार्वजनिक करे या न करे, इससे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता है.

आम आदमी पार्टी ने यह सर्वे सिसरो एशोसिएट्स के द्वारा करवाया था. इस सर्वे में 34,427 लोगों की प्रतिक्रिया ली गई. इन लोगों के दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों के 1,750 पोलिंग बूथ से चुना गया था. वैसे दिल्ली के लिए इतना बड़ा सैम्पल बहुत पर्याप्त है. आम आदमी पार्टी का दावा है कि सभी लोगों के घर जाकर आमने-सामने बैठकर बातचीत की गई और यह सर्वे 5 सितंबर और 5 अक्टूबर के बीच किया गया. लेकिन इस बार सर्वे करने वालों ने ग्लोबल रिसर्च एंड एनालिटिक्स के नाम की जगह सिसरो एसोसिएट्स का नाम लिया. साथ ही कहा कि वो सरकार की तरफ़ से नहीं आए हैं. शायद आम आदमी पार्टी के नेताओं को अपनी भूल का पता चल चुका था कि उन्होंने दूसरे सर्वे में मर्यादा का उल्लंघन किया है. इसलिए तीसरे सर्वे में इसे हटा दिया गया है. लेकिन फिर भी एक सवाल उठता है कि क्या सर्वे करने वाले अन्जान बन कर गए थे? क्या वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे? क्या उन्होंने आम आदमी पार्टी की टोपी पहन कर ये सर्वे किया? यह जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता थे तो वैसे ही इस सर्वे का कोई मायने नहीं रह जाता है. इसे फिर हमें एक पार्टी के प्रचार का एक तरीक़ा समझ लेना चाहिए. वह इसलिए क्योंकि सवाल पूछने वाला कौन है, इससे भी आम लोगों के जवाब बदल जाते हैं. यह सवाल इसलिए उठाया जा रहा है, क्योंकि जिन सवालों का जवाब सीधा था, उसमें क़रीब 27 फ़ीसदी से ज़्यादा लोगों ने अपनी कोई राय नहीं दी.

वैसे भी चुनाव में अभी काफ़ी वक्त है. दिल्ली के बारे में कहा जाता है कि एक दिन में पूरा माजरा बदल जाता है. इसकी वजह यह है कि यहां का चुनाव बहुत ही व्यक्तिगत होता है. पार्टी का आंशिक रोल होता है. उम्मीदवारों को अपने बलबूतों पर ही चुनाव जीतना होता है. एक मज़ेदार बात बताता हूं. 2004 के चुनावों में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री के रेस में हमेशा सबसे आगे रहे. हर सर्वे यही कहता था, लेकिन बीजेपी चुनाव हार गई. वजह साफ़ है कि देश में लोग मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को वोट नहीं देते. वोट स्थानीय एमपी या एमएलए को पड़ता है. अगर वह लोकप्रिय नहीं है तो पार्टी को वोट नहीं मिलते. भारत में ज्यादातर लोग जिसे वोट देते हैं, उसका व्यक्तित्व और उसकी पृष्ठभूमि देखते हैं. इसलिए चुनाव से पहले किए गए सर्वे का कोई मतलब नहीं है. दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने सबसे ज़्यादा उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है. कांग्रेस व भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है. इन दोनों ही पार्टियों में मज़बूत और ज़मीनी आधार वाले कई नेता हैं. जब बीजेपी कांग्रेस के उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी, तब आकलन करने का प्रयास किया जा सकता है. इसलिए यह कहा जा सकता है कि दिल्ली में उम्मीदवारों का पता नहीं, कौन सा मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण रहेगा, इसका पता नहीं है. किस पार्टी का कैंपेन कैसा होगा, यह भी पता नहीं, कौन-कौन नेता, फिल्म स्टार, खिलाड़ी कैंपेन करने दिल्ली आएंगे और उनका क्या असर होगा, यह भी पता नहीं. किस पार्टी के कार्यकर्ता क्या करेंगे, किस पार्टी में विद्रोह होगा, कितने विद्रोही उम्मीदवार खड़े होंगे, अन्ना हजारे व रामदेव के कैंपेन का क्या असर होगा और सबसे महत्व-पूर्ण बात कौन सी पार्टी का मैनेजमेंट कैसा होगा, यह अभी तक किसी को पता नहीं है. और ये बातें ऐसी हैं जिसमें ज़रा सी चूक जीत को हार में बदल सकती है और हार को जीत में. इसलिए चुनाव से पहले किए गए सर्वे का कोई असर चुनाव पर नहीं होता है. आम आदमी पार्टी ने सर्वे का सहारा लेकर चुनावी प्रचार में एक नया प्रयोग किया है. इसे प्रचार के रूप में ही देखना चाहिए.

वैसे भी चुनावी सर्वे इतिहास बताता है. वह भविष्य नहीं बता सकता. यही सच है. अगर कोई यह दावा करे कि सर्वे से किसी चुनाव का भविष्य बताया जा सकता है तो वह लोगों को धोखा दे रहा है. मज़ेदार बात यह है कि कई सालों से सर्वे करने वाली ऐजेंसियां लोगों को और राजनीतिक दलों को मूर्ख बनाती आ रही हैं. हिंदुस्तान में ऐसी कोई सर्वे एजेंसी नहीं है, जिसकी भविष्यवाणी ग़लत नहीं हुई हो. 2004 में सारे सर्वे एनडीए की सरकार को भारी मतों से जिता रहे थे, लेकिन जब परिणाम आए तो सारे सर्वे ग़लत साबित हो गए. देश के सबसे जाने माने व सबसे विश्वसनीय माने जाने वाले योगेंद्र यादव का सर्वे ज्यादातर ग़लत साबित हुआ है. वो कई बार मोदी को सर्वे में हरा चुके हैं. जयललिता को हरा चुके और अमरेंद्र सिंह को जिता चुके हैं और इस तरह कई बार ग़लत साबित हो चुके हैं. जब सबसे विश्वसनीय का हाल यह है तो दूसरों की बात करना ही बेमानी है. कहने का मतलब है सर्वे अपने आप में ग़लत नहीं होते. यह एक तरीक़ा है, एक ज़रिया है जिससे एक अनुमान, बस अनुमान ही लगाया जा सकता है. भविष्य को जानने का कौतुहल मानव स्वभाव है, इसलिए सर्वे प्रजांतत्र और चुनावी माहौल को जीवंत बनाता है, लेकिन इसे आधार बनाकर किसी को विजयी घोषित कर देना लोगों में भ्रम पैदा करना है. ■

manish@chauthiduniya.com

Ac No ☐☐ PS No ☐☐☐ Res No. (As in voter List) ☐☐☐☐

Delhi Opinion Poll-2013

F1. AC Name: _____

F2. Respondent Name: _____

F3. Respondent's Address: _____

(Give landmark to R's house) _____

☐ F4. Is respondent a case of substitution? 1. Yes 2. No

INVESTIGATOR'S INTRODUCTION AND STATEMENT OF INFORMED CONSENT

मेरा नाम ..... है। और मैं दिल्ली की एक संस्था Global Research & Analytics से आया/यी हूं। हम दिल्ली की राजनीति पर एक सर्वे कर रहें हैं जिसके लिए हम कई वोटरों का इन्टरव्यु करेंगे। इस बातचीत के आधार पर अखबारों के लिए लेख तैयार किए जाएंगे। यह सर्वे एक स्वतंत्र अध्ययन है और इसका किसी पार्टी या सरकार से कोई ताल्लुक नहीं है! आप जो भी सूचना देंगे यह किसी को नहीं बतायी जायेगी और आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। इस सर्वे में हिस्सा लेने के बारे में आप स्वयं निर्णय लें। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस सर्वे में हिस्सा लेंगे, क्योंकि आपकी भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। इस इन्टरव्यु में 30 से 35 मिनट लगेंगे। कृपया इस इन्टरव्यु के लिए कुछ समय देकर इस सर्वे को पूरा करने में हमारी मदद करें।

☐ Q5. 2008 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में आपने किसे वोट दिया था? *(Record name of party & consult Codebook for coding)* _____ 9. NA

Q6. अब मैं आपसे आपके निर्वाचन क्षेत्र/Assembly के वर्तमान विधायक/MLA के बारे में पूछुंगा/पूछुंगी।

a. आपके निर्वाचन क्षेत्र/Assembly के विधायक/MLA का नाम क्या है? (_ _ _ _ _ _ _ _ _)
1. Correct 2. Wrong 8. Don't Remember/DK

b. आपके इलाके के लिए उन्होंने कैसा काम किया है?
1. Very Good 2. Good 3. Bad 4. Very Bad 8. Can't say/DK

c. क्या आपकी राय में उन्हें एक और बार विधायक/MLA बनने का मौका मिलना चाहिए?
1. Yes 2. No 8. Can't say/DK

Q7. अपनी बस्ती/मोहल्ले के बारे में सोचते हुए बताएं कि आपके इलाके की कौन सी समस्याएं है जिनपर दिल्ली सरकार को ध्यान देना चाहिए? *(Record 2 answers exactly & consult code book for coding)*

a. _____

b. _____

☐ Q8. 2008 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में आपने किसे वोट दिया था? *(Record name of party & consult Codebook for coding)* _____ 99. NA

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 05 अंक 35
दिल्ली, 04 नवंबर-10 नवंबर 2013
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)
प्रथम तल, विराट कॉम्प्लेक्स के पीछे, सरदार पटेल पथ, कृष्णा अपार्टमेंट के नज़दीक, बोरिंग रोड, पटना-800013
फोन : 0612 2570092, 9431421901

ब्यूरो चीफ (लखनऊ)
अजय कुमार
जे-3/2 डालीबाग कॉलोनी, हजरतगंज, लखनऊ-226001
फोन : 0522-2204678, 9415005111

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.
संपादकीय 0120-6451999, 6450888
विज्ञापन व प्रसार 022-42296060, +91-8451050786, +91-9266627379
फैक्स न. 0120-2544378

पृष्ठ-16+4 (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड) हर शुक्रवार को प्रकाशित

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

दिल्ली का बाबू

बाबुओं को सुरक्षा की दरकार

दिलीप चेरियन

घोटालों की बाढ़ में वरिष्ठ अधिकारियों की संलिप्तता से केंद्र सरकार को जिस तरह से प्रभावित किया है, उससे बाबुओं में बेचैनी है. कोयला आबंटन घोटाले में सीबीआई द्वारा पूर्व कोयला सचिव पीसी पारेख का नाम दर्ज किए जाने के बाद बाबुओं ने स्पष्ट तौर पर निर्णय लिया है कि अब वे इस पर सक्रियता दिखाएंगे. हाल ही में केंद्रीय आईएएस एसोसिएशन ने खुलकर पारेख का समर्थन किया. पारेख के बारे में सिविल अधिकारियों में आमराय यह है कि वे ईमानदार अधिकारी हैं.

ख़बर है कि एसोसिएशन ने अपनी पिछली मीटिंग में तय किया है कि सरकार को उन अधिकारियों की ज़रूरी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, जो उच्च स्तर पर निर्णय लेते हैं. एसोसिएशन के सचिव संजय आर बी रेड्डी ने कहा कि ईमानदार अधिकारियों को सुरक्षा मिलनी चाहिए और सही निर्णय के लिए उनको दंडित नहीं किया जाना चाहिए. इस मामले में आईएएस एसोसिएशन को भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और भारतीय वन सेवा (आईएफओएस) एसोसिएशन का भी समर्थन मिला. वे दोनों संगठन भी अपने सदस्यों के लिए उसी तरह की सुरक्षा चाहते हैं. अब जबकि एक साझे हित के लिए बाबू समुदाय साथ आ गया है तो सरकार को उनकी बात सुननी होगी. क्या उन्हें सफलता मिलेगी? ■

डॉलर में तनख़्वाह पाने की होड़

विदेशी कार्यभार, जिनमें डॉलर में तनख़्वाहें मिलती हैं, की बाबुओं में ज़बरदस्त मांग है. आजकल ज्यादातर योग्य बाबुओं को आशा है कि वे विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक का पद पा जाएं. मौजूदा पदभार हिमाचल प्रदेश कैडर की 1994 बैच की अधिकारी अनुराधा ठाकुर के पास है, जिनका तीन साल का कार्यकाल अगले साल मार्च में पूरा होगा.

बाबुओं पर निगाह रखने वालों का कहना है कि अतीत में यह पोस्ट आमतौर पर उन अधिकारियों को दी जाती रही है जो वित्त मंत्रालय या प्रधानमंत्री कार्यालय में काम कर चुके होते हैं. अपनी बात को पुष्ट करने के लिए वे ऐसे अधिकारियों का उदाहरण भी देते हैं, जैसे- मनोज पंत जो पूर्व वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी के निजी सचिव रहे थे, एलके अतीक और डीपीएस संधू, जो पीएमओ में सेवाएं दे चुके थे. 1972 बैच के आईएएस अधिकारी एमएन प्रसाद भी पीएमओ में रह चुके थे. ये शुरुआती दिन थे, लेकिन अब इस पद की बेहद मांग है, जिस पर काबिज होने के लिए होड़ मची है. ■

बाबुओं को लुभा रही नेतागिरी

ऐसे योग्य अधिकारियों की सूची लंबी है जो बाद में अधिकारी से नेता बन गए. जैसे यशवंत सिन्हा, मीरा कुमार, पीएल पुनिया, मणिशंकर अय्यर, पवन वर्मा, के जे अलफोंस और अरविंद केजरीवाल. चुनाव नजदीक हैं, और राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाले कई अधिकारियों के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि वे सिविल सेवा छोड़कर राजनीति का दामन थाम सकते हैं. उनके लिए अब संभावनाएं बढ़ गई हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग के उस सुझाव को दरकिनार कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि अधिकारियों की सेवानिवृत्ति के दो साल बाद तक उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगे. मजे की बात यह है कि कम से कम तीन, गृह, क़ानून और कार्मिक मंत्रियों ने चुनाव आयोग के प्रस्ताव का समर्थन किया. लेकिन एटॉर्नी जनरल जीई वाहनवती का स्पष्ट मत यह है कि किसी के चुनाव लड़ने के अधिकार को बाधित नहीं किया जा सकता. लेकिन सूत्रों का कहना है कि चुनाव आयोग इस निर्णय से ख़ुश नहीं है और इस मसले पर अपने रुख़ पर क़ायम है. देखिए, आगे क्या होता है. ■

dilipcherian@gmail..com

साउथ ब्लॉक

गोस्वामी आईटीबीपी के महानिदेशक बने

1977 बैच के असम-मेघालय कैडर के आईपीएस अधिकारी सुभाष गोस्वामी को भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस(आईटीबीपी) का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है. इसके पहले वे हैदराबाद स्थित सरदार बल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में बतौर निदेशक कार्यरत थे. मार्च में उन्होंने पुलिस अकादमी के निदेशक का कार्यभार संभाला था.

वीरेंद्र संयुक्त सचिव बने

1984 बैच के भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा(आईए और एएस) वीरेंद्र कुमार की जल्द ही भारत सरकार में बतौर संयुक्त सचिव या उसके समकक्ष किसी पद पर नियुक्ति हो सकती है. वर्तमान में वह नियंत्रक और भारतीय लेखा विभाग के महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं.

प्रिथुल खनन मंत्रालय से जुड़ेंगे

1999 बैच के भारतीय रेल यातायात सेवा अधिकारी प्रिथुल कुमार की बतौर निदेशक खनन मंत्रालय से जुड़ने वाले हैं. वह ए.के. पाटनी के सेवानिवृत्त होने के बाद निदेशक का कार्यभार संभालेंगे. वर्तमान में वह मध्य रेलवे के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक के तौर पर कार्यरत हैं.

श्रेया संस्कृति मंत्रालय से जुड़ेंगी

1994 बैच की राजस्थान कैडर की आईएएस अधिकारी श्रेया गुहा को लंबे इंतज़ार के बाद वित्त सेवा विभाग (डीएफएस) से संस्कृति विभाग भेजा जा सकता है. वर्तमान में श्रेया वित्त सेवा विभाग में निदेशक के रूप में कार्यरत है.

छह सरकारी बैंकों के लिए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की खोज शुरू

छह सरकारी बैंकों और वित्त संस्थानों के अध्यक्षों और की खोज का कार्य 31 अक्टूबर से शुरू हो गया है. जिसमें एक्जिम बैंक भी शामिल है. वित्त मंत्रालय ने अक्टूबर महीने के अंत में चयन प्रक्रिया को प्रारंभ करने का निर्णय लिया क्योंकि अगले वर्ष के प्रारंभ में इन बैंको में रिक्तियां होने वाली हैं. साथ ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अरुंधति भट्टाचार्य के एसबीआई प्रमुख बनने के बाद से प्रबंध निदेशक का स्थान रिक्त हो गया था. इस पद को भरने के लिए भी साक्षात्कार हो रहे हैं. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

नीतीश या उनके सिपहसालार लगातार विफल होते नज़र आ रहे हैं. अपराध की घटनाएं तो बढ़ी ही हैं. हाल के दिनों में साम्प्रदायिक दंगों के भी मामले सामने आए हैं. नवादा और बेतिया में साम्प्रदायिक दंगे हुए. नवादा में तो कर्फ्यू लगाने की नौबत आ पड़ी, लेकिन कोई ठोस निर्णय लेने की बजाय सत्तापक्ष हमेशा रटा-रटाया राग अलापता रहा कि यह विरोधियों की साज़िश है.

नीतीश के लिए क़ानून व्यवस्था अब भी चुनौती है

बिहार में सत्तारूढ़ नीतीश सरकार राज्य में बेहतर क़ानून-व्यवस्था क़ायम करने को लेकर इतराती रही है, लेकिन भाजपा से अलगाव के बाद बढ़ी अपराध की घटनाओं और डगमगाती क़ानून-व्यवस्था को लेकर सरकार बैकफुट पर आ गई है. नीतीश के दूसरे कार्यकाल में ही लक्ष्मणपुर बाथे और बथानी टोला नरसंहार के आरोपी बरी भी हुए, जिसे लेकर सरकार पर सवाल उठे. बढ़ते अपराध और आरोपियों पर कार्रवाई न होने को लेकर नीतीश सरकार सवालों के घेरे में है. इन मसलों पर मुख्यमंत्री नीतीश की चुप्पी हैरान करने वाली है...

सरोज सिंह/शशि सागर

साल 2005 में नीतीश कुमार की सरकार बनने के बाद अगले साल दशहरे पर एक अख़बार की सुर्ख़ियां कुछ इस तरह थीं-डर का रावण भागा, रात भर पटना जागा, लेकिन सत्ता पाने के लगभग आठ साल बाद इसी अख़बार की सुर्ख़ियां हत्या, नरसंहार व लूट की ख़बरों से भरी पड़ी हैं. ख़ासकर जबसे भाजपा सरकार से बाहर हुई है, लगता है रुका हुआ अपराध बाढ़ की तरह फैल रहा है और सरकार व पूरा प्रशासनिक अमला बेबस दिख रहा है.

जिस लॉ एंड ऑर्डर पर ये इतराते थे, अब वह बिगड़ती जा रही है, लेकिन इन स्थितियों से उपजी चुनौती से निपटने के बजाए नीतीश की चुप्पी लगातार उन्हें कमज़ोर ही कर रही है. अलगाव से पहले की घटनाओं को छोड़ भी दें, तो हाल के दिनों में ऐसी कई बड़ी घटनाएं हुईं, जिन पर उनकी चुप्पी माथे पर कलंक की तरह हमेशा साथ रहेगी.

जब जदयू-भाजपा के अलगाव की बात चल रही थी, उसी दौरान जमुई जिले के पास नक्सलियों ने दिन-दहाड़े ट्रेन पर हमला कर तीन लोगों को मौत के घाट उतार दिया और रेलवे पुलिस के हथियार भी लूट कर साथ ले गए. विश्वास मत हासिल करने के एक सप्ताह भी नहीं बीता होगा कि बगहा पुलिस गोलीकांड हो गया. बताते चलें कि इस इलाक़े का एक युवक कई दिनों से ग़ायब था और स्थानीय लोग प्रशासन से उसे ढूंढ़ने का दबाव बना रहे थे. इसी क्रम में थाने के समीप थारू समुदाय के लोग धरना दे रहे थे. पुलिस ने लोगों को समझाने के बजाए उन पर गोलियां दागनी शुरू कर दीं. इस घटना में छह आदिवासी समुदाय के लोग मारे गए थे. ज्ञात हो कि 2005 में नीतीश कुमार ने अपनी न्याय यात्रा की शुरुआत चम्पारण के थारू बहुल इलाके से ही की थी, लेकिन पुलिसिया बर्बरता के शिकार इन आदिवासियों के लिए नीतीश कुछ नहीं कहते हैं. पुलिसिया दमन की ये अकेली घटना नहीं है. जब जदयू-भाजपा साथ थे. उसी दौरान फारबिसगंज गोलीकांड की घटना हुई थी. दो साल बीत जाने के बाद भी अब तक पीड़ित अल्पसंख्यकों को न्याय नहीं मिला है. जानकारों ने बताया कि उल्टे फारबिसगंज के लोगों पर पुलिस मुक़दमा वापस लेने का दबाव बना रही है. मधुबनी, औरंगाबाद और हाल में बेगूसराय में पुलिसिया दमन के क़िस्से चर्चित रहे हैं. अभी से कुछ महीने पहले ही पूर्णिया में आदिवासियों को मार गिराया गया, लेकिन नीतीश चुप्पी ही साधे रहे. वहीं छपरा जिले के धर्मासती गांव में मिड डे मील कांड के बाद की उनकी चुप्पी ने तो देश भर में उनकी किरकिरी करवाई. इस हृदय विदारक घटना के बाद भी नीतीश इतने संवेदनहीन बने रहे कि धर्मासती जाना तो दूर बीमार बच्चों को देखने तक पीएमसीएच नहीं गए, न ही एक शब्द कहा. काफ़ी बाद में उन्होंने मुंह खोला तो इसे विरोधियों की सोची-समझी साज़िश बताया और फिर चुप्पी साध ली. इसके बाद उनके सिपहसलारों ने मोर्चा थाम लिया. हैरत की बात तो यह है कि जब वे नहीं बोलते हैं तो उनके सिपहसालार भी चुप ही रहते हैं. जदयू के एक नेता कहते हैं कि अलगाव के बाद लगातार इतनी घटनाएं होती गईं कि नीतीश किस-किस मुद्दे को संभालते और बोलते? जानकारों का मानना है कि अलगाव के बाद जदयू के अंदर ही मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है. हमेशा नीतीश की बातों को मज़बूती से रखने वाले शिवानंद तिवारी भी नाराज़ ही चल रहे हैं. वहीं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव भी कई मसलों पर उन्हें अकेला छोड़ दे रहे हैं. बताया जाता है कि शरद भाजपा से अलगाव के पक्ष में नहीं थे. यही वजह है कि नीतीश इन दिनों बैकफुट पर नज़र आ रहे हैं.

पिछले नौ अक्टूबर को पटना हाईकोर्ट ने लक्ष्मणपुर-बाथे नरसंहार पर फ़ैसला सुनाया. फ़ैसले से देश की बड़ी आबादी हैरान है. वहीं हैरान करने वाली बात यह भी है कि अभी तक सत्ताधारी दल जदयू की तरफ़ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया. बताते चलें कि 1 दिसंबर, 1997 को जहानाबाद के लक्ष्मणपुर-बाथे में यह नरसंहार हुआ था. इस घटना में 58 लोग मारे गए थे. अदालत ने इस मामले में 26 आरोपियों को बरी कर दिया, जिसमें से निचली अदालत ने 16 को फांसी और दस को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी. भाकपा माले के राज्य सचिव कुणाल कहते हैं कि नीतीश सामंतपरस्त शुरू से ही रहे हैं. फ़ैसले से न्याय का संहार हुआ है और पीड़ितों के घाव हरे हो गए हैं. उन्होंने कहा कि नीतीश के पहले कार्यकाल में इन नरसंहारों के आरोपियों को निचली अदालत ने सज़ा सुनाई थी. इसके बाद उन्होंने शोषितों-वंचितों का वोट अपने पाले में कर लिया, लेकिन दूसरे कार्यकाल से नरसंहारकर्ताओं को हाईकोर्ट ने बरी करना शुरू कर दिया. उनके दूसरे कार्यकाल में ही लक्ष्मणपुर बाथे (जहां पर 58 लोग मारे गए थे), बथानी टोला (जहां 21 लोग मारे गए थे), मियांपुर (मृतक संख्या-33) और नगरी (मृतक संख्या-10) नरसंहारों के आरोपी बरी हुए हैं. बहरहाल नीतीश सरकार कह रही है कि वह इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट जाएगी, लेकिन यह भी जानकारी मिलती है कि बथानी मामले में तो सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है, लेकिन गवाहों को संरक्षण नहीं दे रही है और गवाहों को लगातार धमकाया भी जा रहा है. मामले का हश्र ऐसा ही होगा, इसका आभास तभी से होने लगा था, जब सत्ता में आते ही नीतीश सरकार ने इन नरसंहारों की जांच के लिए बने अमीरदास आयोग को ही भंग कर दिया था. बताया जाता है कि अमीरदास आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपने ही वाला था और उसमें सत्ता पक्ष के कई नेताओं के नाम भी थे, जिनका रिश्ता रणवीर सेना से था. राजनीतिक प्रेक्षक बताते हैं कि राजनीतिक हित साधने के लिए यह चुप्पी है. अगले साल लोकसभा चुनाव है और नीतीश को अगड़ी जातियों के वोट का मोह है.

भाजपा से अलगाव के बाद से लगातार जदयू संगठन कमज़ोर होता गया है. कुशल प्रशासनिक क्षमता का अभाव बढ़ता जा रहा है. नीतीश की साख़ भी धूमिल हुई है. हाल ही में एक सर्वे से यह बात सामने आई है कि बिहार में भ्रष्टाचार और लालफीताशाही में ज़बरदस्त उछाल आया है.

अलगाव के बाद से लगातार संगठन कमज़ोर होता गया है. कुशल प्रशासनिक क्षमता का अभाव भी बढ़ता जा रहा है. साथ ही नीतीश की साख़ भी धूमिल हुई है. हाल ही में हुए एक सर्वेक्षण से यह बात सामने आई है कि बिहार में भ्रष्टाचार और लालफीताशाही में ज़बरदस्त उछाल आया है. वहीं सर्वेक्षण में चालीस फ़ीसद लोगों ने यह भी माना है कि बिहार में हाल के दिनों में अपराध बढ़ गए हैं. बिहार पुलिस की वेबसाइट बताती है कि सिर्फ़ अगस्त माह में हत्या के 299 मामले आए हैं. वहीं बलात्कार के 81 मामले एक महीने में सामने आए हैं. नीतीश मुश्किल में घिरते नज़र जा रहे हैं. कभी उन पर आसमानी क़हर बरसता है तो कुछ मुश्किलें उनके घर के लोग ही पैदा कर देते हैं. कुछ महीने पहले उनकी ही सरकार के मंत्री भीम सिंह ने यह कहकर उनकी किरकिरी करवा दी कि लोग तो सेना में भर्ती ही होते हैं शहीद होने के लिए. सैनिकों का जब शव आया था तो न तो नीतीश और न ही उनका कोई प्रतिनिधि हवाई अड्डे पर गया था. इसी तरह बोधगया बम बलास्ट की घटना में जदयू के एक विधायक यह कहकर प्रहसन के पात्र बने कि बम गुजरात का था, लेकिन इन मामलों में भाजपा ज्यादा तत्पर दिखाई देती है. किसी भी मामले को तुरंत संज्ञान में लेती है. सुशील मोदी धर्मासती गांव भी पहुंचे थे. भले ही गांव वालों ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया, लेकिन वे लगातार सरकार को आड़े हाथों लेते रहे. इसी तरह मोदी खगड़िया के धमारा रेल हादसे के पीड़ितों से भी मिलने पहुंच थे और तब उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री को बीमार राज्यपाल से मुंबई में मुलाक़ात करने का समय है, लेकिन वे खगड़िया नहीं आ सकते हैं.

नीतीश या उनके सिपहसालार लगातार विफल होते नज़र आ रहे हैं. अपराध की घटनाएं तो बढ़ी ही हैं, हाल के दिनों में साम्प्रदायिक दंगों के भी मामले सामने आए हैं. नवादा और बेतिया में साम्प्रदायिक दंगे हुए. नवादा में तो कर्फ्यू लगाने की नौबत आ पड़ी, लेकिन कोई ठोस निर्णय लेने के बजाय सत्तापक्ष हमेशा रटा-रटाया राग अलापता रहा कि यह विरोधियों की साज़िश है. पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी कहते हैं कि भाजपा से अलग होने के बाद सरकार का इक़बाल ख़त्म हो गया है. विधि व्यवस्था में काफ़ी गिरावट आई है और सरकार संवेदनहीन हो गई है. अलगाव के बाद यह तो हुआ ही है कि अब उनका विरोध करने के लिए मज़बूत विपक्ष उनके सामने है. प्रो. नवल किशोर चौधरी कहते हैं कि नीतीश विचारधारा के स्तर पर भले मज़बूत हुए, लेकिन राजनीतिक स्तर पर बहुत कमज़ोर हो गए हैं. यही वजह है कि उन्हें चुप होना पड़ रहा है और लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं. वे आगे कहते हैं कि कब तक ये लालू का भय जनता को दिखाकर लोकप्रिय बने रहेंगे. विधि व्यवस्था उनका मज़बूत पक्ष था और अब लगातार विफलताएं सामने आ रही हैं. अब नीतीश नर्वस हो गए हैं. बात सही भी है. अब तक के शासनकाल में नीतीश एक साथ इतनी परेशानियों से कभी नहीं घिरे थे और न ही अकेले पड़े थे. फ़िलहाल स्थिति यह है कि ये आंतरिक और बाह्य दोनों तरह की परेशानियों से घिरे हुए हैं और अलग-थलग पड़े हुए हैं. ■

जदयू के एक नेता कहते हैं कि अलगाव के बाद लगातार इतनी घटनाएं होती गईं कि नीतीश किस-किस मुद्दे को संभालते. अलगाव के बाद जदयू के अंदर ही मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है. उनकी बातों को मज़बूती से रखने वाले शिवानंद तिवारी भी नाराज़ ही चल रहे हैं. वहीं पार्टी अध्यक्ष शरद यादव भी कई मसलों पर उन्हें अकेला छोड़ दे रहे हैं.

feedback@chauthiduniya.com

पार्वती देवी ने लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार में अपने परिवार के नौ सदस्यों को खो दिया था (बाएं). बथानी टोला कांड के आरोपियों को कोर्ट द्वारा बरी किए जाने के बाद प्रदर्शन करते सीपीआई एमएल के कार्यकर्ता (दाएं).

हाल ही में चुनाव आयोग ने एक सर्वे किया है, उसमें अधिकांश युवा मतदाता चुनाव के दिन को गैजेटेड हॉलीडे के तौर पर मनाते हैं. ये वो मतदाता हैं जो दाग़ी छवि के उलट साफ़–सुथरी छवि वाले उम्मीदवार को पसंद करते हैं. अगर वो वोट देने जा ही नहीं रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि दाग़ी उम्मीदवारों के धन–बल से इकट्ठा किए हुए सेट वोट बाहर निकलेंगे और उन्हें ज्यादा मत मिलेंगे.

राइट टू रिजेक्ट

मतदाताओं को मिला नैतिक हथियार

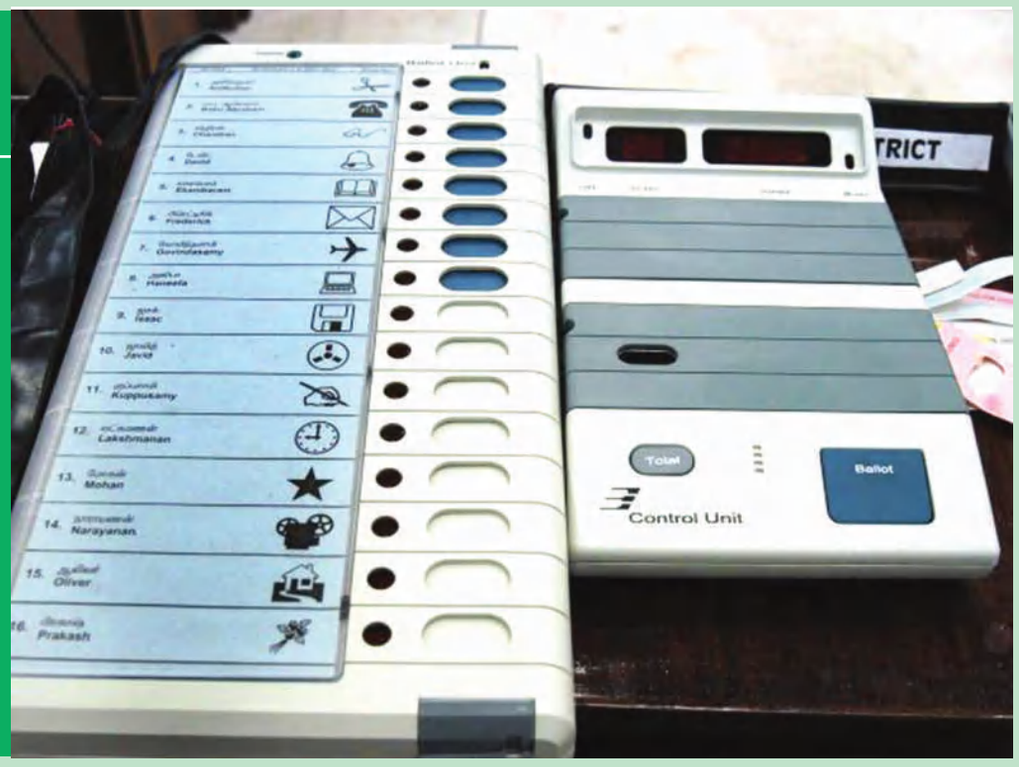

मतदाताओं के हाथ में राइट टू रिजेक्ट का विकल्प देकर सर्वोच्च न्यायालय और चुनाव आयोग ने चुनाव सुधार की दिशा में एक बड़ी पहल की है. हालांकि, राइट टू रिजेक्ट के बाद की स्थिति क्या होगी, इसको लेकर कोई भी स्पष्ट तस्वीर नहीं दिखती. जो लोग इसके विरोध में हैं, उनका तर्क है कि यह केवल मतदाताओं को राजनीतिक ताक़त देता हुआ झुनझुना मात्र है, लेकिन इसके फ़ायदे भविष्य की गर्त में उतनी गइराई तक भी नहीं हैं कि उनका आकलन न किया जा सके. वास्तव में रूढ़ पड़ चुकी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए और मतदाताओं में उत्साह भरने के लिए इस अधिकार की तरफ़ उम्मीद से देखा जा रहा है.

नीरज सिंह

समाजशास्त्री रॉबर्ट डहल ने एक बार कहा था कि भारत में लोकतंत्र के फलने–फूलने के एक भी लक्षण नहीं हैं. 66 वर्ष बीत गए और भारतीय लोकतंत्र न केवल फलता–फूलता गया, बल्कि और मज़बूत होता गया. रॉबर्ड डहल की इस अवधारणा को देश की जनता की लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति श्रद्धा ने कभी फलने–फूलने नहीं दिया. रॉबर्ड डहल ने एक और राजनीतिक व्याख्या की और वह थी दबाव समूह की. समूचे 66 वर्ष के लोकतांत्रिक इतिहास पर गौर करें तो देश की जनता लोकतंत्र के भीतर कभी भी दवाब समूह के तौर पर नहीं उभर पाई. कुछ एक संदर्भों जैसे सूचना के अधिकार और जनलोकपाल जैसे मुद्दों को छोड़ दें तो कभी भी हमें राजनीतिक फ़ैसलों में शामिल नहीं किया गया. अब राइट टू रिजेक्ट के रूप में हमें वह नैतिक हथियार मिलने जा रहा है, जब चुनाव सुधारों की दिशा में जनता दबाव समूह बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है. हालांकि, चुनाव सुधार के तात्कालिक असर कभी भी देखने को नहीं मिले हैं. औषधि विज्ञान की अवधारणाओं से समझें तो भले ही फ़िलहाल राइट टू रिजेक्ट की ज़रूरत पर सवाल उठ रहे हों, लेकिन इसका परिणाम होम्योपैथी दवाओं की तरह रोग के संपूर्ण निदान के तौर पर दिखेगा, न कि एलोपैथी की तरह तात्कालिक लाभ के रूप में.

राइट टू रिजेक्ट या इनमें से कोई नहीं के विकल्प को समझने के लिए पहले सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को समझना होगा, जिसमें उसने चुनाव आयोग को इसे लागू करने की सलाह दी है. अपने इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अगर देश में चुनावों के दौरान अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट देना एक वोट का अधिकार है, उसी तरह किसी भी उम्मीदवार को वोट न देना यानी राइट टू वोट और राइट नॉट टू वोट भी हर मतदाता का अधिकार है. इस तरह अगर कोई मतदाता यह तय करने के लिए स्वतंत्र है कि उसे किस उम्मीदवार को वोट देना चाहिए तो उसे इस बात का भी हक़ मिलना चाहिए कि वह किस उम्मीदवार को अपना वोट नहीं देना चाहता.

अगर भारतीय संविधान या चुनाव नियमों में इससे जुड़ी कोई व्यवस्था पहले से न होती, तब यह कहा जाता कि सांविधानिक स्तर पर ही इस दिशा में खोट है. लेकिन चूंकि यह अधिकार पहले से ही चुनाव नियमों में है. इसलिए स्पष्ट है कि यह यह खोट संविधान के स्तर पर या चुनाव से जुड़े नियमों के स्तर पर नहीं है. यह खोट है वोटिंग की पूरी प्रक्रिया के प्रति लोगों को जागरूक न करना. अभी तक जो व्यवस्था है उसमें अगर मतदाता अगर पोलिंग बूथ पर जाकर मतदान नहीं करना चाहता तो बूथ पर मौजूद रिटर्निंग ऑफिसर मतदाता को फॉर्म 17 (ए) देता है, जिसपर मतदाता अपनी आपत्ति दर्ज करा देता है. यह व्यवस्था लंबे समय से है. लेकिन इस व्यवस्था को लेकर कोई गोपनीयता नहीं है और यह उल्लिखित है कि जिस तरह देश के हर नागरिक को मतदान का अधिकार है उसी तरह उसे गुप्त रखने का भी अधिकार है. इसी अधिकार को कायम रखने के लिए सुप्रीम ने यह आदेश दिया है कि ईवीएम में अंतिम विकल्प के तौर पर नोटा (नन ऑफ दि एबव) का विकल्प दिया जाए. यहां पर सवाल उठता है कि जब यह सारी व्यवस्था पहले से है ही, तो फिर इस पहल पर चर्चा करने की ज़रूरत क्या है. दरअसल, जब से ईवीएम का प्रयोग शुरू हुआ तो मतदान की प्रक्रिया काफ़ी हद तक और पारदर्शी हुई, जिससे लोगों में मतदान के प्रति और उत्साह बढ़ा. इसी उत्साह को देखते हुए यह मांग शुरू

हुई कि राइट टू रिजेक्ट को शामिल किया जाए. लेकिन यह मामला 2001 से ही क़ानून मंत्रायल के पास अटका हुआ था. पिछले दिनों जब सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे जी ने राइट टू रिजेक्ट और राइट टू रिकॉल को अपने 25 सूत्री कार्यक्रम में शामिल किया तो देश में इस मांग को लेकर एक माहौल बनना शुरू हुआ. यह बात सही है कि यह सुधार पहले से ही चली आ रही कागजी व्यवस्था का डिजिटल रिफॉर्म होगा, लेकिन इसके जो दूरगामी परिणाम होंगे उन्हें समझने की ज़रूरत है. हालांकि, गंभीरता से परखा जाए तो यह परिणाम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही रूप में दिखाई दे रहे हैं.

मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों पर गौर करें तो दाग़ी उम्मीदवार अपनी सारी ऊर्जा और धन बल को वोटों को मैनेज करने में लगाते हैं. अब वह वोटों को मैनेज करने में अपना समय जाया नहीं करेगा. दूसरे इस समय देश में राजनीति को लेकर लोगों के मन में उत्साह ख़त्म हो रहा है. हाल ही में चुनाव आयोग ने एक सर्वे किया है, उसमें अधिकांश युवा मतदाता चुनाव के दिन को गैजेटेड हॉलीडे के तौर पर मनाते हैं. ये वो मतदाता हैं जो दाग़ी छवि के उलट साफ़–सुथरी छवि वाले उम्मीदवार को पसंद करते हैं. अगर वो वोट देने जा ही नहीं रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि दाग़ी उम्मीदवारों के धन–बल से इकट्ठा किए हुए सेट वोट बाहर निकलेंगे और उन्हें ज्यादा मत मिलेंगे.

एक और दलील यह भी है यह प्रावधान देश में अस्थिरता ला सकता है. भारत में वोट मुद्दों से ज्यादा जाति और धर्म के आधार पर दिया जाता है और जीत–हार तय करने निकले वह वोटर जो जातीय या धर्म या समुदाय के आधार पर बंटे होते हैं, वह उम्मीदवार के दाग़ी होने से पहले अपने आधारों को देखते हैं. एक और चिंता, और संभवतः यह इस प्रावधान की सबसे बड़ी चिंता है कि कितने वोटरों ने इनमें से कोई नहीं का बटन दबाया, उनकी गिनती नहीं होगी. इस तरह अगर कुल पड़े वोट की तादाद में सबसे ज्यादा वोटरों ने इनमें से कोई नहीं वाला बटन दबा भी दिया तो भी कोई न कोई उम्मीदवार तो हर हाल में जीतेगा ही. जैसे एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल 100 मतदाता हैं और 99 ने इनमें से कोई नहीं का बटन दबाया और एक ने किसी उम्मीदवार को मत दिया है तो वह उम्मीदवार विजयी माना जाएगा.

इस तरह अब होगा यह कि वोटर निगेटिव वोट तो डाल देगा और उसके वोट को कहीं दिखाया नहीं जाएगा. इसे आंकड़ों से समझें तो 2009 में देश में कुल 70 करोड़ मतदाता थे. लेकिन वोटिंग महज 29 करोड़ हुई और इसमें से 11.5 करोड़ वोटरों ने कांग्रेस को वोट दिया और 8.5 करोड वोटरों ने बीजेपी को वोट दिया. कमोवेश इसी तरह करीब एक करोड़ वोट सपा या बीएसपी के पक्ष में पड़े. यानी किस पार्टी को कितने वोट मिले यह चुनाव आयोग के पास दर्ज है. पर अब क्या होगा कि यह सारे आंकड़े तो मिलेंगे कि किस पार्टी को कितने वोट मिले, कौन सी पार्टी का कौन सा उम्मीदवार कितने मत से हारा या जीता. लेकिन कितने मतदाताओं ने किस निर्वाचन क्षेत्र में कितने नन ऑफ द एबव वोट डाले हैं, इसका उल्लेख कहीं नहीं मिलेगा. तो यह माना जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में नन ऑफ दि एबव का विकल्प देकर सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग ने एक रद्दी की टोकरी तैयार कर दी है, जिसमें पड़े हुए माल का कोई हिसाब नहीं होगा. इस तरह अगर मान लीजिए पांच राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों में अगर पांच लाख मत नन ऑफ द एबव के रूप में पड़ते हैं तो उन पांच लाख मतदाताओं को चुनावी आंकड़ों से बाहर कर दिया जाएगा. यह सभी सवाल एकबारगी चिंता बढ़ाते हैं कि जब सब कुछ नकारात्मक ही है तो फिर राइट टू रिजेक्ट को लेकर देश में इतनी चर्चा क्यों है. जब 1857 का ग़दर हुआ था तो भले ही वह असफल हो गया हो, लेकिन उसने देश के लोगों में एक उम्मीद ज़रूर भरी थी कि अगर हम एकजुट होकर और तैयारी के साथ लड़ें तो हम अपने उद्देश्य में कामयाब हो सकते हैं. वास्तव में राइट टू रिजेक्ट का यह विकल्प हमें उसी सोच की ओर ले जाता है. इसीलिए भले ही आगामी कुछ चुनावों में इसके असरकारी परिणाम न दिखें, लेकिन बदलाव के इस क्रम में राइट टू रिजेक्ट के बाद जिस असली हथियार राइट टू रिकॉल की बात हो रही है, वह इसी मांग और उम्मीद के भरोसे हासिल होगा.

मौजूदा चुनावी व्यवस्था पर गौर करें तो कई बार ऐसे उदाहरण सामने आते हैं जब यह ज़ाहिर होता है कि मतदाताओं में नकारा उम्मीदवारों को लेकर रोष है. जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे तो मतगणना करने वाले अधिकारियों को कई ऐसे बैलेट पेपर मिलते थे, जिनमें लिखा रहता था कि सब चोर हैं. ऐसे बैलेट पेपर भी मिलते थे, जिनमें सभी उम्मीदवारों के सामने मुहर लगी होती थी. ऐसा नहीं है कि यह मतदाता ने अनजाने में किया है. वास्तव में यह उनके भीतर का रोष है, जिसे वे मतदान केंद्र तक आकर दिखाना चाहते हैं. अब वह रोष दिखाने का एक वैधानिक माध्यम उन्हें मिल गया है. दूसरे, जब अपने रोष को दिखाने का मौक़ा मिलेगा तो उसे ज़ाहिर करने के लिए लोग बाहर आएंगे, इससे मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा.

तीसरा इसका जो सबसे असरकारी प्रभाव होगा कि अगर प्रत्याशियों के मत प्रतिशत में कमी हुई तो साफ़ ज़ाहिर है कि उन्हें जनता पसंद नहीं कर रही है. इसलिए राजनीतिक दल मज़बूर होंगे कि अगले चुनाव में वे वैसे उम्मीदवार को उतारें जिसकी छवि साफ़ हो और उसे अधिक मतदात–ाओं का समर्थन मिल सके.

वास्तव में इस क़ानून को मौजूदा स्तर पर देखें तो ऐसा लगता है कि इसे लागू करके केवल चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट को ख़ुशी मिलती दिख रही है कि चुनाव सुधार की दिशा में आगे बढ़ते हुए उन्होंने देश की जनता को एक नया राजनीतिक विकल्प दे दिया. लेकिन इसकी असली परीक्षा का चरण यह नहीं है. असली परीक्षा देश के मतदाताओं की है कि वह इस प्रणाली में विश्वास बनाए रखे, उन उम्मीदवारों के विरोध में खड़ा रहे और उनके विरोध में मत करे जिन्हें वह नकारा समझता है. यह लौकिक हथियार नहीं, नैतिक हथियार है जो बदलते वक्त के साथ राजनीतिक पार्टियों को स्वच्छ छवि वाले उम्मीदवारों के साथ आगे बढ़ने को मजबूर करेगा.■

राइट टू रिजेक्ट के रूप में हमें वह नैतिक हथियार मिलने जा रहा है, जब चुनाव सुधारों की दिशा में जनता दबाव समूह बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है. हालांकि, चुनाव सुधार के तात्कालिक असर कभी भी देखने को नहीं मिले हैं. औषधि विज्ञान की अवधारणाओं से समझें तो भले ही फ़िलहाल राइट टू रिजेक्ट की ज़रूरत पर सवाल उठ रहे हों, लेकिन इसका परिणाम होम्योपैथी दवाओं की तरह रोग के संपूर्ण निदान के तौर पर दिखेगा, न कि एलोपैथी की तरह तात्कालिक लाभ के रूप में.

feedback@chauthiduniya.com

विकास महिला छवि बनाने की कोशिश में लगी दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित भी अपने विकास मॉडल के बेहतर होने की बात करती हैं, लेकिन दिल्ली के अस्पतालों में हर साल औसतन दस हजार शिशुओं की मृत्यु हो रही है. दिल्ली के अस्पतालों में पिछले पांच वर्षों में पचास हजार शिशुओं की मौत हुई है.

राजनीतिक दलों में विकास मॉडल की होड़

मोदी गुजरात के विकास मॉडल का हवाला देकर जनादेश मांगने निकले हैं. वे अपनी हर सभा में बताते हैं कि उन्होंने गुजरात में विकास के अनूठे प्रयोग किए हैं, जिसके चलते गुजरात देश का सबसे विकसित राज्य बन गया है, लेकिन विभिन्न मसलों पर, जो देश की असल समस्याएं हैं, उसे लेकर मोदी के पास कोई विज़न नहीं है. नरेंद्र मोदी की जिस तरह कट्टर छवि बनी है, ख़ासकर गुजरात दंगों के बाद, उससे देश के नागरिकों की बड़ी संख्या में खौफ है. इसके अलावा हाल ही में कैग की रिपोर्ट ने उनके विकास के दावे की हवा निकाल दी. रिपोर्ट में कहा गया है कि गुजरात में हर तीसरा बच्चा कुपोषित है. प्रति व्यक्ति आय के मामले में गुजरात 11वें स्थान पर है. गुजरात की विकास दर हरियाणा, राजस्थान, केरल, और आंध्र प्रदेश के मुकाबले निचले पायदान पर है.

कृष्णकांत

इस बार का लोकसभा चुनाव पिछले चुनावों से कुछ मायनों में अलग है. राजनीतिक विश्लेषक यह मान रहे हैं कि इसके नतीजे जो भी आएं, लेकिन चुनाव कई लिहाज से ऐतिहासिक होगा. कई नई अवधारणाएं स्थापित होंगी तो कई पुरानी अवधारणाएं ध्वस्त होंगी. यह चुनाव हमेशा की तरह कई राजनीतिक पार्टियों के बीच तो होगा ही, कई विकास मॉडल भी इस बार आजमाए जाने हैं, जिनके बारे में बेहतरी का दावा किया जा रहा है. राजनीतिक गलियारों में विकास मॉडलों की ऐसी बाढ़ आ गई है कि एक ही पार्टी में कई-कई विकास मॉडल चर्चित हैं. यह चुनाव इनकी परीक्षा का अवसर भी मुहैया कराएगा. देखना यह है कि जनता किसके विकास मॉडल पर भरोसा करती है.

ऐसा नहीं है कि साढ़े छह दशक तक आज़ादी का जश्न मना चुके देश की राजनीति ने आज से पहले विकास की बात नहीं की, लेकिन इस बार देश के विकास को लेकर कुछ ख़ास तरह का हल्ला मचा हुआ है. बेशक इसका श्रेय गुजरात के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को जाता है. भले ही मिथ्या-प्रचार के तहत टीम मोदी की ओर से गुजरात के विकास मॉडल का ढिंढोरा पीटा जा रहा है और एक व्यक्ति अथवा पार्टी के एजेंडे को पब्लिक एजेंडा बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसी बहाने मीडिया में, लोगों के बीच और राजनीतिक गलियारे में विकास की बातें पहले से अधिक होने लगी हैं.

मोदी जब सिर्फ़ गुजरात में सक्रिय थे, तब भी उनकी निगाह दिल्ली की गद्दी पर थी और वे देश के विकास का नारा लगा रहे थे. राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय होने के बाद मोदी और उनकी टीम ने गुजरात के विकास मॉडल को देश में सबसे बेहतर बताकर ऐसा प्रचार शुरू किया, जैसे गुजरात ने कोई अभूतपूर्व विकास कर लिया हो और उसी मॉडल पर पूरा देश विकास का कीर्तिमान रच देगा. मोदी ने दिल्ली में जब पहली रैली की, तब से ही वे गुजरात के बारे में तमाम उजले आंकड़े पेश कर यह बता रहे हैं कि अगर जनता ने उनको मौक़ा दिया तो वे देश की तक़दीर बदल देंगे. मोदी के इस गुजरात मॉडल की काट पेश करने के लिए उनकी पार्टी में प्रधानमंत्री पद के अन्य दावेदारों (जिनमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह भी हैं) का भी विकास मॉडल प्रचारित किया गया. भाजपा की मुख्य विरोधी पार्टी कांग्रेस की ओर से भी बेहतर विकास मॉडल के दावे पेश किए जा रहे हैं.

हाल ही में दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कहा था कि दिल्ली का विकास मॉडल गुजरात के विकास मॉडल से बेहतर है. शीला दीक्षित ने दावा किया कि दिल्ली में जीवन की गुणवत्ता और बुनियादी ढांचे की दुनिया भर में सराहना की जा रही है, जबकि गुजरात में बड़ी तादाद में लोग मूलभूत सेवाओं से वंचित हैं. हालांकि, दोनों बड़ी पार्टियां, जिनके बीच चुनाव में मुख्य मुक़ाबला होना है और उनसे किसी नये विकास मॉडल के घोषणा की उम्मीद की जा जाती है, वे इस पर मौन हैं. दोनों पार्टियों की ओर से किसी नये विकास मॉडल अथवा आर्थिक मॉडल की कोई पेशकश नहीं होनी है. भाजपा की ओर से मोदी ही हैं, जो गुजरात के विकास का हर सभा में ज़िक्र करना नहीं भूलते. उनकी पार्टी के अन्य प्रमुख नेता न तो गुजरात के विकास पर खुलकर बोलते हैं, न ही किसी और मुद्दे पर ढंग से मुखर हो रहे हैं. इसके उलट कांग्रेस ने तो अब तक चुनाव को लेकर किसी भी तरह की घोषणा नहीं की है. हालांकि, यह सबको पता है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार राहुल गांधी ही हैं, लेकिन न तो उनके नाम की अभी औपचारिक घोषणा हुई है, न ही विकास आदि को लेकर किसी तरह का दावा किया जा रहा है. कांग्रेस या भाजपा के विकास के दावों और वादों पर चर्चा करने समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि दोनों ही पार्टियों में से जो भी सत्ता में आएगा, उसकी नीति वही रहेगी जो कि आज है. यह आश्चर्यजनक है कि हाल के वर्षों में सबसे ज़्यादा चर्चा महंगाई की हुई है, जनता में इसे लेकर आक्रोश है, बावजूद इसके महंगाई के मद्देनज़र किसी पार्टी की ओर से कोई नीति घोषित नहीं की गई है. भाजपा और अन्य दल कांग्रेसनीत यूपीए सरकार पर महंगाई को लेकर हमले तो करते हैं, लेकिन यदि वे सत्ता में आते हैं तो महंगाई कम करने लिए क्या करेंगे, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है. कहने को सबके पास अपने-अपने विकास मॉडल हैं, लेकिन सवाल उठता है कि वे मॉडल कौन से हैं, जिनका ढिंढोरा पीटा जा रहा है? इस चुनाव के बाद क्या बदलने जा रहा है? भाजपा आएगी तो उसकी अर्थनीति क्या होगी? उसकी विदेश नीति क्या होगी? पड़ोसी देशों से रिश्ते सुधारने के लिए क्या क़दम उठाए जाएंगे? देश की क़रीब आधी जनता, जो भुखमरी का शिकार है, उसके लिए क्या नीतियां बनेंगी? अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या नीति अपनाई जाएगी? यह सारे सवाल कांग्रेस से भी हैं और ज़ाहिर है कि दोनों पार्टियों में से जो भी सत्ता में आएगी, देश की मूलभूत नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है.

मोदी गुजरात के विकास मॉडल का हवाला देकर जनादेश मांगने निकले हैं. वे अपनी हर सभा में बताते हैं कि उन्होंने गुजरात में विकास के अनूठे प्रयोग किए हैं, जिसके चलते गुजरात देश का सबसे विकसित राज्य बन गया है, लेकिन विभिन्न मसलों पर, जो देश की असल समस्याएं हैं, मोदी के पास कोई विज़न नहीं है. नरेंद्र मोदी की जिस तरह कट्टर छवि बनी है, ख़ासकर गुजरात दंगों के बाद, उससे देश के नागरिकों की बड़ी संख्या में खौफ है. इसके अलावा हाल ही में कैग की रिपोर्ट ने उनके विकास के दावे की हवा निकाल दी. रिपोर्ट में कहा गया है कि गुजरात में हर तीसरा बच्चा कुपोषित है. प्रति व्यक्ति आय के मामले में गुजरात 11वें स्थान पर है. गुजरात की विकास दर हरियाणा, राजस्थान, केरल, और आंध्र प्रदेश के मुकाबले निचले पायदान पर है. नरेंद्र मोदी अक्टूबर, 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, तब से अब तक सत्ता पर काबिज हैं, जबकि पिछले नौ सालों से प्रदेश की औसत विकास दर 6.1 से आगे नहीं बढ़ सकी है. इससे पहले देखें तो 1980 से 1990 के बीच गुजरात में कांग्रेस की सरकार थी. यहां माधव सिंह सोलंकी और अमरसिंह चौधरी इस दौरान मुख्यमंत्री रहे और गुजरात की विकास दर 14.8 थी. 1990 से 94 तक चिमनभाई पटेल की सरकार के कार्यकाल के दौरान गुजरात की विकास दर 16.75 थी. 2005-06 से 2011-12 के बीच बिहार ने 15.7 फीसद कृषि विकास दर हासिल की, जबकि गुजरात में इस दौरान कृषि विकास दर मात्र 6.47 फ़ीसद रही. मोदी ने देश का क़र्ज़ उतारने की बात कही तो गुजरात पर क़र्ज़ की भी चर्चा छिड़ गई कि नरेंद्र मोदी के पहले गुजरात पर 42 हज़ार 780 करोड़ था. इन तेरह सालों में यह बढ़कर एक लाख 76 हज़ार 490 करोड़ रुपये हो गया है. यह भी एक तथ्य है कि गुजरात दंगों के पीड़ित आज भी शरणार्थी कैंपों में जीवन बिता रहे हैं. हालांकि, मोदी गुजरात के विकास को सर्वश्रेष्ठ बताकर जनता से वोट मांग रहे हैं. हाल ही में जब भाजपा में प्रधानमंत्री पद को खींचतान मची हुई थी, भाजपा के पितामह लालकृष्ण आडवाणी ने भाजपाई मुख्यमंत्रियों शिवराज चौहान और रमन सिंह को श्रेष्ठ बताकर हंगामा मचा दिया था.

हाल ही में राज्यों को विशेष मदद दिए जाने के लिए मानक तय किए जाने को लेकर रघुराम राजन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें कहा गया कि गोवा, केरल, तमिलनाडु, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और हरियाणा सबसे विकसित राज्य हैं. गुजरात, जिसके बारे में नरेंद्र मोदी सबसे विकसित होने का दावा करते हैं, वह पश्चिम बंगाल, मिजोरम, सिक्किम, हिमाचल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, मणिपुर, त्रिपुरा और नागालैंड के साथ कम विकसित प्रदेशों में शामिल है, जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, अरुणाचल और मेघालय देश के सबसे पिछड़े राज्य हैं. गौरतलब है कि दो अन्य भाजपाई मुख्यमंत्रियों-शिवराज और रमन सिंह का भी विकास मॉडल चर्चा में है और उसे बेहतर बताकर वोट बटोरने की कोशिशें की जा रही हैं. हाल ही मध्य प्रदेश सरकार की ओर विज्ञापन प्रसारित हुए कि देखो तराजू तौल, बीमारू से अनमोल... रघुराम राजन समिति की रिपोर्ट इस अनमोल प्रदेश की पोल खोलती है. मध्य प्रदेश की विकास दर 10.02 है, जो बिहार जैसे राज्यों से भी कम है और शिवराज का प्रदेश जीवन स्तर के मानकों पर आज भी बेहद बीमारू राज्य ही है. छत्तीसगढ़ का हाल भी इससे इतर नहीं है. रिजर्व बैंक के मुताबिक, केंद्र से सबसे ज्यादा मदद पाने वाला राज्य छत्तीसगढ़ है. बावजूद इसके यहां गरीबों की संख्या बढ़ रही है. राज्य की 40 फीसद जनता गरीब है. राज्य में सौ में मात्र 27 नागरिकों की पहुंच वित्तीय सेवाओं तक है. राज्य में 38.47 फीसद बच्चे कुपोषित हैं. ग्रामीण इलाकों में बड़ी आबादी ऐसी है, जहां अभी तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच ही नहीं सकी हैं. राज्य में साक्षरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दंतेवाड़ा जिले में 1220 गांव हैं, जिनमें से 700 गांवों में विद्यालय ही नहीं हैं.

विकास महिला छवि बनाने की कोशिश में लगी दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित भी अपने विकास मॉडल के बेहतर होने की बात करती हैं, लेकिन दिल्ली के अस्पतालों में हर साल औसतन दस हजार शिशुओं की मृत्यु हो रही है. दिल्ली के अस्पतालों में पिछले पांच वर्षों में पचास हजार शिशुओं की मौत हुई है. यहां शिशु मृत्यु दर प्रति एक हज़ार बच्चों पर 28 है. दिल्ली विकास रिपोर्ट-2013 के अनुसार झुग्गी बस्तियों में रहने वाली करीब आधी जनसंख्या को शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार, दिल्ली स्वास्थ्य की दृष्टि से उच्च जोखिम जोन में आता है. पिछले 10 वर्षों में यहां प्रदूषण का स्तर 21 प्रतिशत बढ़ गया है. यह तथ्य है कि राष्ट्रीय राजधानी होने की वजह से दिल्ली को विकास के लिए केंद्र से धनराशि मिलती है. ज़्यादातर सुरक्षा और कार्यदायी एजेंसियां केंद्रीय हैं या फिर स्वायत्त हैं, जिसका श्रेय भी शीला दीक्षित ख़ुद लेती हैं. शीला के सुशासन और पारदर्शिता की पोल कैग की रिपोर्ट में खुल चुकी है.

सवाल यह है कि यदि विकास के इतने सारे मॉडल हैं, तो जहां पर वे लागू हैं, वहां पर स्थितियां इतनी बदतरीन क्यों हैं? जाहिर है, चुनावी सीजन में विकास मॉडलों की भरमार है, उनका डंका पीटा जा रहा है, लेकिन विकास कहीं नहीं दिखता. सिर्फ चौड़ी सडकें, और सनसनाती कारें विकास का पैमाना नहीं हो सकतीं. किसी भी राज्य या देश को विकसित मानने के लिए वहां का जीवन स्तर, अशिक्षा, बेरोज़गारी, महिलाओं और दलितों की स्थिति परखी जाएगी. इन पैमानों पर देश का हर राज्य फिलहाल फिसड्डी है. फिर वे विकास मॉडल क्या सिर्फ़ पार्टी के प्रचार के लिए हैं? ■

मोदी गुजरात के विकास मॉडल का हवाला देकर जनादेश मांगने निकले हैं. वे अपनी हर सभा में बताते हैं कि उन्होंने गुजरात में विकास के अनूठे प्रयोग किए हैं, जिसके चलते गुजरात देश का सबसे विकसित राज्य बन गया है, लेकिन विभिन्न मसलों पर जो देश की असल समस्याएं हैं, मोदी के पास कोई विज़न नहीं है. नरेंद्र मोदी की जिस तरह कट्टर छवि बनी है, ख़ासकर गुजरात दंगों के बाद, उससे देश के नागरिकों की बड़ी संख्या में खौफ है. इसके अलावा हाल ही में कैग की रिपोर्ट ने उनके विकास के दावे की हवा निकाल दी. रिपोर्ट में कहा गया है कि गुजरात में हर तीसरा बच्चा कुपोषित है. प्रति व्यक्ति आय के मामले में गुजरात 11वें स्थान पर है.

feedback@chauthiduniya.com

शोभन सरकार की बातों पर विश्वास करके पीएमओ खुदाई का आदेश देता है तो भाजपा के पीएम इन वेटिंग नरेन्द्र मोदी को खुदाई का उपहास उड़ाने के कुछ घंटों के भीतर ही संत शोभन सरकार से माफी मांगनी पड़ जाती है. मोदी उनकी तपस्या और त्याग को प्रणाम करने लगते हैं. बुद्धिजीवी पूरे घटनाक्रम पर बुद्धू बक्से के सामने सिर पीटते रहते हैं.

सपना पीछे छूटा विवाद आगे बढ़ा

हम भले ही इक्कीसवीं सदी में पहुंच चुके हों, लेकिन अभी अंधविश्वास से मुक्त नहीं हो सके हैं. यह केवल जनता के बीच हो, ऐसा नहीं है. सरकारें भी अपने बिना अतार्किक फैसलों और असंगत हरकतों से अंधविश्वास को बढावा देती हैं. इसे हास्यास्पद ही कहा जाएगा कि एक तरफ जहां विज्ञान की कसौटी पर सपनों या फिर किसी की आत्मा से बातचीत को कोई मान्यता नहीं दी जाती है. वहीं पुरातत्व विभाग उन्नाव के डौंडिया गांव में राजा राव रामबख्श सिंह के खंडहर हो गए किले की खुदाई करने पहुंच जाते हैं.

अजय कुमार

आस्था और अंधविश्वास के बीच बेहद बारीक रेखा खिंची होती है. कई बार इसकी बारीकी राजा से प्रजा और सरकार से लेकर जनता तक नहीं समझ पाती है. कई मौकों पर जनता ही नहीं, सरकारें तक आस्था के विश्वास में अंधविश्वास का साथ देते हुए दिख जाती हैं, जिसका फ़ायदा चन्द्रा स्वामी से लेकर आसाराम बापू जैसे तमाम कथित संत उठाते रहते हैं. आस्था के नाम पर भोली जनता को साधु-संत ही नहीं ठगते हैं, ठगों का लूट-खसोट का धंधा भी अंधविश्वास के सहारे ख़ूब फलता-फूलता है. अक्सर ही आस्था और अंधविश्वास के सामने वैज्ञानिक सोच और ऐतिहासिक दावों की प्रामाणिकता बेमानी हो जाती है. अनजाने में ही सही, कई बार मीडिया भी ऐसी धारणाओं को बल प्रदान करने का काम करता है. चाहे दो दशक पूर्व गणेश जी को दूध पिलाने की घटना रही हो या फिर ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से जुड़ा हो, जहां एक संत के सपने ने देश ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय मीडिया तक को अपनी ओर आकर्षित कर लिया. देश-विदेश का मीडिया एक हज़ार टन सोना देखने के लिए जंगलों में भटकने लगा. किसी ने इतिहास नहीं टटोला कि कैसे यहां एक हज़ार टन सोना मिल सकता है?

इसे हास्यास्पद ही कहा जाएगा कि एक तरफ जहां विज्ञान की कसौटी पर सपनों या फिर किसी की आत्मा से बातचीत को कोई मान्यता नहीं दी जाती है. वहीं पीएमओ से जारी पत्र के आधार पर पुरातत्व विभाग के अधिकारी जिला उन्नाव के डौंडिया गांव में राजा राव रामबख्श सिंह के खंडहर हो गए किले की खुदाई करने पहुंच जाते हैं और तर्क यह दिया जाता है कि साधु के सपने के आधार पर नहीं, हमने अपनी जांच के बाद यह पाया है कि यहां धातु जैसी कोई चीज़ हो सकती है. केन्द्र और राज्य सरकार के मंत्री संत शोभन सरकार के सपने को साकार करने की कामना में उनके सामने दंडवत करने लगते हैं. सोने पर किसका कितना हक होगा, इस पर भी राज्य सरकार चर्चा शुरू कर देती है. जिस गांव का नाम कल तक पूरे जिले ने नहीं सुना था, वह अंतरराष्ट्रीय सुर्ख़ियों में आ जाता है. राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय मीडिया अपने ओवी वैन के साथ घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं. खुदाई की लाइव कवरेज होती है. जिलाधिकारी महोदय प्रेस को ब्रीफ करते हैं. सोना देखने की चाहत में लोगों का हुजूम जुट जाता है. भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन को धारा 144 लगानी पड़ती है. खुदाई स्थल को सीसीटीवी कैमरे और बैरिकेडिंग के जरिये सुरक्षित किया जाता है. पुलिस और पीएसी के जवान कथित सोने की हिफ़ाज़त के लिए मुस्तैदी के साथ डट जाते हैं. खुदाई स्थल पर खाने-पीने से लेकर सभी ज़रूरतों के सामान वाली दुकानें सज जाती हैं.

शोभन सरकार की बातों पर विश्वास करके पीएमओ खुदाई का आदेश देता है तो भाजपा के पीएम इन वेटिंग नरेन्द्र मोदी को खुदाई का उपहास उड़ाने के कुछ घंटों के भीतर ही संत शोभन सरकार से माफी मांगनी पड़ जाती है. मोदी उनकी तपस्या और त्याग को प्रणाम करने लगते हैं. बुद्धिजीवी पूरे घटनाक्रम पर बुद्धू बक्से के सामने सिर पीटते रहते हैं. खुदाई की कवरेज के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्राइम टाइम एलॉट कर देता है. वहीं दूसरी और खुदाई प्रिंट मीडिया के पहले पेज की ख़बर बन जाती है और अन्य ख़बरों को छोटा कर दिया जाता है. इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार को इस बात की चिंता नहीं रहती है कि आजमगढ़ मे जहरीली शराब से मरने वालों के परिवार के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए ज़हरीली शराब के कारोबारियों पर फंदा कसा जाए, जिसमें क़रीब 45 लोग मौत के मुंह में चले गए थे. इसी तरह से मुज़फ़्फ़रनगर दंगों के बाद के हालात पर से कुछ समय के लिए ही सही, लोगों का ध्यान हट जाता है. सरकार की नाकामयाबी से ध्यान हटा कर लोग सोने के सपने देखने लगते हैं. शोभन सरकार के सपनों की वकालत करने के लिए एक अन्य महात्मा ओमजी इलेक्ट्रॉनिक चैनलों पर प्रकट होते हैं. बाद में पता चलता है कि वह पुराने कांग्रेसी थे और 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उन्होंने राजनीति से तौबा करके अपना जीवन धमार्थ कार्यों में लगा रखा था.

अच्छी बात यह है कि यह ड्रामा कुछ ही दिन चला. खुदाई के हफ्ते भर के भीतर ही एक हज़ार टन सोने की जिज्ञासा नेताओं/ नौकरशाहों/ सरकारों के दिलो-दिमाग़ से काफूर हो गई. खुदाई स्थल से मीडिया और अधिकारी नेता नदारद हो गए हैं. सोने पर हकदारी जताते हुए सामने आए राजा के वारिसों का भी अब कोई अता-पता नहीं चल रहा है. बयान बहादुर अपना बयान पलटने लगे हैं. त्योहारी मौसम में कुछ कमा लेने की चाहत में दुकान सजा कर बैठ गए लोगों ने भी ठिकाना बदल लिया है, लेकिन इस बात का जवाब देने वाला कोई नहीं है कि सारे घटनाक्रम में सरकारी पैसे की जो बर्बादी हुई, उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा. बहरहाल, अभी भी संत के अनुयायी दावा कर रहे हैं कि शोभन सरकार चाहें तो अभी 20 हज़ार टन सोना और सरकार को दिला सकते हैं. सोना मिले या न मिले, लेकिन इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि संत शोभन की नीयत में जरा भी खोट थी. वह देश का भला चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपने स्थानीय सांसद अनु टंडन के माध्यम से केन्द्र तक अपनी बात पहुंचाई थी. उन्होंने सोने के लिए किसी तरह का दावा भी नहीं ठोंका था. बस, वह क्षेत्र का विकास होते देखना चाहते थे, लेकिन एक हज़ार टन सोने की ख़बर ने मेरे ज़ेहन में एक ठग की पुरानी यादें ताज़ा कर दी. कुछ दशकों पूर्व एक ठग ने सोने की आड़ में उत्तर प्रदेश प्रशासन को हिला कर रख दिया था. यह कारनामा करने वाला ठग था मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव उर्फ नटवर लाल, जिसके चरित्र पर कई फिल्में बन चुकी हैं. यह ठग तो यहां तक दावा करता था कि उसे अगर एक बार विदेश भेज दिया जाए तो वह ठगी के बल पर हिन्दुस्तान का पूरा कर्ज़ ही उतार देगा. एक जमाने में जब नटवर लाल लखनऊ जेल में बंद था, तो सिवान जिले में स्थित उसके गांव बंगारा से पत्नी का पत्र आया, जिसमें उसकी पत्नी ने अपनी व्यथा लिखते हुए कहा था, मैं बड़े आर्थिक संकट में हूं, घर में खाने को नहीं है. खेत जोतने के लिए मजदूर भी तैयार नहीं हैं. कहीं से कुछ पैसे की व्यवस्था कराओ. नहीं तो भूख से मर जाऊंगी. पत्र पढ़ते ही नटवर लाल बेचैन हो गया. तभी उसके शातिर दिमाग में एक आइडिया आया. नटवर ने अपनी पत्नी को जवाब में पत्र लिखा कि परेशान मत हो. किसी विश्वसनीय व्यक्ति से खेत के दक्षिणी कोने में एक-डेढ़ फिट खुदवा लेना. वहां एक पोटली में मैंने कुछ जेवरात गाड़ रखे हैं, जिन्हें बेचकर घर चलाओ. जल्दी ही जेल से निकलूंगा, तब मिलूंगा.

क़ैदियों द्वारा लिखकर भेजी जाने वाली चिट्ठियां जेल प्रशासन द्वारा सेंसर की जाती हैं. नटवरलाल की भी चिट्ठी पढ़ी गई. जेल अधिकारी सकते में आ गए. उन्होंने चिट्ठी दबा ली. तत्काल नटवर के गांव बंगारा की जानकारी के लिए बिहार के सिवान जिले के एसपी को लिखित जानकारी भेजी गई. नटवर लाल के खेत पर सिवान पुलिस ने धावा बोल दिया. बताए गए स्थान पर खुदाई की गई. वहां कुछ न मिला तो उन लोगों ने पूरा खेत खोद डाला. खेत में न रुपये मिले, न जेवरात. अधिकारी सिर खुजलाने लगे. नटवर को पूरे प्रकरण की पल-पल जानकारी मिल रही थी. खुदाई की ख़बर सुनते ही उसने पत्नी को दूसरा पत्र लिखा. खुदाई हो गई हो तो फ़सल बो दो. चिंता की कोई बात नहीं.

सोना मिले या न मिले, लेकिन इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि संत शोभन की नीयत में ज़रा भी खोट थी. वह देश का भला चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपने स्थानीय सांसद अनु टंडन के माध्यम से केन्द्र तक अपनी बात पहुंचाई थी. उन्होंने सोने के लिए किसी तरह का दावा भी नहीं ठोंका था. बस, वह क्षेत्र का विकास होते देखना चाहते थे, लेकिन एक हज़ार टन सोने की ख़बर ने मेरे ज़ेहन में एक ठग की पुरानी यादें ताज़ा कर दी.

चर्चा यह है कि जिस तरह नटवर ने अपना परिवार चलाने के लिए साज़िश रची थी, कहीं ऐसी ही किसी सोच को तो किसी ने साज़िशन उन्नाव में सोना होने की बात कहकर आगे नहीं बढ़ाया है, क्योंकि सोने की बात सामने आते ही कई ख़बरें हाशिये पर चली गई थीं. इस समय नरेन्द्र मोदी की यूपी में पहली रैली होने वाली थी. विपक्ष और सरकार रैली की सफलता को लेकर परेशान था. शोभन सरकार के सपने को बेहद प्रचार मिलने की वजह को 2014 के लोकसभा चुनाव से भी जोड़ कर देखा जा रहा है. उन्नाव, फतेहपुर और सोनिया गांधी के संसदीय जिले रायबरेली की सीमाएं आपस में जुड़ती हैं. इस इलाके में बाबा शोभन सरकार के चमत्कार के तमाम किस्से मशहूर हैं. जनता उन्हें भगवान की तरह मानती है और इस भगवान को सभी दलों के नेता अपने पाले में करना चाहते थे, ताकि चुनावी फ़ायदा उठाया जा सके. इसीलिए सपा और कांग्रेस बाबा का महिमामंडन करने में लगे हैं और भाजपा को राजनीतिक नुकसान से बचाने के लिए मोदी को शोभन सरकार के सामने झुकना पड़ जाता है. ■

feedback@chauthiduniya.com

हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी संसदीय हिंदी परिषद, परिचय साहित्य परिषद व विधि भारती परिषद द्वारा संसद के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रभाषा उत्सव का आयोजन किया गया. राष्ट्रभाषा उत्सव की अध्यक्षता पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रतिष्ठित साहित्यकार डॉ. श्याम सिंह शशि ने की. पूर्व केंद्रीय विधि मंत्री और संसदीय हिंदी परिषद की अध्यक्ष डॉ. सरोजिनी महिषी, प्रतिष्ठित साहित्यकार अर्चना वर्मा सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे.

लोकायुक्त विधेयक बना बहुगुणा के गले की फांस

राजकुमार शर्मा

उत्तराखंड में भाजपा शासन के दौरान अन्ना के प्रभाव में बने लोकायुक्त विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद राज्य में सत्तारूढ़ विजय बहुगुणा सरकार के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है. सरकार इस अधिनियम को किसी भी तरह से ठंडे बस्ते में डालकर इससे बचना चाहती है. उत्तराखंड की सत्ता कांग्रेस के हाथों में है, इसके बावजूद भाजपा द्वारा पारित यह विधेयक कानून बनकर चुपचाप अमल में आ गया और सरकार भौचक रह गई. अब राज्य की कांग्रेस सरकार इस मुश्किल में है कि अगर एक राज्य में यह कानून अमल में आता है तो फिर अन्य राज्यों में इसी तर्ज पर लोकायुक्त और केंद्र में लोकपाल लाने को लेकर कांग्रेस पर दबाव बनेगा. यही कारण है कि बहुगुणा सरकार इसे अपने मूल रूप में लागू करने को तैयार नहीं है. राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद मुख्यमंत्री बहुगुणा द्वारा इस विधेयक के कुछ हिस्सों को असंवैधानिक बताए जाने से सरकार नए विवाद में फंस गई है. भाजपा ने इसे न सिर्फ राष्ट्रपति का अपमान बताया, बल्कि सरकार से इस्तीफा भी मांग लिया है.

लोकायुक्त विधेयक को लेकर पैदा हुआ यह विवाद राज्य कांग्रेस सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकता है. दरअसल, अन्ना हजारे के सशक्त लोकपाल की अवधारणा के मुताबिक पूर्व भाजपा सरकार ने लोकायुक्त विधेयक बनाया और विधानसभा से पारित कराकर राज्यपाल की मंजूरी के बाद नवंबर 2011 में राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा था. लगभग दो साल बाद गत सितंबर में इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई. इसके बाद यह विधिवत अधिनियम बन गया. राज्य सरकार के विधायी विभाग ने विगत 24 सितंबर को इसे राज्य के 27वें अधिनियम के रूप में अधिसूचित भी कर दिया. इसके करीब डेढ़ महीने बाद बहुगुणा सरकार को जानकारी मिली कि भाजपा सरकार द्वारा तैयार लोकायुक्त विधेयक अब कानून का रूप ले चुका है तो मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने आनन–फानन इसके कुछ प्रावधानों को असंवैधानिक करार देते हुए इस पर नए सिरे से विचार करने की बात कही.

अब भ्रष्टाचार के खिलाफ इस सशक्त लोकायुक्त अधिनियम के अस्तित्व में आने से सूबे में हड़कंप मचा है. खासकर राजनेताओं, जनप्रतिनिधियों और लोकसेवकों में खलबली है. लोकायुक्त के दायरे में मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, सभी राजकीय सेवक व अधीनस्थ न्यायपालिकाएं हैं. अधिनियम पर अमल होने के बाद भ्रष्टाचारियों की मुश्किलें बढ़नी तय हैं. भ्रष्ट लोकसेवकों से वसूली और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान नए अधिनियम में है, लोकायुक्त को निलंबित करने से लेकर दंडित करने का अधिकार है. लोकायुक्त में भ्रष्टाचार के मामलों का संज्ञान लेने और जांच के लिए तीन विंग इन्वेस्टीगेशन, प्रोसिक्यूशन और ज्यूडिशियल गठित की जाएंगी. लोकसेवा का अधिकार और लोकसेवकों द्वारा भ्रष्ट तरीके से संपत्ति अर्जित करने के मामलों पर लोकायुक्त की नजर रहेगी. साथ ही भ्रष्टाचार में लिप्त लोक सेवकों को पदच्युत करने, पदावनत करने का अधिकार लोकायुक्त को दिया गया है. ऐसी संस्तुतियां मानने को शासन बाध्य होगा. इसमें शिकायतकर्ता को संरक्षण दिया जाएगा व झूठी शिकायत करने पर दंडित भी किया जाएगा.

लोकायुक्त को अवमानना की कार्यवाही का अधिकार भी होगा. लोकसेवकों को भ्रष्टाचार के मामले में लोकायुक्त कम से कम छह महीने का कठोर कारावास (जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है) का दंड दे सकता है. अत्यंत विशेष मामलों में आजीवन कारावास का दंड भी दिया जा सकता है. जांच के दौरान लोकायुक्त सरकारी सेवकों के निलंबन या स्थानांतरण के निर्देश भी दे सकता है. लोकायुक्त में लोकायुक्त संस्था के खिलाफ मामलों की शिकायत भी की जा सकती है. इसका ऑडिट सीएजी (कैग) द्वारा किया जाएगा. इधर, लोकायुक्त अधिनियम में अधीनस्थ न्यायपालिका को दायरे में लेने के प्रावधान को अधिनियम के अस्तित्व के लिए चुनौती माना जा रहा है. न्यायिक सेवा के सूत्र न्यायिक अधिकारियों को लोकायुक्त के दायरे में लेने को हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण के रूप में देख रहे हैं.

लोकायुक्त पांच सदस्यीय संस्था होगी, जिसे अधिकतम सात तक बढ़ाया जा सकता है. लोकायुक्त के आधे सदस्य विधिक पृष्ठभूमि के होंगे, शेष आधे सदस्य लोक सेवा, अन्वेषण, सतर्कता, वित्त प्रबंधन, पत्रकारिता एवं सूचना अभियांत्रिकी से होंगे. चयन समिति में मुख्यमंत्री अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा चयनित दो न्यायाधीश, लोकायुक्त के पूर्व अध्यक्ष, भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, थल सेना, वायु सेना और नौ सेना के सेवानिवृत्त सेनाध्यक्ष, उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश, सेवानिवृत्त केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त, संघ लोक सेवा आयोग के सेवानिवृत्त अध्यक्ष, सेवानिवृत्त कैबिनेट सचिव, सेवानिवृत्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होंगे, जो एक पांच सदस्यीय स्क्रीनिंग कमेटी बनाएगी.

लोकायुक्त में पीठ एवं बेंच होंगी. लोकायुक्त की पीठ देहरादून में बैठेगी. अध्यक्ष एवं सदस्यों का

कार्यकाल पांच वर्ष या सत्तर वर्ष की आयु तक, जो पहले होगा, रखा गया है. अध्यक्ष का वेतन हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा सदस्यों का वेतन न्यायाधीश के बराबर होगा. लोकायुक्त की एक अन्वेषण तथा एक अभियोजन शाखा होगी. लोकायुक्त प्रशासनिक, वित्तीय तौर पर स्वायत्त रखा गया है. लोकायुक्त के समस्त व्यय राज्य की संचित निधि से दिए जाएंगे. लोकायुक्त के सचिव का चयन लोकायुक्त करेगा, जिसका स्तर प्रमुख सचिव के समकक्ष होगा. अन्य अधिकारियों की नियुक्ति स्थायी अथवा संविदा के आधार पर लोकायुक्त बोर्ड करेगा. मुख्यमंत्री, मंत्री तथा विधायकों के खिलाफ जांच तथा अभियोजन लोकायुक्त के सभी सदस्यों की अध्यक्ष के साथ पीठ की अनुमति के बिना नहीं होगा. लोकायुक्त के अध्यक्ष तथा सदस्य को किसी व्यक्ति की शिकायत पर उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद की गई संस्तुति के आधार पर पद से राज्यपाल हटा सकता है. लोकायुक्त अधिनियम के भविष्य को लेकर भी अभी से सवाल उठने लगे हैं. अधीनस्थ न्यायपालिका को दायरे में लेने के प्रावधान को अधिनियम के अस्तित्व के लिए चुनौती माना जा रहा है. भाजपा के समय में रचित यह अधिनियम पूरी तरह से बहुगुणा सरकार के गले की फांस तो बन ही गया है, इसने राज्य सरकार की मदमस्त चाल की कलई खोल कर रख दी है. सरकार के उच्च पदासीन अफसर किस तरह ला–परवाही से सरकार चला रहे हैं, यह प्रकरण एक बानगी प्रस्तुत कर गया है. पूरी कांग्रेस इस मामले में सकते में है. फिलहाल इस अधिनियम को लाख जनहितकारी होने के बावजूद ठंडे बस्ते में डालने की हर जुगत सरकार खोज रही है.

नए लोकायुक्त बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी से भले ही प्रदेश सरकार अंजान हो, शासन की ओर से 24 सितंबर को ही इसका नोटिफिकेशन भी कर दिया गया है. ऐसे में वर्तमान लोकायुक्त की वैधता को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं. अब इसे संवादहीनता कहें या नौकरशाहों की कार्यप्रणाली, पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी सरकार के लोकायुक्त बिल को लेकर राष्ट्रपति की मंजूरी से प्रदेश सरकार अब सवालों के घेरे में है. ऐसे में इसकी गाज किस पर गिरेगी कहा नहीं जा सकता. किसी न किसी अधिकारी का इस मामले में जाना तय है. इसके साथ ही नए लोकायुक्त कानून को लागू करने को लेकर अब विचार–विमर्श शुरू हो गया है. पूर्व भाजपा सरकार ने जन लोकपाल की तर्ज पर बनाए गए जिस लोकायुक्त बिल को राष्ट्रपति को भेजा था, इसे पिछले महीने यानि तीन सितंबर को ही राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी थी. सूत्रों के अनुसार राष्ट्रपति की ओर से इस बिल को नौ सितंबर को केंद्रीय गृह विभाग को भेज दिया गया था. केंद्रीय गृह विभाग की ओर से संस्तुति के साथ उत्तराखंड शासन को भेजा गया यह बिल 16 सितंबर को विधायी विभाग में प्राप्त किया गया है. केंद्र की ओर से भेजे गए नए लोकायुक्त बिल का प्रदेश के विधायी विभाग ने 24 सितंबर को नोटिफिकेशन कर इसे प्रदेश के 27वें अधिनियम के रूप में शामिल कर लिया था. नोटिफिकेशन में 180 दिन के अंदर इसे लागू करने को कहा गया है. इतना सब कुछ हुआ, प्रदेश के मुखिया से लेकर शासन के मुखिया तक को इसकी भनक तक नहीं लगी.

लोकायुक्त बिल पर मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने कहा कि यह गीता के ग्रंथ की तरह है, तो मोदी, धूमल और शिवराज चौहान समेत भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इसे क्यों नहीं लागू किया. उन्होंने कहा कि तत्कालीन भाजपा सरकार ने जो ड्राफ्ट राष्ट्रपति की मंजूरी को भेजा, इसमें कई खामियां हैं. लोकायुक्त बिल को संशोधन के बाद ही लागू किया जाएगा. यह राज्य का विशेषाधिकार है. इसमें राष्ट्रपति के अपमान जैसी कोई बात ही नहीं है. भाजपा इस पर ओछी राजनीति कर रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान में 118 बार संसोधन हो चुका है. इसका आशय यह नहीं लगाना चाहिए कि संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर का अपमान हो रहा है. कांग्रेस हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ रही है. कांग्रेस पूरे देश में एक ऐसा कानून चाहती है, जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम लग सके. तत्कालीन भाजपा सरकार ने जो ड्राफ्ट भेजा, इसे 2012 के चुनाव में जनता ने नकार भी दिया है.

कार्यक्रम में मौजूद कृषि मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत ने कहा कि भाजपा सरकार ने सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए आनन–फानन में कई खामियों के साथ इसे राष्ट्रपति की मंजूरी को भेज दिया. जब सदन के पटल पर इसे लाया गया था तब भी नेता प्रतिपक्ष के रूप में मैंने खुद इसका विरोध किया था. इसमें सबसे बड़ी कमी यह है कि जांच भी और फैसला देने का अधिकार भी लोकायुक्त को ही दिया गया है. ऐसा किसी भी तरह से न्यायोचित नहीं है. कांग्रेस पूरे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कानून बना रही है. ■

feedback@chauthiduniya.com

राष्ट्रभाषा के संरक्षकों का सम्मान

नवीन चौहान

भाषा का संबंध देश की उत्तपत्ति, विकास, संस्कृति और परंपरा से होता है. भाषा देश की अस्मिता होती है. हिंदी को राष्ट्रभाषा होने का गौरव प्राप्त है. जिस तरह समुद्र में न जाने कितनी छोटी बड़ी नदियां समा जाती हैं, उसी तरह हिंदी में भी न जाने कितनी बोलियों और भाषाओं के शब्द और संस्कार समाहित हो गए हैं. इसी वजह से तमाम बाधाओं के बावजूद समय के साथ हिंदी और ज्यादा परिपक्व और समृद्ध होती जा रही है. हिंदी की समृद्धि को उत्सव का रूप देने के लिए हर वर्ष संसद के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रभाषा उत्सव का आयोजन किया जाता है. जिसमें हिंदी की महत्ता को स्थापित करने और उसे बल देने में जुटे कलम के सिपाहियों, लेखकों, कवियों और पत्रकारों को उनके योगदान के लिए सराहा और पुरस्कृत किया जाता है.

हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी संसदीय हिंदी परिषद, परिचय साहित्य परिषद व विधि भारती परिषद द्वारा संसद के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रभाषा उत्सव का आयोजन किया गया. राष्ट्रभाषा उत्सव की अध्यक्षता पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रतिष्ठित साहित्यकार डॉ. श्याम सिंह शशि ने की. पूर्व केंद्रीय विधि मंत्री और संसदीय हिंदी परिषद की अध्यक्ष डॉ. सरोजिनी महिषी, प्रतिष्ठित साहित्यकार अर्चना वर्मा सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे. इस अवसर पर संप्रेषण के विभिन्न क्षेत्रों में अपना अमूल्य योगदान दे रही कुछ महत्वपूर्ण शख़्सियतों को राष्ट्रभाषा गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया. पत्रकारिता के क्षेत्र में हिंदी भाषा में राजनीतिक विषयों पर मौलिक लेख लिखने और राजनीति जैसे गूढ़ विषय को सामान्य जन तक आसान भाषा में पहुंचाने के लिए लिए चौथी दुनिया के प्रधान संपादक संतोष भारतीय को राष्ट्रभाषा गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया. इसी कड़ी में पत्रकारिता को संस्कृति से जोड़ने और हिंदी के विकास में अहम योगदान के लिए टीवी पत्रकार समीना अली को भी राष्ट्रभाषा गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया. जिस गति से कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के नए संसाधनों का विकास हुआ है, उसी गति से हिंदी की लोकप्रियता भी बढ़ी है. बदलती तकनीक के इस दौर में हिंदी को बचाए रखने की चुनौती दिखाई पड़ रही थी, वहीं तकनीक हिंदी के एक वैश्विक भाषा बनने की राह में सबसे बड़ा वरदान साबित हो रही है. अब

संसद के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रभाषा गौरव सम्मान ग्रहण करते हुए चौथी दुनिया के प्रधान संपादक संतोष भारतीय.

एक आम आदमी आसानी से कंप्यूटर, मोबाइल फोन आदि में अपने विचार हिंदी में प्रकट करता और बहस करता दिखाई देता है. इसमें उसे किसी तरह की कोई शर्म महसूस नहीं होती है. साहित्य व इंटरनेट पर योगदान आदि के लिए कवि शेरजंग गर्ग, डॉ. प्रवेश सक्सेना, डॉ. बालेन्दु शर्मा दाधीच तथा डॉ. शारदा वर्मा को राष्ट्रभाषा गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया. कार्यक्रम के दौरान विधि भारती परिषद की महासचिव संतोष खन्ना द्वारा संपादित त्रैमासिक पत्रिका महिला विधि भारती के 75वें अंक का लोकार्पण किया गया. साथ ही अन्य कई पुस्तकों, जिनमें परिचय साहित्य परिषद के अध्यक्ष उर्मिल सत्यभूषण की सृजन–समग्र, अनुरागेंद्र निगम का काव्य संग्रह अंतस, डॉ. ऊषा देवी का कहानी संग्रह बड़ा हुआ तो क्या हुआ, सुषमा भंडारी की मौन के स्वर और सूर्य प्रकाश सेमवाल द्वारा संपादित पत्रिका हिम उत्तरायणी के राजभाषा विशेषांक का लोकार्पण भी हुआ.

संसदीय हिंदी परिषद की स्थापना गोविंद बल्लभ पंत जैसे दिग्गजों के सानिध्य में की गई थी. संविधान में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया जा चुका था. संसद में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग के लिए यह ज़रूरी था कि जनप्रतिनिधि संसद सदस्य संसद में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करें. इसके लिए उन्हें हिंदी सिखाने के लिए संसदीय हिंदी परिषद की स्थापना की गई. आरंभ से ही सांसदों और आम जनता में हिंदी को लोकप्रिय बनाने के लिए संसद के केंद्रीय कक्ष में हिंदी दिवस मनाया जाने लगा.

संसदीय हिंदी परिषद की स्थापना गोविंद बल्लभ पंत जैसे दिग्गजों के सानिध्य में की गई थी. संविधान में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया जा चुका था. संसद में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग के लिए यह ज़रूरी था कि जनप्रतिनिधि संसद सदस्य संसद में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करें. इसके लिए उन्हें हिंदी सिखाने के लिए संसदीय हिंदी परिषद की स्थापना की गई.

कर्नाटक की हिंदी सेवी डॉ. सरोजनी महिषी 1962 में संसद में आईं तो उन्होंने हिंदी सिखाने का कार्यक्रम शुरू किया. 1972 तक वे संसद के केंद्रीय कक्ष में यह कार्यक्रम चलाती रहीं, पर बाद में यह काम लोकसभा सचिवालय ने अपने हाथ में ले लिया. उनका कहना था कि सेठ गोविंद दास ने तो हिंदी के विकास के लिए संसदीय हिंदी परिषद का गठन किया था.

गहन सोच के बाद यह तय किया गया कि संसद के केंद्रीय कक्ष, जहां से देश और दुनिया की बड़ी हस्तियां देश को संबोधित करती हैं, उस कक्ष में होने वाले इस समारोह को राष्ट्रभाषा उत्सव के रूप में मनाया जाए और देश की उन साहित्यकार विभूतियों को सम्मानित किया जाए, जो हिंदी की तन–मन से निरंतर सेवा कर उसे प्रगति के शिखरों तक ले जा रहे हैं. 12 सितंबर 2003 को पहली बार राष्ट्रभाषा गौरव सम्मान दिया गया. तब पुरस्कार पाने वालों में प्रभाकर श्रोत्रिय, दिनेश नंदिनी डालमिया, हिमांशु जोशी और राजकुमार सैनी जैसे साहित्यकार थे. अगले कुछ वर्षों में डॉ रमणिका गुप्ता, शांताबाई, डॉ. विश्वनाथ त्रिपाठी, डॉ. शाकुंतला कालरा, डॉ. परमानंद पंचाल, महीप सिंह, उर्मिल सत्यभूषण, डॉ. पूर्णचंद्र टंडन आदि को इस पुरस्कार से नवाजा गया. वर्ष 2011 में यह महसूस किया गया कि हिंदी को बढ़ावा देने में मीडियाकर्मी भी उल्लेखनीय भूमिका निभा रहे हैं. अतः उन्हें भी सम्मानित किया जाना चाहिए. 2011 में आयोजित किए गए राष्ट्रभाषा उत्सव में पहली बार पत्रकारों को राष्ट्रभाषा गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. ■

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

सांप्रदायिक ताक़तों के ख़िलाफ़ लड़ने की ज़रूरत है

बीते दिनों हमें मन्ना डे की मृत्यु का दुखद समाचार मिला. मन्ना डे 94 वर्ष के हो गए थे और पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे, लेकिन बेशक! वे उस पीढ़ी के आख़िरी गायकों में थे, जिन्होंने हिंदी फिल्म संगीत को इसकी पराकाष्ठा तक पहुंचाया. मोहम्मद रफी, किशोर कुमार और मुकेश का निधन कम उम्र में ही हो गया था. ये सभी साठ वर्ष से कम के ही थे. तलत महमूद भी हमारे बीच नहीं रहे. लेकिन मन्ना दा हमारे बीच थे और जिनके चलते हमें लगता था कि हम अभी भी उस दौर से जुड़े हुए हैं. लेकिन अजीब बात तो यह है कि मन्ना डे को जीवन भर कभी भी वह सम्मान नहीं मिला, जिसके वह हक़दार थे. मन्ना डे को लोकप्रियता मिली विमल राय की फिल्म *सीमा* से, जिसमें उन्होंने गाना गाया *तू प्यार का सागर है...* इसी गाने के बाद एस डी बर्मन और दूसरे संगीतकार उन्हें बुलाने लगे, जब उन्हें लगता कि रफी या मुकेश किसी गाने के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं. राजकपूर के ऊपर फिल्माए मशहूर गानों में से ज्यादातर को मुकेश ने गाया. लेकिन राजकपूर के ऊपर फिल्माए गए गानों को देखा जाए तो जो सबसे लोकप्रिय दृश्य सामने उभरकर आता है वह है, जिसमें राजकपूर और नरगिस हाथ में छाता लेकर गा रहे होते हैं, *प्यार हुआ इक़रार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है दिल.* यह गाना फिल्म श्री–420 का है और इसे मन्ना डे ने गाया है. ज्यादातर लोग समझते हैं कि यह गाना मुकेश ने गाया है क्योंकि मुकेश का नाम राजकूपर के साथ जुड़ चुका था. राजकपूर के ऊपर फिल्माया गया जो सबसे बेहतरीन गाना है वह फिल्म मेरा नाम जोकर से है और उस मशहूर जोकर गाने को मन्ना डे ने ही गाया है. बलराज साहनी ने फिल्मों में काफ़ी काम किया है, लेकिन जब भी उन्हें याद किया जाता है तो उनके ऊपर फिल्माए गए वक़्त फिल्म का गाना *वो मेरी जोहरा जबीं* की तस्वीर ज़रूर उभरकर सामने आती है.

हालांकि, इस गाने के आधार पर बलराज साहनी के व्यक्तित्व का आकलन नहीं किया जा सकता, लेकिन इस मशहूर गाने को आवाज़ मन्ना डे ने दी है. इसी तरह फिल्म दिल ही तो है का मशहूर गाना *लागा चुनरी में दाग.* मन्ना डे ने तकरीबन 500–600 गानों को आवाज़ दी और इनमें से ज्यादातर मशहूर हुए. लेकिन इसे दुर्भाग्य ही कहेंगे कि मन्ना डे को प्रेस और पब्लिक की तरफ से कभी भी वह स्नेह और सम्मान नहीं मिला जो किशोर कुमार, रफी और मुकेश को मिला. किशोर कुमार तो प्रशिक्षित गायक भी नहीं थे, जबकि मन्ना डे ने बाक़ायदा अपने चाचा के सी डे से संगीत की तालीम हासिल की थी. जब वे कलकत्ता से मुंबई आए तो ख़ुद में और भी सुधार किया और उस ऊंचाई तक पहुंचे, जहां आज वे थे. मन्ना डे ने भारतीय फिल्मों और फिल्म संगीत को समृद्ध बनाया. हम सबको उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि देनी चाहिए. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे.

देश के राजनीतिक माहौल की बात करें तो चुनावी बुखार अब लोगों को अपनी गिरफ़्त में ले रहा है और राहुल गांधी एकाएक आक्रामक मुद्रा में आ गए हैं. मुझे नहीं पता कि उनके भाषण कौन लिख रहा है या उनके सलाहकार कौन हैं. लेकिन इतना ज़रूर है कि इन सबके चलते राहुल गांधी अपना प्रभाव खो रहे हैं. अगर राहुल को सांप्रदायिकता से लड़ना है, अगर नरेंद्र मोदी का सामना करना है तो उनको महत्वपूर्ण क़िरदार निभाना पड़ेगा. ऐसा इसलिए क्योंकि पार्टी उन्हीं को अपने नेता के तौर पर पेश कर रही है. उन्हें अपने मौजूदा वयक्तित्व से आगे बढ़ते हुए और केंद्रित होना होगा. अचानक वे भावुक हो उठते हैं और कहते हैं कि मेरी दादी को मारा गया, मेरे पिता को मार डाला गया. संभव है कि मुझे भी मार दिया जाए, लेकिन मैं इसकी परवाह नहीं करता. अच्छी बात है. लेकिन यह सब बीजेपी ने तो किया नहीं. राहुल गांधी की दादी और पिता को बीजेपी ने तो मारा नहीं. इसलिए अगर बीजेपी पर प्रहार करना है, सांप्रदायिक ताकतों पर प्रहार करना है, तो आपको अपना ध्यान सही मुद्दों पर केंद्रित करना होगा.

वास्तव में श्रीमती इंदिरा गांधी की मौत की ज़िम्मेदार तो ख़ुद कांग्रेस ही है. कांग्रेस ने सिखों की अनदेखी की और इसका ख़ामियाज़ा उन्हें भुगतना पड़ा. इसमें बीजेपी का क्या दोष है. इसी तरह राजीव गांधी की हत्या के लिए श्रीलंका के लोग ज़िम्मेदार हैं. इसलिए अगर गांधी भावुक होते हैं तो उसमें कुछ ग़लत नहीं है, लेकिन जो उदाहरण वे देते हैं उनके माध्यम से वह नरेंद्र मोदी को आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएंगे. अगर राहुल वास्तव में नरेंद्र मोदी को रोकना चाहते हैं, तो उन्हें बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठाना होगा. इस प्रकरण के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने देश में व्याप्त धर्मनिरपेक्षता की रीढ़ ही तोड़ दी थी. भले ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया हो, भारतीय जनता पार्टी ने या विश्व हिंदू परिषद ने. 6 दिसंबर, 1992 को संघ परिवार ने भारत के सभ्य समाज और उसकी जीवन शैली में एक बंटवारा कर दिया था. मुझे नहीं समझ में आता कि इस मुद्दे को उठाने में कांग्रेस संकोच क्यों कर रही है. यूपी में तो राज्य के नौकरशाहों ने एक सर्कुलर तक निकलवा दिया था कि वहां पर मंदिर कैसे बनना है. संभवत: बीजेपी के नेताओं ने अपने कुछ ख़ास नौकरशाहों को सरकार में तैनात किया हुआ है.

अगर राहुल गांधी चीज़ों को गंभीरता से ले रहे हैं, तो उनको चाहिए कि पार्टी के दायित्व को और ज़िम्मेदारी के साथ संभालें. वह जो कर रहे हैं उससे ऊपर उठकर उन्हें जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के पूर्व में दिए गए भाषणों को और गंभीरता से समझना होगा. वह देश भर में घूम रहे हैं, मसलन राजस्थान, मध्य प्रदेश और अन्य जगहों पर. मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया की लोकप्रियता काफ़ी है. इसकी वजह स्थानीय लोगों का उनसे जुड़ाव भी हो सकता है. इसलिए राहुल गांधी का यहां का दौरा उनकी मदद करेगा. राज्य में बीजेपी को वे कैसे घेरते हैं, यह हम नहीं कह सकते. राजस्थान की बात करें तो यहां मुक़ाबला 50–50 का है. अगर कांग्रेस सही ढंग से चुनाव लड़ती है तो अभी भी अपनी उपस्थिति को बनाए रख सकती है, लेकिन टिकट के बंटवारे को लेकर असंतोष और दूसरे मुद्दे इसमें बाधा पैदा कर रहे हैं. मैं एक विधानसभा क्षेत्र के बारे में जानता हूं, क्योंकि मैं वहां से संपर्क में रहता हूं कि वहां पर पार्टी वर्तमान विधायक का टिकट काटकर दूसरे को टिकट देना चाहती है. नि:संदेह जीतने की अपनी एक कसौटी होती है, लेकिन अगर कांग्रेस अगर पुराने तरीकों से ऊपर उठकर नए–नए प्रयोग करेगी तो और मुश्किल में पड़ जाएगी.

राजनीतिक स्तर पर एक सही गतिविधि हुई है. कुछ गैर–कांग्रेसी और गैर–बीजेपी पार्टियों ने 30 दिसंबर को दिल्ली में एक मीटिंग करने का फ़ैसला किया है. सीपीएम, जनता दल यूनाइटेड, समाजवादी पार्टी और अन्ना डीएमके सहित अन्य पार्टियां सांप्रदायिक ताकतों का सामना करने के लिए इकट्ठा हो रही हैं. अगर ऐसा होता है तो यहां से तीसरे मोर्चे का बीज पड़ेगा. हालांकि, यह अभी दूर की कौड़ी है, लेकिन अगर सभी गैर–कांग्रेस और गैर–भाजपा पार्टियां मिलकर सांप्रदियक ताक़तों से लड़ने के लिए संगठित हो जाती हैं, तो मैं मानता हूं कि यह एक शुभ संकेत है. मैं इसकी सफलता की कामना करता हूं. ■

राहुल गांधी एकाएक आक्रामक मुद्रा में आ गए हैं. मुझे नहीं पता कि उनके भाषण कौन लिख रहा है या उनके सलाहकार कौन हैं. लेकिन इतना ज़रूर है कि इन सबके चलते राहुल अपना प्रभाव खो रहे हैं. अगर राहुल को सांप्रदायिकता से लड़ना है, अगर नरेंद्र मोदी का सामना करना है तो उन्हें महत्वपूर्ण क़िरदार निभाना पड़ेगा. ऐसा इसलिए क्योंकि पार्टी उन्हीं को अपने नेता के तौर पर पेश कर रही है. उन्हें अपने मौजूदा वयक्तित्व से आगे बढ़ते हुए और केंद्रित होना होगा.

feedback@chauthiduniya.com

सत्ता दमन और शोषण का साधन बन गई है

ठाकुर दास बंग

हमारा देश आज जिस विषम परिस्थिति से गुज़र रहा है, वह हर जागरूक नागरिक के लिए चिंता का विषय है.

देश की आज़ादी ने स्वाभाविक ही लोगों के मन में यह आशा जगाई थी कि अब ग़रीबी और शोषण समाप्त होंगे तथा देश प्रगति की राह पर आगे बढ़ेगा. इस आशा को संजोते और अच्छे दिनों की बाट देखते हुए पैंसठ बरस बीत रहे हैं.

मौजूदा परिस्थिति

इन वर्षों में कुछ भी नहीं हुआ, ऐसी बात नहीं है. देश के निर्माण और विकास के लिए कई योजनाएं हाथ में ली गईं और उनका कुछ परिणाम भी निकला, लेकिन इन योजनाओं और नीतियों की दिशा और प्राथमिकताएं ग़लत थीं. इसीलिए ग़रीबी, महंगाई, बेकारी, विषमता और शोषण दिनो–दिन बढ़ते गए. विकास के नाम पर अरबों रुपये ख़र्च हुए, पर उनका लाभ अधिकांशत: देश के चंद लोगों तक ही सीमित रह गया. उन्होंने अपने लिए सब प्रकार की सुख–सुविधाएं जुटा लीं, लेकिन आम जनता उनसे वंचित रह गई. सरकारी कामकाज में भारी अपव्यय तथा अधिकारियों और मंत्रियों के रहन–सहन की विलासिता में साधनों का भंयकर दुरुपयोग हुआ. सरकारी योजनाओं का रुख़, सदियों की तपस्या से समाज में प्रतिष्ठित परस्पर सहयोग और त्याग से अर्जित जीवन–मूल्यों के ख़िलाफ़ होने से देश का चारित्रिक और सांस्कृतिक पतन हुआ है. भ्रष्टाचार के कारण सारा जन–जीवन खोखला हो गया है तथा परस्पर अविश्वास, हिंसा और गुंडागर्दी ने सामान्य नागरिक का जीवन असुरक्षित और दूभर बना दिया है. उत्पादकों, अर्थात किसान, मज़दूर व दस्तकार को उनके उत्पादन के उचित लागत मूल्य और वाजिब पारिश्रमिक से वंचित रखा गया, जबकि कारखानेदारों और बिचौलियों को मनमाना मुनाफ़ा कमाने की छूट रही, जिससे गावों और नगरों के बीच विषमता की खाई दिनों–दिन बढ़ती गई. नौकरशाही और बुद्धिजीवी वर्ग भी इसमें पीछे नहीं रहे. क़ायदे–क़ानून, लाइसेंस, कोटा–परमिट आदि का जाल बिछाकर अनपढ़ ग़रीब तबके को उसमें जकड़ लिया गया. लोगों के सामने दो ही विकल्प रह गए–या तो वे इन क़ायदे–क़ानूनों का पालन करने में क़दम–क़दम पर कठिनाइयां भुगतें या फिर भ्रष्टाचार का सरल रास्ता पकड़ें. डर या लालच के इस दुष्चक्र में फंसी लाचार जनता में सत्ता के दुरुपयोग के ख़िलाफ़ बोलने की या उससे अपना बचाव करने की शक्ति प्राय: समाप्त हो गई. सत्ता के बाहर जो समाज सेवक या प्रबुद्ध नागरिक थे, वे भी आज की परिस्थिति के लिए कम ज़िम्मेदार नहीं हैं, क्योंकि इस ग़लत प्रवाह को रोकने के लिए उन्होंने भी कोई परिणामदायी क़दम नहीं उठाए.

आज़ादी के बाद जनता की शक्ति और उसके अभिक्रम का दायरा बढ़ना चाहिए था, पर बजाय इसके धीरे-धीरे अधिकांश जन-जीवन सरकार के नियंत्रण में चला गया है. लोगों ने भी मान लिया कि स्वराज्य मिल जाने के बाद उन्हें अब कुछ नहीं करना है. सब कुछ सरकार ही करेगी. लोकतंत्र में जनता मालिक मानी जाती है, पर आज उसकी हैसियत भिखारी सी हो गई है. आज जो संकट खड़ा हुआ है, उसके मूल में इस प्रकार एक ओर भ्रष्ट व्यवस्था और दूसरी ओर परावलम्बी जनता है.

सत्ता का चरित्र और जनता की हैसियत

सामान्यत: सत्ता जनता की समस्याओं को हल करने की बजाय उसके शोषण और दमन का साधन बन गई है. विदेशी शासन के समय साम्राज्यवादियों द्वारा खड़ी की गई प्रशासन, न्याय, पुलिस, जेल आदि की व्यवस्थाएं आज़ाद और जनतंत्रीय भारत में भी न केवल ज्यों की त्यों क़ायम हैं, बल्कि और अधिक मज़बूत बना दी गई हैं. आर्थिक क्षेत्र में देश की आम जनता का शोषण राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय संस्थानों द्वारा लगातार बढ़ता जा रहा है. शिक्षण की पद्धति, भाषा संबधी नीति और सांस्कृतिक मूल्य भी इस शोषणकारी व्यवस्था के अनुरूप ढाले जा रहे हैं. शोषण की इस प्रक्रिया को बढ़ाने और अपना वर्चस्व स्थापित करने की आकांक्षा ने आणविक अस्त्रों के होड़ को जन्म देकर संसार को सर्वनाश के कगार पर पहुंचा दिया है.

हाल के वर्षों में सत्ता का एक नया चरित्र प्रकट हुआ है. उसकी कोशिश यह है कि आज के लोकतंत्र में जनता को जो भी थोड़े अधिकार प्राप्त हैं, उन्हें सीमित या समाप्त कर दिया जाय. न्यायपालिका, प्रेस आदि की स्वतंत्रता के लिए नये–नये ख़तरे सामने आ रहे हैं. विधानसभाएं व संसद केवल दलगत शक्ति परीक्षण के अखाड़े या खरीद–बिक्री के बाज़ार बनते जा रहे हैं और चुनाव लाठी, रुपया, जाति तथा खोखले नारों का खेल.

सामान्य जनतांत्रिक प्रक्रिया जब इस प्रकार प्रभावहीन हुई हो तो राजनीतिक दलों के अप्रासंगिक हो जाने में आश्चर्य क्या? दलों का बिखराव और उनमें फैल रही एकाधिकारशाही इसी के परिणाम हैं.

आज़ादी के बाद जनता की शक्ति और उसके अभिक्रम का दायरा बढ़ना चाहिए था, पर बजाय इसके धीरे–धीरे अधिकांश जन–जीवन सरकार के नियंत्रण में चला गया है. लोगों ने भी मान लिया कि स्वराज्य मिल जाने के बाद उन्हें अब कुछ नहीं करना है. सब कुछ सरकार ही करेगी. लोकतंत्र में जनता मालिक मानी जाती है, पर आज उसकी हैसियत भिखारी सी हो गई है. आज जो संकट खड़ा हुआ है, उसके मूल में इस प्रकार एक ओर भ्रष्ट व्यवस्था और दूसरी ओर परावलम्बी जनता है.■

भ्रष्टाचार के कारण सारा जन-जीवन खोखला हो गया है तथा परस्पर अविश्वास, हिंसा और गुंडागर्दी ने सामान्य नागरिक का जीवन असुरक्षित और दूभर बना दिया है. उत्पादकों, अर्थात किसान, मज़दूर व दस्तकार को उनके उत्पादन के उचित लागत मूल्य और वाजिब पारिश्रमिक से वंचित रखा गया, जबकि कारखानेदारों और बिचौलियों को मनमाना मुनाफ़ा कमाने की छूट रही, जिससे गावों और नगरों के बीच विषमता की खाई दिनों-दिन बढ़ती गई. नौकरशाही और बुद्धिजीवी वर्ग भी इसमें पीछे नहीं रहे.

feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

राहुल का इमोशनल अत्याचार

राहुल गांधी के दिए गए भाषणों से लगता है कि अब उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, जिसे लेकर वह लोगों के पास जाएं. इसीलिए राहुल गांधी अपने मध्य प्रदेश और राजस्थान के दोनों भाषणों में इमोशनल ड्रामा किया. राहुल गांधी को समझना चाहिए कि झुठे वादों और इमोशनल बातों से कुछ नहीं होगा. उन्होंने पहले मध्य प्रदेश में अपने भाषण में मां का सहारा लेकर इमोशनल ड्रामा किया. राजस्थान में उन्होंने पहले लोगों को बताया कि मां ने कहा है कि अपने बारे में लोगों को बताओ, मेरे बारे में नहीं. राहुल ने अपने बारे में बताने के बजाय दादी और पापा के हत्या के बारे में लोगों को बताकर इमोशनल ड्रामा किया. राहुल गांधी क्या नरेंद्र मोदी से इतने घबरा गए हैं कि वह विकास और महंगाई, भ्रष्टाचार, रोजगार, अर्थव्यवस्था पर बात नहीं करते, जिससे उन्हें इमोशनल ड्रामा करना पड़ रहा है. कांग्रेस और यूपीए के प्रति, जिसे लेकर लोगों में गुस्सा है, उसके बारे में राहुल गांधी लोगों से क्यों नहीं बात करते हैं. राहुल गांधी खाद्य सुरक्षा पर भी खूब बात करतें हैं और सांप्रदायिकता पर भी प्रवचन करते हैं. राहुल गांधी एक गरीब को खाना, घर, कपड़ा, रोजगार भी चाहिए. राहुल जिस खाद्य सुरक्षा के तहत मिलने वाले अनाज की बात कर रहे हैं, क्या उससे गरीब का पेट भर जाएगा? सही मायने में देखा जाए तो राहुल को वास्तविक भारत की तस्वीर के बारे में पता ही नहीं है. वे भले ही दूसरी पार्टियों पर आरोप लगाते हैं कि उन पार्टियों के नेता एसी कमरे में बैठकर राजनीति करते हैं, लेकिन राहुल पूरे 10 साल कहां बैठकर राजनीति किए. क्या यह सही नहीं है कि जब-जब चुनाव आता है, राहुल को जनता की याद आती है. यह जनता के साथ राहुल का इमोशनल अत्याचार है, जिसे उन्हें बंद कर देना चाहिए.

मज़बूत होती भाजपा

चुनाव में सर्वे करने वाले उस पक्षी की तरह हो जाते हैं, जो आसमान से अपने शिकार पर निगाहें लगाए रहता है, जिससे राजनीतिक पार्टियों को अपना शिकार बना सकें और इसलिए एक सर्वे के बाद सभी सर्वे करने वालों के आकड़े आने लगते हैं कि राज्य और केंद्र में किसकी सरकार बनेगी. इस बार आए सभी सर्वे से यह जरूर पता चल रहा है कि केंद्र में किसी एक पार्टी की सरकार नहीं बन रही है और भाजपा हो या कांग्रेस, इन दोनों पार्टियों को सरकार बनाने के लिए क्षेत्रीय पार्टियों की जरूरत पड़ेगी. राज्यों की बात करें तो मिजोरम को छोड़कर छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, राजस्थान में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलता दिख रहा है और दिल्ली में भी भाजपा सबसे बड़ी पार्टी होगी. 2014 लोकसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच ही लड़ाई होगी. यह बात साफ है कि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी होगी और कांग्रेस दूसरी बड़ी पार्टी होगी. तीसरे मोर्चे की बात करें तो वह चुनाव बाद ही साथ आएंगे, क्योंकि उनका मुकाबला पहले राज्यों में एक-दूसरे से है. यह बात साफ हो गई है कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के उभरने और उन्हें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाए जाने से भाजपा की स्थिति मजबूत हुई है.

प्याज को लगा पंख

प्याज के कारण ही एक बार दिल्ली की सरकार गिर चुकी है. इस बार फिर प्याज की कीमत आसमान छू रही है. यह दिल्ली में विपक्ष के लिए एक हथियार है, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को घायल कर रहा है. पूरे देश में बढ़ती प्याज की कीमतों को कोसने और प्याज का दाम कम कब होगा, इसके सिवाय कुछ नहीं कर सकते. प्याज में आई तेजी का कारण जमाखोरी और प्राकृतिक आपदा है, जिसके कारण प्याज की आवक कम हुई है, लेकिन इसके लिए सरकार भी जिम्मेदार है. सरकार यदि पहले ही इस पर काबू कर ली होती और निर्यात पर रोक लगाती तो प्याज की कीमत इतनी नहीं बढ़ती. कृषि मंत्री शरद पवार इसके लिए कम जिम्मेदार नहीं है. पहले महाराष्ट्र किसान फायदे के लिए प्याज को निर्यात करने का बयान देते हैं और अब कह रहे हैं कि प्याज की कीमत जल्द ही कम हो जाएगी. ऐसे बयानों से ही जमाखोर प्रोत्साहित होते हैं, जिससे वह प्याज की जमाखोरी करते हैं. सरकार अब प्याज आयात करेगी. कोई जरूरी नहीं कि प्याज की कीमत कम हो जाए. अब देखना होगा कि प्याज की कीमत का असर चुनावों पर दिखता है या नहीं.

कड़ी कार्रवाई की ज़रूरत

पाकिस्तान सीमा पर लगातार फायरिंग कर रहा है और ऐसा कर के वह लगातार संघर्ष विराम का उल्लघंन कर रहा है. विडंबना देखिए कि भारत सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम उठाने की बजाय बयान दिए जा रहे हैं. गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने अपने जम्मू-कश्मीर के दौरे पर यह जरूर कहा है कि पाकिस्तान को हर एक गोली का जबाब दिया जाना चाहिए. केवल कड़ी प्रतिक्रया से माहौल सुधरने वाला नहीं है. अब भारत को पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जरूरत है. पाकिस्तान से सारे रिश्ते तोड़ने होंगे, क्योंकि पाकिस्तान बात को तव्वजो नहीं दे रहा है. अभी हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की मुलाकात भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से न्यूयॉर्क में हुई थी, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान घुसपैठ कराने के लिए सीमाओं पर बार-बार गोलीबारी कर रहा है. सरकार के लचीले रुख के कारण ही पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है. अब पाकिस्तान को मुहतोड़ जवाब देने का समय आ गया है. सरकार को पाकिस्तान के रुख को समझना चाहिए. ■

पाठक पूरा नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने स्वतंत्र विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें :

चौथी दुनिया, एफ.2, सेक्टर-11, नोएडा (उत्तर प्रदेश) पिन-201301

ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

राहुल गांधी और बुद्धिमत्ता में अभी फ़ासला बाक़ी है

नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी, दो व्यक्तित्व हैं, जिनके बारे में प्रचार हो रहा है कि इन दोनों में से कोई एक प्रधानमंत्री बनेगा. नरेंद्र मोदी की पार्टी छह महीने पहले तक महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोज़गारी जैसे सवाल गाहे–बगाहे उठाती रहती थी. कभी–कभी महंगाई को लेकर इन्होंने प्रदर्शन भी किया, लेकिन अचानक ये सवाल भाजपा ने उठाने बंद कर दिए. कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता, इनफाइटिंग के आरोप लगाती रहती थी, पर उसने भी ये आरोप लगाने बंद कर दिए. दोनों पार्टियों में एक छुपा हुआ समझौता हो गया. समझौते के पीछे की वजह सिर्फ़ एक थी कि इन समस्याओं के बढ़ने में दोनों ही पार्टियों की थोड़ी और ज़्यादा भूमिका रही है. इसलिए शायद दोनों पार्टियों ने तय किया कि हम मुद्दों को लेकर एक–दूसरे पर हमला ही न करें. हम दोनों व्यक्तित्वों को आमने–सामने लेकर आएं. भारतीय जनता पार्टी को इसमें फ़ायदा दिखा कि कांग्रेस के द्वारा फैलाए हुए ख़राब शासन को मुद्दा बनाकर आसानी से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनवाया जा सकता है और कांग्रेस को लगा कि राहुल गांधी की उम्र को मुद्दा बनाकर नौजवानों को अपने साथ लिया जा सकता है और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है. राहुल गांधी ने बयान भी दिया कि नई सरकार नौजवानों की होगी. कांग्रेस के जितने भी बुजुर्ग नेता हैं और बुजुर्ग से मेरा मतलब है पचास साल से ऊपर के लोग हैं, उन्हें लग रहा है कि उनकी भूमिका राजनीति में समाप्त करने की तैयारी कर ली गई है. शायद लोकसभा के इस चुनाव में 70 प्रतिशत से ज़्यादा सीटें 24 से लेकर 40 वर्ष की उम्र के लोगों को मिलेंगी. दोनों ही दल सत्ता पाने के सपने में खोए हुए हैं.

राहुल गांधी सारे देश में घूम रहे हैं, पर एक अजीब संयोग है कि राहुल गांधी की कहीं पर भी बड़ी सभा नहीं हो रही है. उत्तर प्रदेश में एक जगह उनकी सभा में एक सौ सत्तर लोग आए दूसरी सभा में ढाई हज़ार. उसके बाद जहां–जहां भी वो गए, वहां–वहां उन्हें दस हज़ार से बड़ी भीड़ कहीं मिली नहीं. क्या राहुल गांधी को कांग्रेस के ख़राब शासन का ख़ामियाज़ा भुगतना पड़ रहा है या फिर राहुल गांधी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भाषा या वो शैली लोगों में उनके प्रति विश्वास नहीं जगा पा रही है? राहुल गांधी ने अपनी दादी की, अपने पिता की हत्या को चुनाव का मुद्दा बनाया. शायद राहुल गांधी के इन्हीं बचकाने बयानों से उनके गंभीर चुनौती के रूप में खड़े होने में दिक्कत पेश आ रही है. नरेंद्र मोदी को महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोज़गारी के हटने से कोई मतलब नहीं है, पर नरेंद्र मोदी में ये कला है कि वो इन सवालों को कांग्रेस के ख़िलाफ़ भाजपा के हित में प्रचार का हथियार बना रहे हैं. दूसरी तरफ़ राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ कोई भी ऐसी बात नहीं कह पा रहे हैं, जिस बात से उनके परिपक्व होने की, या उनमें राजनीतिक कुशलता का अभाव नहीं है, ये पता चल सके.

कांग्रेस पार्टी पूरी तौर पर राहुल गांधी पर निर्भर है. राहुल के सामने एक मानसिक समस्या भी है. उनके बारे में कई तरह की अफ़वाहें देश के लोगों के मन में बस गई हैं. उन अफ़वाहों को लोग सच मान रहे हैं. जैसे रात आठ बजे के बाद राहुल गांधी क्या करते हैं, किससे मिलते हैं. माना ये जाता है कि राजनीतिक दलों के लोग शाम तक कार्यकर्ताओं से मिलते हैं और शाम के बाद राजनीतिक मंत्रणाएं करते हैं और रणनीति बनाते हैं, लेकिन राहुल गांधी के साथ किसी ने शाम आठ बजे के बाद मीटिंग होते देखी नहीं, लोगों से उन्हें मिलते देखा नहीं और ऐसी स्थिति में वही हो रहा है, जो होना चाहिए. भिन्न–भिन्न किस्म की अफ़वाहें राहुल गांधी को लेकर फ़ैल रही हैं.

वहीं, दूसरी तरफ़ उनकी बहन प्रियंका गांधी को लेकर देश के लोगों में अभी भी एक उत्सुकता है. प्रियंका गांधी की राजनीतिक समझ उसी तरह लोगों के सामने नहीं आई, जिस तरह राहुल गांधी की नहीं आई है, लेकिन प्रियंका गांधी की मुट्ठी बंद है. प्रियंका गांधी को लेकर कांग्रेस के लोगों में आशा दिखाई देती है और उन्हें लगता है कि प्रियंका गांधी अगर चुनाव प्रचार में आईं और लोकसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा तो वे देश में बहुत सारी सीटों पर अपना असर डाल पाएंगी. पिछले बीस सालों से हिंदुस्तान के लोगों के मन में ये बात बिठाई जा रही है कि प्रियंका गांधी की सारी अदाएं, प्रियंका गांधी की भाव–भंगिमा, उनकी शैली, यहां तक कि उनका चेहरा, उनके बाल उनकी दादी इंदिरा गांधी से मिलते हैं. और पता नहीं क्यों लोग प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी की छवि देखना चाहते हैं. इसीलिए जब–जब प्रियंका गांधी को लेकर कोई ख़बर फ़ैलती है, कांग्रेस के लोगों के चेहरे पर ख़ुशी की लहर दौड़ जाती है.

सोनिया गांधी भले ही इटली में पैदा हुई हों, लेकिन उनका मन भारतीय मां का मन है. वो बेटे को बेटी से ज़्यादा पसंद करती हैं. बेटी उनकी सहेली हो सकती है, लेकिन उनका राजनीतिक वारिस बेटा ही होगा, ऐसा सोनिया गांधी ने कई बार संकेतों-संकेतों में बता दिया है. इसीलिए वो अपने बेटे की किसी भी ऐसी हरकत को बुरा नहीं मानती हैं, जो हरकत उन पर या उनकी समझ पर सवाल खड़ा करती हैं. ऐसी ही एक घटना सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को बदलने के लिए अध्यादेश लाते वक़्त हुई. ये अध्यादेश सोनिया गांधी से बातचीत के बाद कैबिनेट ने पास किया, उसे राज्यसभा ने इंट्रोड्यूस किया, लेकिन राष्ट्रपति के पास जब अध्यादेश भेजा गया, तो अचानक राहुल गांधी ने कहा कि ये नॉनसेंस अध्यादेश है, इसे फाड़कर फेंक देना चाहिए.

यह भी सत्य है कि सोनिया गांधी भले ही इटली में पैदा हुई हों, लेकिन उनका मन भारतीय मां का मन है. वो बेटे को बेटी से ज़्यादा पसंद करती हैं. बेटी उनकी सहेली हो सकती है, लेकिन उनका राजनीतिक वारिस बेटा ही होगा, ऐसा सोनिया गांधी ने कई बार संकेतों–संकेतों में बता दिया है. इसीलिए वो अपने बेटे की किसी भी ऐसी हरकत को बुरा नहीं मानती हैं, जो हरकत उन पर या उनकी समझ पर सवाल खड़ा करती हैं. ऐसी ही एक घटना सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को बदलने के लिए अध्यादेश लाते वक़्त हुई. ये अध्यादेश सोनिया गांधी से बातचीत के बाद कैबिनेट ने पास किया, उसे राज्यसभा ने इंट्रोड्यूस किया, लेकिन राष्ट्रपति के पास जब अध्यादेश भेजा गया, तो अचानक राहुल गांधी ने कहा कि ये नॉनसेंस अध्यादेश है, इसे फाड़कर फेंक देना चाहिए. कोई नहीं मानता कि सोनिया गांधी ने इसकी चर्चा राहुल गांधी से नहीं की होगी, क्योंकि सोनिया गांधी, राहुल गांधी को अपनी जगह पार्टी चलाने के लिए मानसिक और शारीरिक तौर पर तैयार कर रही हैं. उन्होंने ज़रूर बात की होगी. तब फिर अपनी मां के द्वारा किए गए फ़ैसले के विरोध में राहुल गांधी क्यों खड़े हो गए? राहुल गांधी इसका और बेहतर विरोध कर सकते थे. इसे लाने ही नहीं देते, पर उनके सलाहकारों ने उन्हें इसके लिए तैयार किया और उन्होंने इसका एक नाटकीय माहौल रचा.

राहुल गांधी के सलाहकारों में समझदार लोग हैं. मोहन प्रकाश उनमें सर्वाधिक समझदार हैं, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रहे और डॉक्टर लोहिया के विचारों में उनकी आस्था है. मोहन प्रकाश कितना भी पूंजीपतियों के नज़दीक रहें, अधिकारियों के नज़दीक रहें, लेकिन मोहन प्रकाश बुनियादी तौर पर समाजवादी हैं और मोहन प्रकाश की सोच में ग़रीब है. राहुल गांधी जब–जब ग़रीबों की बात करते हैं या सामान्य जन की बात करते हैं तो मुझे मोहन प्रकाश का चेहरा याद आ जाता है कि इन लाइनों को या इस विषय को राहुल गांधी के दिमाग़ में भरने का काम अवश्य उन्होंने किया होगा. पर इसके बावजूद क्यों राहुल गांधी कि ज़ुबान लड़खड़ा जाती है? क्यों राहुल गांधी अपरिपक्व बयान दे देते हैं? राहुल गांधी को भाषण देते समय एंग्री यंग मैन की जगह इस देश के सामान्य जन को समझ में आने वाली भाषा बोलनी चाहिए. राहुल गांधी के दिमाग़ में किसने भर दिया कि देश को अपने साथ लाने के लिए दीवार के अमिताभ बच्चन की छवि ज़रूरी है? ये बात कभी राहुल गांधी को जावेद अख़्तर ने ज़रूर समझाई थी, लेकिन राहुल गांधी में अपनी समझ अगर हो, या मोहन प्रकाश की समझ को वो ज़रा आत्मसात करें तो वो इस देश के नेता की भाषा बोल सकते हैं, बजाय अपरिपक्व राजनीतिक शैली के.

राहुल गांधी के बयान, राहुल गांधी की शैली, राहुल गांधी की भाषा और राहुल गांधी का एपीयरेंस, ये सब इस देश के होने वाले प्रधानमंत्री को परिलक्षित नहीं करते. और यहीं पर मोहन प्रकाश जैसे लोगों का फ़र्ज़ है कि वो राहुल गांधी को थोड़ा गढ़ें, राहुल गांधी को थोड़ा पॉलिश करें और राहुल गांधी को इस देश की बुनियादी समस्याओं के बारे में बताएं, ताकि वो नरेंद्र मोदी का सामना एक बुद्धिजीवी के तौर पर कर सकें. अगर वो ये नहीं करेंगे तो लोगों में ये विश्वास और ज़ोर पकड़ेगा कि बुद्धिमत्ता और राहुल गांधी में अभी फ़ासला बाक़ी है.■

editor@chauthiduniya.com

मेघनाद देसाई

मुस्लिमों के सवाल

ईद मुबारक. भारतीय नेता अक्सर यह मुबारकबाद क्यों दिखावटी तरीक़े से देते हैं. आख़िर इसी तरीक़े से वे दीपावली, दशहरा और क्रिसमस की बधाई क्यों नहीं देते हैं? क्यों वे इफ्तार पार्टियों में जाना पंसद करते हैं, लेकिन क्रिसमस पर होने वाले कार्यक्रमों में वे शरीक नहीं होते.क्या भारतीय मुसलमान नेताओं के इन तरीक़ों से मूर्ख बन जाते हैं या इन बनावटी तरीक़ों से अब वे आजिज़ आ चुके हैं.

आगामी लोकसभा चुनाव कई मामलों में ऐतिहासिक होने जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि भारत में मुसलमान होने के मायने क्या हैं? जब से भाजपा ने नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है, कांग्रेस व अन्य धर्मनिरपेक्ष पार्टियों का यह अनुमान है कि वे गुजरात दंगों का डर दिखाकर मुस्लिम मतों का ध्रुवीकरण अपनी तरफ़ कर लेंगी. कांग्रेस व अन्य धर्मनिपेरक्ष पार्टियों के लिए धर्मनिरपेक्षता का सिर्फ़ एक मतलब है, मुस्लिम वोट को किसी भी तरह हथियाना.

विभाजन की त्रासदी के बाद भारत में मुसलमानों के साथ दूसरे समुदायों से भिन्न व्यवहार किया जाता रहा है. यहां तक कि जो वास्तविक धर्मनिरपेक्ष नेता हैं, वे उन्हें मुसलमान कहने तक से बचते हैं. वे उन्हें अल्पसंख्यक कहते हैं, लेकिन क्या भारत में दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय नहीं हैं? क्या मुस्लिम, भारत के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय हैं या वे भारत के दूसरे बड़े बहुसंख्यक हैं (जैसा की हाल ही में जावेद जमील ने अपने लेख में लिखा है). क्या मुस्लिमों को अल्पसंख्यक का दर्जा उनकी नागरिकता को एक पद ऊपर उठाता है? क्या वे एकमात्र अल्पसंख्यक समुदाय हैं, जो इस दर्जे का आनंद (या कष्ट) उठाते हैं.

विभाजन कांग्रेस द्वारा भारत को लेकर देखे गए सपने पर एक गहरा धक्का था, फिर भी कांग्रेस के नेता विभाजन के लिए तैयार हो गए थे. उन्होंने मुहम्मद अली जिन्ना का विरोध नहीं किया. इस बात के काफ़ी सबूत हैं कि कांग्रेसी नेता अप्रैल 1947 तक मुस्लिम लीग से छुटकारा पाने के लिए काफ़ी अधीर हो उठे थे. सही मायने में देखा जाए तो वे मुस्लिम लीग के साथ सत्ता का बंटवारा नहीं करना चाहते थे. ऐसा कहा जाता है कि बंटवारे में सिर्फ जिन्ना विश्वास करते थे, कांग्रेस नहीं. बंटवारे को कांग्रेस ने सीधे तौर पर तो स्वीकार नहीं किया. हालांकि उसे दगाबाज़ अंग्रेज़ों की वजह से स्वीकार करना पड़ा था.

बंटवारे का विरोध नहीं करने पर पार्टी में एक अपराधबोध पैदा हुआ, जिसका परिणम एक अहंकार भरे अनुमान के रूप में सामने आया कि भारत में कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है, जो मुस्लिमों का कल्याण कर सकती है, जिसकी वजह से मुस्लिमों को हमेशा मूल नागरिकता मिलने में मुश्किलें होती रहीं. ऐसा माना गया कि उन्हें हमेशा एक विशेष व्यवहार की ज़रूरत है, लेकिन अब 66 सालों के विलंब के बाद समय आ गया है कि इस विषय पर खुली बहस की जाए कि आख़िर भारत में एक मुसलमान होने के मायने क्या हैं? अठारह करोड़ की आबादी वाले इस समुदाय को विशेष बर्ताव की कोई ज़रूरत नहीं है. इन्हें भारत के किसी भी अन्य समुदाय के नागरिक की तरह ही माना जाना चाहिए.

विभाजन कांग्रेस द्वारा भारत को लेकर देखे गए सपने पर एक गहरा धक्का था, फिर भी कांग्रेस के नेता विभाजन के लिए तैयार हो गए थे. उन्होंने मुहम्मद अली जिन्ना का विरोध नहीं किया. इस बात के काफी सबूत हैं कि कांग्रेसी नेता अप्रैल 1947 तक मुस्लिम लीग से छुटकारा पाने के लिए काफी अधीर हो उठे थे.

पिछले दिनों मुस्लिम समुदाय के बीच में चर्चा ज़ोरों पर थी. वो यह कि समुदाय के बड़े नेता महमूद मदनी ने कहा कि धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हिंदुत्व का भय दिखाकर मुसलमानों को उनके मूलभूत अधिकारों से वंचित कर रही हैं. ये पार्टियां मुस्लिम वोटरों से कहती हैं कि समुदाय के पास उन्हें वोट देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, लेकिन इन धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को वोट देने के बावजूद मुस्लिम समुदाय सामाजिक और आर्थिक सूचकांक में कहीं भी नहीं ठहरता.

अगर हमारे पास धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत की बजाय समान नागरिकता होती तो हमें मंडल कमीशन का सामना नहीं करना पड़ता, जो पूरी तरह हिंदू आरक्षण एजेंडे पर आधारित था और अन्य सभी समुदायों को इससे वंचित रखता है. अगर कोई सकारात्मक क़दम उठाना है तो यह आर्थिक और सामाजिक आधार पर होना चाहिए. आख़िर मंडल कमीशन ने पिछड़ों और कमज़ोरों को आरक्षण देने के लिए हिंदू रुख़ क्यों अपनाया? और अगर उन्होंने ऐसा किया भी तो उनके बाद की सरकारों ने संविधान के मूलभूत अधिकारों का हनन करते हुए इसे जारी क्यों रखा?

एक बार अगर आपने धर्मनिरपेक्षता को बुरी तरह छोड़ दिया तो आपको दोबारा मुस्लिम दलितों और इसाई दलितों को परिभाषित करना होगा. मुस्लिमों पर एक नये तरह की बहस छेड़कर मंडल कमीशन के बकवास को बंद कर एक ऐसा तरीक़ा ईजाद करना होगा, जिससे सभी समुदायों के पिछड़ों को लाभ पहुंचाया जा सके. यही अंतिम समावेश होगा.

और अंतिम में, यह कहना की भाजपा की सरकार में मुस्लिम परेशानी में पड़ जाएंगे, यह भारत के पिछले 66 वर्षों के लोकतांत्रिक इतिहास की तरफ़ भी इशारा करता है. यह एक कमज़ोर दलील है कि एक ही पार्टी हमेशा सत्ता में बने रहना चाहिए. क्या ऐसा नहीं है कि बीते वर्षों में एक ही पार्टी ने उन्हें कमज़ोर और पिछड़ा बनाए रखा है.■

feedback@chauthiduniya.com

अगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो बीमार

चौथी दुनिया ब्यूरो

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का महत्व किसी बड़े अस्पताल से कम नहीं होता, क्योंकि यही वह केंद्र है, जहां बच्चों के टीकाकरण और गर्भवती महिलाओं के समुचित इलाज की व्यवस्था करने की ज़िम्मेदारी सरकार की होती है. यही वह केंद्र है, जहां देश के नौनिहालों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं. भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा की हालत क्या है, यह किसी से छिपा नहीं है. कुछ राज्यों में स्थिति अच्छी है, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की हालत ख़ुद एक मरीज की तरह है. ऐसे में आप सभी से कुछ सवालों का जवाब जानना ज़रूरी है. जैसे, क्या आपकी पंचायत या वार्ड में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है? अगर हां, तो उसकी हालत क्या है? क्या वहां नर्स, डॉक्टर एवं कंपाउंडर नियमित रूप से आते हैं, दवाएं मिलती हैं, जांच की सुविधा है? अगर इनमें से कोई भी एक सुविधा आपको नहीं मिलती है तो आप क्या करते हैं, शिक़ायत या कुछ और? चौथी दुनिया के सूचना अधिकार अभियान के तहत इस अंक में हम आपको यही बता रहे हैं कि आप कैसे उपरोक्त सुविधाएं पा सकते हैं, वह भी बड़ी आसानी से. इसके लिए आपको बस एक आवेदन तैयार करना है और कुछ सवाल पूछने हैं. सवाल क्या होंगे, यह हम आपको बता रहे हैं. फ़िलहाल इस अंक में हम आपको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर नियुक्त नर्स (एएनएम) के बारे में बता रहे हैं. अगर आपके केंद्र पर नियुक्त एएनएम नियमित रूप से नहीं आती या देर से आती है या टीकाकरण अथवा दवा वितरण का काम सही समय और सही ढंग से नहीं होता है तो आप इस अंक में प्रकाशित आवेदन पत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं. तय मानिए, सिर्फ़ एक आवेदन करने से आपके केंद्र की हालत सुधर जाएगी. नर्स सही समय पर नियमित रूप से आएगी, टीकाकरण एवं दवा वितरण का काम सुधर जाएगा. आपको अपने आवेदन में एएनएम से संबंधित उपस्थिति रजिस्टर की प्रति मांगनी है. उनकी छुट्टियों के बारे में पूछना है. टीकाकरण से लाभांवित होने वाले बच्चों की सूची मांगनी है. ज़ाहिर है, जब आप इतने सारे सवाल पूछेंगे तो किसी भी सरकारी विभाग के लिए जवाब दे पाना मुश्किल हो जाएगा. किसी पचड़े में फंसने के बजाय वह स्थिति सुधारने पर ज़्यादा ध्यान देगा. हम उम्मीद करते हैं कि आप इस

आवेदन का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे. साथ ही अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करेंगे, क्योंकि यह एक अभियान है कुव्यवस्था और भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ और इसमें आपकी भागीदारी ज़रूरी है. ■

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं, तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ई-मेल कर सकते हैं या पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है :

चौथी दुनिया

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश, पिन -201301 ई-मेल : rti@chauthiduniya.com

आवेदन का प्रारूप

(एएनएम के संबंध में)

सेवा में,
लोक सूचना अधिकारी
(विभाग का नाम)
(विभाग का पता)

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन

महोदय,

.....ग्राम पंचायत में कार्यरत एएनएम के संबंध में निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध कराएं:

1. इस ग्राम पंचायत में कार्यरत एएनएम के संबंध में निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध कराएं:

क. नाम

ख. पद

ग. इस पंचायत में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि

घ. कार्यभार/जिम्मेदारी का विवरण

ड. प्रतिदिन ड्यूटी पर आने और जाने का समय

2. उक्त एएनएम के उपस्थिति रजिस्टर की पिछले छह महीनों की प्रति उपलब्ध कराएं.

3. उक्त एएनएम द्वारा पिछले एक वर्ष में इस ग्राम पंचायत में किए गए टीकाकरण और दवा वितरण कार्यों की सूची उपलब्ध कराएं, जिसमें निम्नलिखित सूचनाएं अवश्य शामिल हों:

क. लाभार्थी का नाम व पता

ख. लाभार्थी को टीका लगाने या दवा दिए जाने की तारीख

ग. दवा और टीके का नाम

4. उक्त एएनएम अगर समय पर गांव का दौरा नहीं करती है तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही किए जाने का प्रावधान है? कृपया इस संबंध में नियमों/नीति निर्देशों की प्रतियां उपलब्ध कराएं.

5. इस पंचायत का कार्यभार संभालने के बाद अब तक उक्त एएनएम के खिलाफ देर से आने या अनुपस्थित रहने से संबंधित यदि कोई शिकायत प्राप्त हुई है तो उसका विवरण उपलब्ध कराएं, जिसमें निम्नलिखित सूचनाएं अवश्य शामिल हों:

क. शिकायत करने वाले का नाम

ख. शिकायत का संक्षिप्त विवरण

ग. शिकायत की तारीख

घ. शिकायत पर की गई कार्यवाही का विवरण

ड. कार्यवाही करने वाले अधिकारी का नाम, पद एवं पता

मैं आवेदन शुल्क के रूप में.....रुपये अलग से जमा कर रहा/रही हूं.

या

मैं बीपीएल कार्डधारक हूं, इसलिए सभी देय शुल्कों से मुक्त हूं. मेरा बीपीएल कार्ड नंबर.....है.

यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग/कार्यालय से संबंधित न हो तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन संबंधित लोक सूचना अधिकारी को पांच दिनों की समयावधि के अंतर्गत हस्तांतरित करें. साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम और पता अवश्य बताएं.

भवदीय

नाम.....
पता.....
फोन नंबर.....

संलग्नक.....
(यदि कुछ हो तो)

राशिफल

मेष (21 मार्च से 20 अप्रैल)
आपने अपने हिस्से का कार्य पूरा कर लिया है. अब आपको उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिससे आपके कौशल में बढ़ोतरी हो सके. उन नई चीजों को सीखने की कोशिश करें जिनका आपकी जिंदगी में व्यवहारिक तौर पर उपयोग हो सके.

वृष (21 अप्रैल से 20 मई)
सफलता और अपने आस-पास के लोगों को स्थायी न समझें. वृषभ राशि वाले जातक किसी भी काम की शुरुआत करने के बाद उसका नियमित रूप से ध्यान रखें नहीं तो सफलता आपके हाथ से दूर खिसक सकती है.

मिथुन (21 मई से 20 जून)
आपके द्वारा अपनी सृजनात्मकता को बढ़ाने वाले काम करने से आने वाले समय में आवश्यकतानुसार मदद मिलेगी.

कर्क (21 जून से 20 जुलाई)
आपको कोई नई सूचना मिल सकती है. उसका उपयोग आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए करें.

सिंह (21 जुलाई से 20 अगस्त)
आप अच्छे समय की शुरुआत के मुहाने पर खड़े हैं. जल्द ही आप उन सभी पुरानी चीजों को अलविदा कह देंगे जिन्होंने आपको अबतक बांधे रखा था.

कन्या (21 अगस्त से 20 सितंबर)
वर्तमान में जो घटनाएं घटित हुई हैं और जो स्थितयां उभर रही हैं उनका जोड़ आपको एक बेहतर अवस्था में ले जाएगा.

तुला (21 सितंबर से 20 अक्टूबर)
आप जितने ज्यादा निर्णय अपने विवेक और विश्लेषण के आधार पर लेंगे उतनी ही कम बाधाओं का आपको सामना करना पड़ेगा. इस तरह आप अपने दूसरे हितों के साथ सही तरह की नीतियां अपना सकेंगे.

वृश्चिक (21 अक्टूबर से 20 नवंबर)
आपको किसी की मदद की दरकार नहीं होगी बल्कि दूसरे लोग आपको समझ लेंगे. वे आपको सफलता पाने के लिए एक संकीर्ण रास्ता मुहैया कराएंगे.

धनु (21 नवंबर से 20 दिसंबर)
आप नए कदम उठाने के लिए अच्छी स्थिति में होंगे. जिससे आपकी प्रगति में सहूलियत होगी.

मकर (21 दिसंबर से 20 जनवरी)
जो लोग आपके लिए महत्वपूर्ण हैं उनकी तरफ ज्यादा ध्यान दें. किसी भी संघर्ष में आपको विजय मिलेगी चाहे वह संघर्ष खुद से हो या दूसरों से.

कुंभ (21 जनवरी से 20 फरवरी)
आम तौर पर जिन लोगों के पास अनुभव है या करीबी मित्रों के साथ बैठक करेंगे तो आपको सोचे और बिना सोचे लाभ होंगे.

मीन (21 फरवरी से 20 मार्च)
आपको सोचे समझे और संतुलित निर्णय लेने होंगे कि किस चीज के पीछे भागें और किसे छोड़ दें.

ज़रा हट के

सांप और छिपकली खाकर 19 दिन तक ज़िंदा रहा

मनुष्यों को जिंदा रहने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है और ऊर्जा भोजन से मिलती है, लेकिन कभी-कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि भोजन नहीं मिल पाता. कैलिफोर्निया के इस व्यक्ति के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब वह व्यक्ति जंगल में खो गया और इसे कुछ खाने को नहीं मिला तो इसने जंगल में खोने के बाद सांप, गिलहरी और छिपकली खाकर 19 दिन बिताए. यह शख्स उत्तरी कैलिफोर्निया के जंगल में रास्ता भूल जाने के कारण 19 दिन तक वहीं रहा. इस पूरे समय में न तो उसके पास कुछ खाने को था और न ही पीने को, लेकिन ज़िंदा तो रहना था. इसलिए जेन पेनाफ्लोर नाम के इस आदमी ने जंगल के जानवरों को ही अपना भोजन बनाना शुरू कर दिया. 72 वर्षीय इस आदमी को खोजने के लिए काफ़ी बचाव दल भेजे गए, लेकिन बीच में तूफ़ान आने के कारण उसको ढूंढा नहीं जा सका. 19 दिन बाद जब बचाव दल दोबारा उसको खोजने पहुंचा तो वो ज़िंदा था. लौटकर आने पर वह बताया कि वो इस दौरान छिपकली, सांप और गिलहरी का मांस खाकर ज़िंदा रहा. साथ ही सोने के लिए उसने सूखी पत्तियों का सहारा लिया. ■

बच्चे के पेट से निकलीं 22 सुइयां

केरल के कोल्लम इलाके में एक साल का बच्चा 22 सुइयां निगल गया, जिसे डॉक्टरों ने ऑपरेशन की मदद से बाहर निकाला. ऑपरेशन में शामिल डॉक्टर सुधीर ने बताया कि बच्चा कागज़ में लपेट कर रखी गई सुइयों को गलती से निगल गया था. संयोग सही था कि सभी सुइयां बिना आंतों को नुकसान पहुंचाएं सीधे पेट में चली गईं. बच्चे के माता-पिता उसे पेट में अधिक दर्द और उल्टियां होने के कारण अस्पताल लाए, जहां चिकित्सकों ने बच्चे के पेट का एक्सरे किया, जिसमें पता चला कि बच्चे के पेट में कम से कम 22 सुइयां हैं. बच्चे की हालत काफी ख़राब थी, इसलिए डॉक्टरों को आनन-फानन में ऑपरेशन का फ़ैसला लेना पड़ा. इस बेहद जटिल किस्म के ऑपरेशन में लगभग दो घंटे की जद्दोजहद के बाद डॉक्टर बच्चे के पेट से सुइयां निकालने में कामयाब रहे. ऑपरेशन के बाद बच्चे की रेडियोलॉजी की गई. साथ ही फिर एक्सरे कर यह सुनिश्चित करने की कोशिश की गई कि कहीं कोई सूई आंत में तो नहीं फंसी है, लेकिन इस पूरी जांच में कहीं कोई सूई नहीं मिली. ■

टैटू ने 22 साल बाद परिवार से मिलाया

महाराष्ट्र पुलिस में तैनात एक युवक 22 साल पहले अपने परिवार से बिछड़ गया था, लेकिन एक साधारण से टैटू के कारण वह अपने परिवार के पास फिर से पहुंच गया. 1991 में जब गणेश छह साल का था तो उसने एक दिन स्कूल बंक कर दिया. उसी दौरान खेलते हुए वह ठाणे के वागले इस्टेट उपनगर इंदिरा नगर में स्थित अपने घर से बहुत आगे निकल गया, लेकिन अब वह लौट आया है. उसके हाथ पर गुदे नाम से मांडा को मां ने अपने बेटे को तुरंत पहचान लिया. गणेश के खोने के बाद उसकी मां मांडा धनगड़े ने बेटे की तलाश में कोई कसर नहीं छोड़ी. खेल में उत्कृष्ट गणेश राज्य पुलिस परीक्षा में बैठा था और साल 2010 में चयनित हो गया था. वर्तमान में बतौर क्यूआरटी सदस्य तैनात होने से पहले उसने विभिन्न पदों पर काम किया. गणेश और उसका पूरा परिवार पिछले माह युवा भर्ती के लिए उसे लेकर आए क्यूआरटी इंस्पेक्टर श्रीकांत सोंधे का आभारी है. आभारी गणेश ने कहा कि मेरी बांह पर गुदे टैटू की तह में जाने के लिए सोंधे ने सभी पुलिस जांच तकनीकों का प्रयोग किया. आखिर में मेरे परिवार तक पहुंचने में मुझे सफलता मिल गई. ■

सबसे छोटी क़िताब

आप दृढ़ इच्छाशक्ति और आत्मविश्वास के साथ किसी कार्य को करने की ठान लें तो हर मुश्किल आसान हो सकती है. दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं है, जिसे पूरा न किया जा सके. इसी विश्वास के साथ प्रकाश उपाध्याय ने दुनिया की सबसे छोटी क़िताब लिखने कार्य कर किया. अब वह अपने इस कार्य को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं. प्रकाश ने दावा किया है कि अब तक विश्व में इतनी छोटी साइज की क़िताब किसी ने नहीं लिखी है. इसका साइज चार गुणा चार एमएम और मोटाई 8 एमएम है. 192 पृष्ठकी इस पुस्तक में 192 देशों के नाम उनके राष्ट्रध्वज के साथ है. राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में पैथोलॉजी विभाग में आर्टिस्ट के पद पर कार्यरत प्रकाश ने इस छोटी सी क़िताब को वाटर कलर व एक्रेलिक पेंट से लिखा है. कई दिनों की कड़ी मेहनत से यह पुस्तक तैयार की गई है. छोटी साइज की पुस्तक का अभी तक का जो रिकॉर्ड है, वह उत्तर प्रदेश के तरुण कुमार के नाम है. उनकी पुस्तक 5 गुणा 8 एमएम साइज की है, जिसमें हनुमान चालीसा लिखी गई है. 31 दिसंबर, 2012 को गिनीज बुक में इसे दर्ज किया गया था. प्रकाश का दावा है कि अब उनकी क़िताब दुनिया की सबसे छोटी क़िताब के रूप में दर्ज ज़रूर होगी. उन्हें अपने कार्य पर पूरा भरोसा है. प्रकाश ऑयल पेंटिंग व वाटर पेंटिंग बनाते हैं. ■

सुरक्षा परिषद की सदस्यता ठुकराना, सऊदी अरब की हताशा भले ही हो, लेकिन उसके इस क़दम से सुरक्षा परिषद के कार्यों और उसकी नीतियों पर एक सवालिया निशान ज़रूर लग गया है, जिससे सुरक्षा परिषद की ख़ामियां भी उजागर हुई हैं. यक़ीनन, सऊदी अरब का यह क़दम स्वागत योग्य है.

सुरक्षा परिषद ख़ुद असुरक्षित है

सऊदी अरब ने सुरक्षा परिषद की सदस्यता ठुकरा दी है. इस देश का कहना है कि परिषद दोहरे मापदंड अपनाता है. परिषद के 120 सदस्य देश भी सुरक्षा परिषद की कार्यशैली पर समय-समय पर सवाल उठाते रहे हैं. वास्तव में यह पूरे विश्व का मसला हो गया है. ज़रूरत है कि समय रहते सुरक्षा परिषद ख़ुद को बदले. अन्यथा आज सऊदी अरब ने इसकी सदस्यता ठुकराई है, कल कोई और देश ठुकराएगा और ऐसे में एक दिन सुरक्षा परिषद का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा.

राजीव रंजन

सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के छः प्रमुख अंगों में से एक है, जिसका उत्तरदायित्व है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, लेकिन सऊदी अरब ने जिस तरह से सुरक्षा परिषद की सदस्यता ठुकरा दी है, उससे सुरक्षा परिषद के औचित्य पर ही सवाल खड़े हो गए हैं. इस देश को पहली बार परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया था. सऊदी अरब ने यह आरोप लगाया है कि सुरक्षा परिषद विश्व में शांति कायम करने के लिए दोहरे मापदंड अपनाता है. उसका मानना है कि शांतिपूर्ण तरीके से मसले सुलझाने के लिए सुरक्षा परिषद का आधुनिकीकरण और विस्तार जरूरी है. परिषद मध्यपूर्व में पुराने संघर्ष को और परमाणु हमले के खतरे को खत्म करने में विफल रहा है. उसका यह भी आरोप है कि सीरिया में तीन साल से चल रहे गृहयुद्ध को खत्म करने के कोई उपाय नहीं किए हैं. हालांकि सऊदी अरब को मध्यपूर्व के क्षेत्र और विशेष रूप से सीरिया में आतंकवादी संगठनों का मुख्य समर्थक माना जाता है. उसका यह भी कहना है कि फिलस्तीन–इजरायल के बीच 65 साल पुराने संघर्ष को परिषद नहीं रोक पाया है. बहरीन जैसे कुछ देशों ने सऊदी अरब के फैसले का समर्थन किया है और कहा है कि सुरक्षा परिषद की खाड़ी एवं अरब देशों के प्रति दोहरे मापदंडों को सामने लाने के लिए यह पश्चिमी देशों को एक कड़ा संदेश है. उसका कहना है कि सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय मुठभेड़ों से निपटने में विफल रही है.

संयुक्त राष्ट्र में भारत

भारत संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है. यह 7 बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है. इतना ही नहीं, भारत संयुक्त राष्ट्र के शांति स्थापना संबंधी अभियानों में महती भूमिका निभाने वाला सबसे बड़ा देश है. संयुक्त राष्ट्र के शांति स्थापना के लिए चल रहे 14 मिशनों में से 7 मिशनों में भारत सशस्त्र बल भाग ले रहा है. भारत ने 1996 में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर एक प्रारूप प्रस्तुत किया. भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण एवं अप्रसार के मुद्दे को आगे बढ़ाया है. यह परमाणु हथियारों से लैस एकमात्र ऐसा देश है, जिसने परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन की मांग की है. भारत ने 2005 में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि का गठन किया.

क्यों ठुकराई सदस्यता

सऊदी अरब द्वारा परिषद की सदस्यता ठुकराने के पीछे दो कारण हो सकते हैं. पहला तो यह कि सीरिया पर अमेरिकी आक्रमण की चाह रखने वाले सऊदी अरब अपने निजी हितों को पूरा न होता देख तिलमिला गया हो और आनन–फानन में परिषद की सदस्यता अस्वीकार कर दिया हो. दूसरा कारण यह कि सचमुच सुरक्षा परिषद की प्रासंगिकता समाप्त हो गई हो. हालांकि सऊदी अरब के मामले में दूसरा कारण सही साबित नहीं होता, क्योंकि सऊदी अरब ने इसे लेकर पहले कभी कोई सवाल क्यों नहीं उठाया और एक ही बार उसने सदस्यता नामंजूर कर लेने का फैसला कैसे कर लिया. ये सारी घटनाएं सऊदी अरब के हताशा को ही व्यक्त करती हैं. सऊदी अरब के इस फैसले पर विदेश नीति के जानकारों का कहना है कि सीरिया में बशर असद की सरकार को गिराने के लिए सऊदी अरब ने विश्व के अनेक देशों से आतंकवादियों को एकत्रित किया और उन्हें प्रशिक्षण तथा भारी हथियार दिए. उसे क़तर और जॉर्डन सहित अनेक देशों का भरपूर सहयोग भी मिला, लेकिन सऊदी अरब को सीरिया की जनता और सरकार से लज्जाजनक पराजय मिली है, जिससे वह परेशान हो गया है. ओबामा प्रशासन ने जिस तरह से सीरिया संकट का कूटनीतिक समाधान निकाला है, वह भी सऊदी अरब को बहुत अखरा है, जिससे सऊदी अरब की शाही सरकार बुरी तरह हताश है.

स्वागतयोग्य क़दम

सुरक्षा परिषद की सदस्यता ठुकराने की घटना सऊदी अरब की हताशा ही सही, लेकिन इससे जो बड़ी बात निकल कर सामने आई, वह यह कि वर्षों से सुरक्षा परिषद के कार्यों और उसकी नीतियों पर कम से कम किसी देश ने सवालिया निशान तो लगाया. सऊदी अरब का यह कदम स्वागत योग्य है. परोक्ष–अपरोक्ष रूप से इस देश के इस कदम का समर्थन सुरक्षा परिषद के वे 120 सदस्य देश भी कर रहे हैं, जो पहले ही सुरक्षा परिषद के कार्यों और उसके दोहरे मापदंड को लेकर लगातार सवाल खड़े करते आ रहे हैं.

हालांकि सऊदी अरब ने सुरक्षा परिषद से अलग होने के पीछे परिषद को ही जिम्मेदार ठहराया है, ताकि विश्व जनमत उसके निजी हितों के मुद्दों को लेकर उसकी खिल्ली न उड़ाए और सुरक्षा परिषद के ढुलमुल कार्यों को देखते हुए परिषद पर ही सारा दोष मढ़ दिया जाए. सऊदी अरब का यह आरोप लगभग सही निशाना पर लग भी गया है, क्योंकि सऊदी के सुरक्षा परिषद की सदस्यता से इन्कार कर देने से विश्व में सुरक्षा परिषद के औचित्य पर ही सवाल खड़ा हो गया है. हालांकि दबी जुबान से सऊदी अरब के इस कदम को लेकर विश्व के देशों में सुगबुगाहट भी शुरू हो गई है कि सऊदी अरब अपने निजी हितों और अपनी मनमानी न पूरा होते देख सुरक्षा परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है.

सुरक्षा परिषद की विफलता

सुरक्षा परिषद का कार्य है वैश्विक संघर्षों को निपटा कर संपूर्ण विश्व में शांति की स्थापना, लेकिन अपनी स्थापना से लेकर आज तक उसने ऐसा कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं दिया है, जिससे उसके होने या न होने का औचित्य समझ में आए. यही कारण है कि विश्व के लगभग अधिकांश सदस्य देश उसकी कार्य शैली पर समय–समय पर उंगली उठाते रहे हैं. ऐसे में सऊदी अरब का यह कदम आग में घी डालने का काम किया है. सबसे बड़ी बात तो यह है कि सुरक्षा परिषद की अपनी कोई सेना नहीं है. नाटो देशों के पास अपनी सेना है, जिससे वे उन देशों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, जो उनके हितों की अनदेखी करते हैं. यही कारण है कि विश्व नाटो देशों से खौफ खाता है. सुरक्षा परिषद के पास अपनी सेना नहीं होने से विश्व के देशों पर न तो किसी तरह का भय काम करता है और न ही किसी तरह का बंधन. ऐसे में सवाल उठता है कि अगर कोई देश मनमानी करता है तो परिषद उस देश पर कार्रवाई किस आधार पर करे. सेना के होने का मतलब आक्रमण करना ही नहीं है, बल्कि सेना सांकेतिक तौर पर भी शांति को बढ़ावा देती है.

सुरक्षा परिषद की परवाह नहीं

वैश्विक देशों की हालत यह है कि कोई भी देश अपने निजी स्वार्थ को साधने के लिए दूसरे देश से दुश्मनी मोल ले लेता है. यही नहीं, छोटे–छोटे मसलों पर वे देश न सिर्फ कमजोर देश को सताते हैं, बल्कि वहां के संसाधनों पर कब्जा करने की फिराक में छिटपुट हमले भी कर देते हैं और उस देश के जान–माल की तनिक भी चिंता नहीं करते. अमेरिका का उदाहरण इस मामले में बहुत सही है, जिसने पूरे विश्व में घूम–घूम कर हमला किया है और आज भी वह इसके लिए बहाना ढूढ़ता है. अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अभी हाल ही में सीरिया के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को लेकर सुरक्षा परिषद को दरकिनार कर आगे बढ़ने का फैसला किया था. ओबामा ने यहां तक कह दिया था कि यह निकाय पूरी तरह से पंगु हो चुकी है. सुरक्षा परिषद की भूमिका को लेकर भारत का कहना है कि सुरक्षा परिषद अपनी संरचना और कामकाज में सुधार की कमी के चलते वैश्विक संकटों पर सटीक रुख अपनाने में अक्षम है. हाल ही में रूस की यात्रा पर गए भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और रूस के राष्ट्रपति ब्लादीमिर पुतिन ने सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता जताई, ताकि उभरने वाली चुनौतियों से और प्रभावी तरीके से निपटा जाए और इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व हो सके.

वैश्विक देशों का यह मानना है कि जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा परिषद ने अपने कार्यों का निर्वहन किया है, उसे लेकर पूरे विश्व में निराशा का माहौल है. कहना गलत नहीं होगा कि सुरक्षा परिषद के होने और न होने का कोई बहुत मतलब नहीं है. वह विभिन्न संकटों के समय प्रतिक्रिया नहीं करता. दूसरी तरफ वह अपने सदस्य देशों को साथ लेकर न तो चल पाता है और न ही उन देशों में सामंजस्य बैठा पाता है. परिषद के कुछ स्थायी सदस्य भी सुरक्षा परिषद में सुधार को लेकर चिंतित हैं. सुरक्षा परिषद में जितना जल्दी सुधार होगा, वह अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बरकरार रखने की अपनी भूमिका उतनी अधिक निभा सकेगा. सबसे बड़ा सवाल यह है सुधार के बिना सुरक्षा परिषद आखिर कितने समय तक कार्य कर सकता है.

क्या हो सकता है

अगर सऊदी अरब अपनी बात पर अड़ा रहता है तो एशिया पेसिफ़िक ग्रुप को महासभा के पटल पर किसी अन्य देश का नाम रखना होगा, लेकिन इससे पहले सऊदी अरब को मनाने के लिए कूटनीतिक प्रयास किए जाएंगे. बान की मून ने कहा है कि कुछ सदस्य देश, खासकर संबंधित सदस्य देशों का समूह इस मुद्दे पर विचार–विमर्श कर रहा है. ये देश इसके बारे में कौन–सा फैसला करेंगे, इस पर वो खुद भी करीबी नजर रखेंगे. कुवैत सऊदी अरब का स्थान लेने के लिए प्रयास भी करने लगा है. कुछ भी हो, लेकिन सुरक्षा परिषद की महत्त्वपूर्ण भूमिका है और हर देश का अपना एक मत हो सकता है. इसलिए यह जरूरी है कि हर देश, जिसे सुरक्षा परिषद में महत्वपूर्ण भूमिका दी जाए, उसका जिम्मेदारीपूर्वक निर्वहन करे, न कि अपनी जिम्मेदारियों से भागे. कोई सदस्य देश संगठन में रहकर भी अपनी बात कह सकता है, लेकिन अफसोस सऊदी अरब ने ऐसा नहीं किया.

सुरक्षा परिषद की महत्ता

सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के छः प्रमुख अंगों में से एक है, जिसका उत्तरदायित्व है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना. सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष हर महीने वर्णमालानुसार बदलता है. परिषद को अनिवार्य निर्णयों को घोषित करने का अधिकार भी हैं. वीटो या प्रतिनिषेध शक्ति द्वारा सुरक्षा परिषद के बहुमत से स्वीकृत कोई भी प्रस्ताव किसी एक सदस्य देश की असहमति से भी रोका जा सकता है.

भारत की स्थाई सदस्यता

भारत की सुरक्षा परिषद में स्थाई सदस्यता को लेकर परिषद के अधिकांश स्थाई सदस्य देशों ने भारत के दावे का समर्थन किया है, लेकिन अभी भी भारत को सुरक्षा परिषद में स्थाई सदस्यता नहीं मिल पाई है. हाल ही में रूस ने एक बार फिर सुरक्षा परिषद में स्थाई सदस्यता के भारत के दावे का समर्थन किया है. सुरक्षा परिषद का आखिरी विस्तार साल 1963 में हुआ था, जब अस्थाई श्रेणी में सदस्यों की संख्या 11 से बढ़ाकर 15 कर दी गई. भारत के साथ ब्राजील, जर्मनी और जापान ने मिलकर सुरक्षा परिषद में स्थाई सदस्यता में विस्तार हेतु दबाव बनाने के लिए चार देशों का समूह (जी4) बनाया है. फिलहाल सुरक्षा परिषद में पांच स्थाई सदस्य हैं– चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका. इसके अलावा 10 अस्थाई सदस्य भी हैं, जिसमें पांच सदस्य दो वर्ष के कार्यकाल के लिए हर साल चुने जाते हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

साई

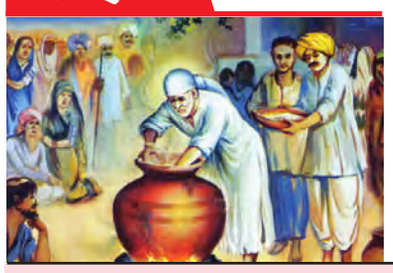

अन्नदान के बिना सभी दान वैसे ही अपूर्ण हैं, जैसे कि चन्द्रमा बिना तारे, भक्तिरहित भजन, सिन्दूर बिना सुहागिन, मधुर स्वरविहीन गायन, नमक बिना पकवान. जिस प्रकार अन्य भोज्य पदार्थों में दाल उत्तम समझी जाती है, उसी प्रकार समस्त दानों में अन्नदान श्रेष्ठ है. साई बाबा अल्पाहारी थे और वे थोड़ा बहुत जो कुछ भी खाते थे, वह उन्हें केवल दो गृहों से ही भिक्षा में उपलब्ध हो जाया करता था.

एक बार...

साई सबकी झोली भरते हैं

चौथी दुनिया ब्यूरो

मानव धर्म–शास्त्र में भिन्न–भिन्न युगों के लिए भिन्न–भिन्न साधनाओं का उल्लेख किया गया है . सतयुग में तप, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ और कलयुग में दान का विशेष माहातम्य है. सब दानों में अन्नदान को श्रेष्ठ माना गया है. जब दोपहर के समय हमें भोजन प्राप्त नहीं होता, तब हम विचलित हो जाते हैं. ऐसी ही स्थिति में अन्य प्राणियों को अनुभव कर जो भिक्षुक या भूखे को भोजन देता है, वही श्रेष्ठ दानी है. जब कोई अतिथि दोपहर के समय घर आता है तो हमारा कर्तव्य होता है कि हम उसका अभिनंदन कर उसे भोजन कराएं. अन्य दान जैसे– धन, भूमि और वस्त्र इत्यादि देने में तो पात्रता का विचार करना पड़ता है, लेकिन अन्न के लिए विशेष सोच–विचार की आवश्यकता नहीं है. दोपहर के समय कोई भी आपके द्वार पर आए, उसे शीघ्र भोजन कराना हमारा परम कर्त्तव्य है. लूले, लंगड़े, अन्धे या भिखारियों को, हाथ–पैर से स्वस्थ लोगों को और उन सभी के बाद अपने संबंधियों को भोजन कराना चाहिए. अन्य सभी की अपेक्षा पंगुओं को भोजन कराने का महत्व अधिक है.

अन्नदान के बिना अन्य सब प्रकार के दान वैसे ही अपूर्ण है, जैसे कि चन्द्रमा बिना तारे, भक्तिरहित भजन, सिन्दूर बिना सुहागिन, मधुर स्वरविहीन गायन, नमक बिना पकवान. जिस प्रकार अन्य भोज्य पदार्थों में दाल उत्तम समझी जाती है, उसी प्रकार समस्त दानों में अन्नदान श्रेष्ठ है. साई बाबा अल्पाहारी थे और वे थोड़ा बहुत जो कुछ भी खाते थे, वह उन्हें केवल दो गृहों से ही भिक्षा में उपलब्ध हो जाया करता था, लेकिन जब उनके मन में सभी भक्तों को भोजन कराने की इच्छा होती तो प्रारम्भ से लेकर अन्त तक संपूर्ण व्यवस्था वे स्वयं किया करते थे. वे किसी पर निर्भर नहीं रहते थे. वे स्वयं बाजार जाकर सब वस्तुएं नगद दाम देकर खरीद लाया करते थे. यहां तक कि पीसने का कार्य भी वे स्वयं ही किया करते थे. मस्जिद के आंगन में ही एक भट्टी बनाकर उसमें अग्नि प्रज्ज्वलित करके हांडी के ठीक नाप से पानी भर देते थे. कभी वे मीठे चावल बनाते, कभी–कभी दाल और मुटकुले भी बना लेते थे. पत्थर की सिल पर महीन मसाला पीस कर हांडी में डाल देते थे. भोजन रुचिकर बने, इसका वे पूरा प्रयास करते थे. ज्वार के आटे को पानी में उबाल कर उसमें छांछ मिलाकर अंबिल (आमर्टी) बनाते और भोजन के साथ सब भक्तों को समान मात्रा में बांट देते थे. भोजन ठीक बन रहा है या नहीं, यह जानने के लिए वे निर्भयता से उबलती हांडी में हाथ डाल देते और उसे चारों ओर घुमाया करते थे. ऐसा करने पर भी उनके हाथ पर न कोई जलन का चिन्ह और न चेहरे पर ही कोई व्यथा की रेखा प्रतीत हुआ करती थी. जब पूर्ण भोजन तैयार हो जाता, तब वे मस्जिद में बर्तन मंगाकर मौलवी से फातिहा पढ़ने को कहते थे, फिर वे म्हालसापति तथा तात्या पाटिल का प्रसाद रखकर शेष भोजन गरीब और अनाथ लोगों को खिलाकर उन्हें तृप्त करते थे. कितने भाग्यशाली थे वे, जिन्हें बाबा के हाथ का बना और परोसा हुआ भोजन खाने का मिला.

अन्नदान के बिना सभी दान वैसे ही अपूर्ण हैं, जैसे कि चन्द्रमा बिना तारे, भक्तिरहित भजन, सिन्दूर बिना सुहागिन, मधुर स्वरविहीन गायन, नमक बिना पकवान. जिस प्रकार अन्य भोज्य पदार्थों में दाल उत्तम समझी जाती है, उसी प्रकार समस्त दानों में अन्नदान श्रेष्ठ है. साई बाबा अल्पाहारी थे और वे थोड़ा बहुत जो कुछ भी खाते थे, वह उन्हें केवल दो गृहों से ही भिक्षा में उपलब्ध हो जाया करता था, लेकिन जब उनके मन में सभी भक्तों को भोजन कराने की इच्छा होती तो प्रारम्भ से लेकर अन्त तक संपूर्ण व्यवस्था वे स्वयं किया करते थे.

यहां कोई यह शंका कर सकता है कि क्या वे शाकाहारी और मांसाहारी भोज्य पदार्थों का प्रसाद सभी को बांटा करते थे. यह एक अति पुरातन अनुभूत नियम है कि जब गुरुदेव प्रसाद वितरण कर रहे हों, अगर उस समय कोई शिष्य उसे ग्रहण करने में शंकित हो जाए तो उसका पतन हो जाता है. यह अनुभव करने के लिए कि शिष्यगण इस नियम का किस अंश तक पालन करते हैं, वे कभी–कभी परीक्षा भी ले लिया करते थे. उदाहरणार्थ एकादशी के दिन उन्होंने दादा केलकर को कुछ रुपये देकर मांस खरीद लाने को कहा. दादा केलकर पूरे कर्मकांडी थे और प्रायः सभी नियमों का जीवन में पालन किया करते थे. उनकी यह दृढ़ भावना थी कि द्रव्य, अन्न और वस्त्र इत्यादि गुरु को भेंट करना पर्याप्त नहीं है. केवल उनकी आज्ञा ही शीघ्र कार्यान्वित करने से वे प्रसन्न हो जाते हैं. यही उनकी दक्षिणा है. दादा शीघ्र कपड़े पहन कर एक थैला लेकर बाजार जाने के लिए तैयार हो गए. तब बाबा ने उन्हें वापस बुला लिया और कहा कि तुम न जाओ, अन्य किसी को भेज दो. दादा ने अपने नौकर पांडू को इस कार्य के निमित्त भेजा. उसको जाते देखकर बाबा ने उसे भी वापस बुलाने को कहकर यह कार्यक्रम स्थगित कर दिया.

ऐसे ही एक अन्य अवसर पर उन्होंने दादा से कहा कि देखो तो नमकीन पुलाव कैसा पका है. दादा ने यों ही मुंह देखी और कह दिया कि अच्छा है. तब वे कहने लगे कि तुमने न अपनी आंखों से ही देखा है और न जिह्वा से स्वाद लिया, फिर तुमने यह कैसे कह दिया कि उत्तम बना है. थोड़ा ढक्कन हटाकर तो देखो. बाबा ने दादा की बांह पकड़ी और बलपूर्वक बर्तन में डालकर बोले–थोड़ा सा इसमें से निकालो और अपना कट्टरपन छोड़कर चख कर देखो. जब मां का सच्चा प्रेम बच्चे पर उमड़ आता है, तब मां उसे दुलारती है, परन्तु उसका चिल्लाना या रोना देखकर वह उसे अपने हृदय से लगाती है. इसी प्रकार बाबा ने सात्विक मातृ प्रेम के वश होकर दादा का इस प्रकार हाथ पकड़ा. यथार्थ में कोई भी सन्त या गुरु कभी भी अपने कर्मकांडी शिष्य को वर्जित भोज्य के लिए आग्रह करके अपनी अपकीर्ति कराना पसन्द नहीं करेगा.

इस प्रकार यह हांडी का कार्यक्रम सन 1910 तक चला और फिर स्थगित हो गया. दासगणू ने अपने कीर्तन द्वारा समस्त मुंबई प्रांत में बाबा की अधिक कीर्ति फैली. फलतः इस प्रान्त से लोग झुंड के झुंड शिरडी आने लगे और थोड़े ही दिनों में शिरडी पवित्र तीर्थ–क्षेत्र बन गया. भक्तगण बाबा को नैवेद्य अर्पित करने के लिए नाना प्रकार के स्वादिष्ट पदार्थ लाते थे, जो इतनी अधिक मात्रा में एकत्र हो जाता था कि फकीरों और भिखारियों को सन्तोषपूर्वक भोजन कराने पर भी बच जाता था. साई की लीला अपरंपार है और उनके दर से कोई खाली नहीं जाता. ■

feedback@chauthiduniya.com

साई भक्तों!

आप भी चौथी दुनिया को साई से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साई से आप कब और कैसे जुड़े. साई की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साई को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साई भक्त. साई बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है. साई बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

चौथी दुनिया
एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश, पिन–201301
ई–मेल feedback@ chauthiduniya.com

सत्य ही ईश्वर है

डॉ. अभय बंग

गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग, विद्यार्थी–जीवन में पढ़ी थी. उसके बाद से अब तक बहुत पानी बह चुका था. फिर से पढ़ने की प्रेरणा हुई. स्वयं को शुद्ध कैसे किया जाए. इसके बारे में उनके अनुभव शायद मेरे लिए मार्गदर्शक होंगे, ऐसी उम्मीद जगी.

आत्मकथा में अनेक उपयोगी बातें मिलीं. परन्तु सबसे गहराई में एक वाक्य छू गया. रोमां रोलां से भेंट होने के दौरान गांधी जी ने उनसे कहा, ईश्वर कोई व्यक्ति न होकर एक तत्व है. इस वाक्य की ओर पहले कभी मेरा ध्यान नहीं गया था. ईश्वर है या नहीं, इसका तर्कयुक्त या पूर्णरूप से विश्वसनीय उत्तर मेरे पास नहीं था. ईश्वर शब्द कहते ही स्वर्ग में सिंहासन पर बैठा हुआ, मुकुट पहने एक तेजस्वी पुरुष यही चित्र आंखों के सामने आ जाता, जो कि बचपन में पौराणिक कहानियों और चित्रों के माध्यम से अनजाने ही मन की गहराइयों में बस गया था. ऐसा कोई व्यक्ति होगा, इस पर बुद्धि एवं तर्क विश्वास नहीं करने देते थे. परंतु ईश्वर के अस्तित्व को नकार भी नहीं सकता था. दुविधा ही थी. परंतु यह वाक्य पढ़ा और पढ़ते ही लगा ईश्वर अगर (ऐसा सिंहासन पर बैठा हुआ वगैरह) व्यक्ति नहीं, तत्व रूप हो तो वास्तव में हो सकता है. परंतु तत्व रूप हो तो कौन–सा तत्व? कौन–सा रूप?

अन्य किसी जगह गांधीजी कहते हैं–सत्य ही ईश्वर है. यह एक विलक्षण साहसी एवं प्रचितिपूर्ण वाक्य प्रतीत हुआ. ईश्वर सत्य है, ऐसा सभी धार्मिक श्रद्धाएं कहती हैं. परंतु सत्य ही ईश्वर है. यदि सत्य ही खुद ईश्वर है, तब तो ईश्वर अवश्य हो सकता है, क्योंकि सत्य है, इस विषय में कोई संशय नहीं, बल्कि जो है, उसे ही तो हम सत्य कहते हैं. अर्थात जो है, वही ईश्वर है?

कुछ विलक्षण प्रत्यय हुआ. ईश्वर के अस्तित्व के विषय में बुद्धि का विज्ञाननिष्ठ संशय मिट गया. ईश्वर=सत्य, यह पारंपरिक समीकरण पलटकर गांधी जी ने सत्य=ईश्वर कर दिया था. गणित की दृष्टि से यह बिलकुल दुरुस्त था और इस समझ के साथ अचानक सब प्रकाशमान होकर सारा संशय, सम्भ्रम मिट गया. सत्य ही अगर ईश्वर है, तब तो ईश्वर को ढूंढ़ा जा सकता है, उसे अनुभव किया जा सकता है. ईशावास्योपनिषद के अपने भाष्य में (ईशावास्यवृत्ति) विनोबा ने सत्य व ईश्वर इनके अद्वैत के विषय में संशयरहित आर–पार जाने वाली दृष्टि दी. एक जगह विनोबा कहते हैं–ईश्वर सत्य कि सत्य ईश्वर?

एक तत्वज्ञान की भाषा है, दूसरी उपासन की.

यद्यपि ईश्वर सत्य है और सत्य ईश्वर है. इन दोनों का अर्थ एक ही है, तो भी उपासकों के लिए, साधकों के लिए सत्य ही ईश्वर है, यह दृष्टिकोण अधिक उपयोगी है, क्योंकि सत्य से साधना के प्रयास की शुरुआत की जा सकती है. ईश्वर के निर्गुण होने के कारण उससे उपासना का प्रारम्भ नहीं किया जा सकता. ईश्वर तत्वरूप है, ऐसा गांधी जी का वक्तव्य है.

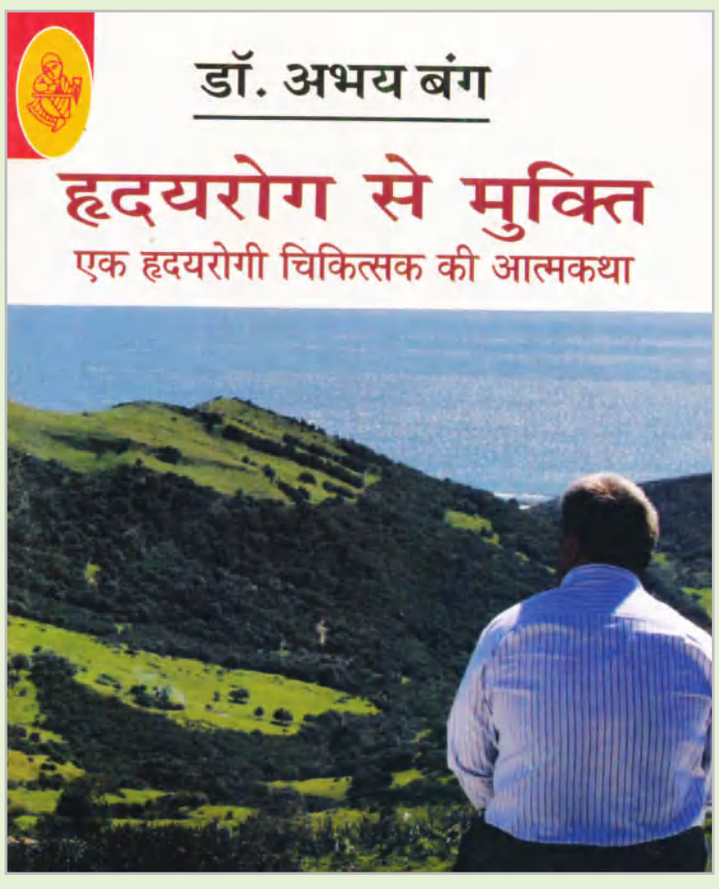

इसका अर्थ क्या हुआ? तत्व अर्थात तत्+त्व. वह पन. वह अर्थात अस्तित्व. जो भी है, उसका होना, अस्तित्व योग ही ईश्वर है. कितना आसान है यह? खेल ही है जैसे.

अब तो तेजी से अर्थ समझ में आने लगे. सत्य तो सब जगह है–क्योंकि जो है, वही सत्य है. फिर ये पेड़, ये पहाड़, ये हवा, ये पत्थर, ये मनुष्य, यह चींटी–ये सब सत्य हैं–अर्थात ये ईश्वर हैं? चराचर में ईश्वर का निवास है अथवा ईशवास्यं इदं सर्वम् का यही अर्थ है. अरे, आज तक मैं यह वचन बोलता आया, परंतु कभी समझ में कैसे नहीं आया?

एक सुंदर जापानी हायकू है.

मैंने पेड़ से कहा
पेड़, पेड़, मुझे ईश्वर के बारे में बताओ
और उस पेड़ में बहार आई.

ईश्वर क्या होता है, यह बात उस पेड़ ने प्रत्यक्ष बहार से बतलाई. पेड़ का होना, उस पर फूलों का खिलना, यही ईश्वर है.

और एंजियोप्लास्टी टेबल पर मुझ पर प्रस्फुटित हुआ अर्थ? उत्पत्ति (बिग बैंग) के बाद की ऊर्जा से मूल कणों का निर्माण होने पर, उनसे यह सारा विश्व निर्मित हुआ है. प्रत्येक वस्तु उसी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि मुलकणों से बनी है. इस कारण सम्पूर्ण विश्व में एक ही सत्य व्याप्त है, इसमें विज्ञान को संशय नहीं. उलटे ऐसी सर्वव्यापक सर्वसमावेशक वैज्ञानिक थ्योरी, जनरल थ्योरी, खोजना यही आधुनिक फिजिक्स का सर्वोच्च ध्येय है. यह थ्योरी अर्थात सत्य का साक्षात्कार, अर्थात ईश्वर का ही साक्षात्कार?

विज्ञान व अध्यात्म हाथों में हाथ डाले चलने लगे. साथ–साथ कुछ आध्यात्मिक साहित्य भी पढ़ रहा था. पतंजलि के योगसूत्र का अनुवाद पढ़ा. संस्कृत सीखने की तीव्र इच्छा होने लगी. विनोबा की गीता प्रवचन किताब व ईशवास्योपनिषद पर उनकी लिखी ईशावास्यवृत्ति यह छोटी–सी पुस्तिका मेरे प्रमुख आधार थे.

ईशावास्यवृत्ति नामक विनोबा की छोटी–सी पुस्तक हीरे–मोतियों से तौलने योग्य है. ईशावास्योपनिषद जैसा अतिशय सघन दर्शन (कुल सिर्फ 18 श्लोक). उस पर कम–से–कम शब्दों में सूत्रमय भाष्य विनोबा ने लिखा. किसके लिए? गांधी जी के स्वयं उपयोग के लिए. गांधी जी के आग्रह पर उनके लिए विनोबा ने संस्कृत के गूढ़ ईशावास्योपनिषद का अर्थ स्पष्ट करनेवाली यह पुस्तिका लिखी. इससे अधिक पवित्र त्रिवेणी संगम खोजना कठिन ही है. रोज सुबह उठकर ईशावास्योपनिषद का पाठ करता हूं. वह इतना अर्थपूर्ण है कि दुनिया की सारी पुस्तकें नष्ट होने वाली हों और एक ही पुस्तक बचनेवाली हो तो मैं ईशावास्योपनिषद को चुनूंगा, ऐसा गांधी जी लिखते हैं. रोज सबेरे जब इसका पाठ करता हूं, मन की स्नान–शुद्धि हो जाती है. आज के दिन एक जीवन नये सिरे से शुरू होता है.■

राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली से प्रकाशित

feedback@chauthiduniya.com

एक बार...

भेड़िया और मेमना

एक जंगल के किनारे घास के मैदान में बकरियों का झुंड रहा करता था. बकरियों की रखवाली के लिए दो कुत्ते हुआ करते थे. बकरियां कभी भी जंगल में घास खाने नहीं जाती थी, क्योंकि जंगल के बीच में शिकारी जानवर रहते थे, जिनसे बकरियों को हमेशा खतरा बना रहता था. बकरियां अपने मेमनों को भी जंगल में नहीं जाने देती थीं, लेकिन एक दिन एक छोटा सा मेमना हरी और मीठी घास खाते–खाते जंगल के बीच में चला गया. एक भेड़िए ने उसे देख लिया. देखते ही भेड़िया मेमने के सामने कूद पड़ा. उसने अपने बड़े–बड़े नुकीले दांत भींच कर बोला, तुम्हें मालूम है कि तुम्हें इस तरह यहां घूमना नहीं चाहिए. भेड़िए को देख मेमना भय के मारे कांपने लगा, लेकिन उसने धैर्य के साथ कहा कि मुझे मालूम है कि इस तरह मुझे नहीं घुमना चाहिए. यह सुन कर भेड़िया उस पर जोर से हंस पड़ा और बोला अब तुम शरारती हो गए हो, तुम्हें दंड मिलनी चाहिए. मैं तुम्हें दंड दूंगा. तुम्हें खाकर अपना पेट भरूंगा. मेमना भयभीत हुआ. इसलिए उसने एक उपाय सोचा. उसने भेड़िए से कहा कि क्या आप मेरी अंतिम इच्छा पूरी नहीं करेंगे. भेड़िए ने कहा, हां इससे मुझे कोई हानि नहीं होगी. मेमने ने कहा कि क्या आप मेरे लिए एक गाना नहीं गाओगे और जोर–जोर से गाने लगा. कुत्ते गाने की आवाज सुनकर समझ गए की मेमना जंगल में चला गया है. वे दौड़ते हुए जंगल में पहुंच गए, लेकिन भेड़िया कुत्तों को देखते ही भाग गया. मेमना अपनी मां के पास गया और कहने लगा कि मैं अब कभी नहीं जाऊंगा. हमेशा बुजर्गों की बातों को मानूंगा ■

शिक्षा : *बुजुर्गों की सीख कारगर होती है.*

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

साहित्य

> अंग्रेज़ी लेखन में महिलाओं के इस दबदबे के बीच साहित्य के लिए इस वर्ष को नोबेल पुरस्कार कनाडा की बयासी साल की वयोवृद्ध लेखिका एलिस मुनरो को दिया गया. मुनरो को पुरस्कार मिलने के बाद अंग्रेज़ी में हो रहे महिला लेखन पर एक बार फिर से सबकी नज़र चली गई.

पुस्तक चर्चा

अंग्रेज़ी में सशक्त महिला लेखन

अनंत विजय

विश्व साहित्य ख़ासकर अंग्रेज़ी साहित्य के इतिहास में दो हज़ार तेरह को महिला लेखन की सशक्त मौजूदगी को लेकर याद किया जाएगा. अमेरिका से लेकर इंग्लैंड, कनाडा से लेकर न्यूजीलैंड तक में लेखिकाओं ने अपने लेखन को एक नया आयाम दिया, एक नई ऊंचाई दी और साथ ही एक नया अंदाज़ भी दिया. अमेरिका की रशेल कुशनर की द फ्लेमथ्रोअर्स ने तो अपने कथ्य और विषय को लेकर पूरे साहित्य जगत को झकझोर दिया था. सत्तर के दशक में आतंक और कला को केंद्र में रखकर लिखे गए उपन्यास को इक्कीसवीं सदी का सर्वोत्तम उपन्यास करार दिया गया था. अमेरिका में भी हिंदी साहित्य की तरह ही सर्वोत्तम और सदी का महानतम, सदी का सर्वश्रेष्ठ क़रार देने की एक लंबी परंपरा है. पिछले साल जब जोनाथन फ्रेंजन का उपन्यास फ्रीडम छपकर आया था तो उसे भी अमेरिकी आलोचकों ने सदी की महानतम कृतियों की श्रेणी में रखते हुए उसको लियो टॉलस्टाय के वॉर एंड पीस के टक्कर का उपन्यास बताया था. अमेरिका और ब्रिटेन के लेखकों के अलावा अंग्रेज़ी में लिख रही एशियाई लेखिकाओं पर भी गौर करें तो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उन्होंने भी अपने लेखन से अंग्रेज़ी साहित्य के आलोचकों का ध्यान खींचा. हम मैन बुकर प्राइज़ के लिए नामांकित लेखकों पर नज़र डालें तो यह तस्वीर और साफ़ होती है. छह में से चार लेखिकाएं–झुंपा लाहिड़ी की द लोलैंड, एलेनॉर काटन की द ल्यूमिनरीज, वॉयलेट बुलावॉयो की वी नीड न्यू नेम्स, रूथ ओजकी की अ टेल फॉर द टाइम बीइंग इस सूची में थी. इसमें से ही न्यूज़ीलैंड की अट्ठाइस साल की युवा लेखिका एलेनॉर काटन की द ल्यूमिनरीज को मैन बुकर प्राइज़ से नवाजा गया. आठ सौ से ज़्यादा पन्नों में लिखे गए इस उपन्यास ने अपने क्राफ्ट और रोमांच की वजह से सूची के बाक़ी लेखकों को पछाड़ा. मैन बुकर के अलावा के ग्रांटा के बेस्ट अंडर फोर्टी के बीस लेखकों की सूची में भी बारह लेखिकाओं ने जगह बनाई. उसी तरह से अमेरिका के नेशनल बुक फाउंडेशन के फाइव अंडर थर्टी फाइव की सूची में पहली बार पांचों लेखिकाएं ही रहीं.

अंग्रेज़ी लेखन में महिलाओं के इस दबदबे के बीच साहित्य के लिए इस वर्ष को नोबेल पुरस्कार कनाडा की बयासी साल की वयोवृद्ध लेखिका एलिस मुनरो को दिया गया. मुनरो को पुरस्कार मिलने के बाद अंग्रेज़ी में हो रहे महिला लेखन पर एक बार फिर से सबकी नज़र चली गई. एलिस मुनरो लंबे–लंबे उपन्यास नहीं लिखती हैं. वो मूलत: कथाकार हैं, जिन्हें अंग्रेज़ी में शॉर्ट स्टोरी राइटर कहते हैं. एलिस मुनरो कनाडा की पहली कथाकार हैं, जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है. इसके पहले कनाडा मूल के साउल बेलो को उन्नीस सौ छिहत्तर में नोबेल पुरस्कार मिला था, लेकिन वो बचपन में ही अमेरिका में जा बसे थे. नोबेल पुरस्कार के इतिहास में बहुत कम बार ही कथाकार को साहित्य के लिए पुरस्कृत किया गया है. यह मुनरो की कहानियों की ताक़त ही है जिसने नोबेल पुरस्कार समिति के सदस्यों को उन्हें चुनने के लिए बाध्य कर दिया. अपनी बीमारी की वजह से ख़ुद पुरस्कार लेने नहीं जा

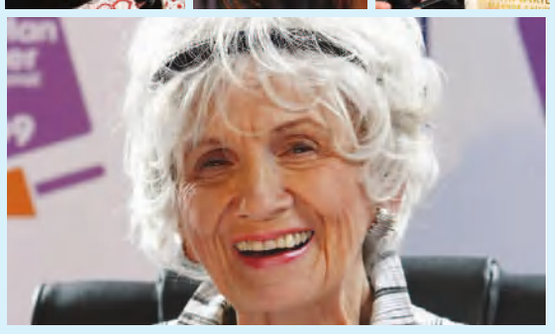

अंग्रेज़ी लेखन में महिलाओं के इस दबदबे के बीच साहित्य के लिए इस वर्ष को नोबेल पुरस्कार कनाडा की बयासी साल की वयोवृद्ध लेखिका एलिस मुनरो को दिया गया. मुनरो को पुरस्कार मिलने के बाद अंग्रेज़ी में हो रहे महिला लेखन पर एक बार फिर से सबकी नज़र चली गई.

पाई एलिस मुनरो ने एक बयान जारी कर कहा कि उनको नोबेल पुरस्कार मिलने के बाद कहानी एक विधा के तौर पर और मज़बूत होगी. किसान परिवार में उन्नीस सौ इकतीस में जन्मी एलिस मुनरो ने साठ के दशक के एकदम शुरुआत से लिखना शुरू किया था. मुनरो ने माना है कि जब उन्होंने लिखना शुरू किया तो कनाडा में बहुत कम लेखक थे और विश्व साहित्य में उनकी उपस्थिति लगभग नगण्य थी. उनके घर का माहौल साहित्यिक था और उनके पिता की साहित्य में गहरी अभिरुचि थी. एलिस एनी लेडलॉ ने पहली कहानी– द डायमेन्शंस ऑफ शैडो–उन्नीस सौ पचास में लिखी. तब वो पत्रकारिता की पढ़ाई कर रही थीं. पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही अपने एक सहकर्मी जेम्स मुनरो से इश्क होता है और वो दोनों शादी रचा लेते हैं. शादी के बाद एलिस मुनरो के तीन बच्चे होते हैं और वो पूरी तरह से एक गृहिणी का दायित्व निभाने लगती हैं. एलिस मुनरो ने माना है कि उस दौर में वो अपने परिवार में मशगूल हो गई थीं और नहीं लिख पाने की वजह से वो डिप्रेशन का भी शिकार हुईं. पारिवारिक चक्रव्यूह में वो इतना उलझ गईं कि उनसे एक शब्द नहीं लिखा जाने लगा. पारिवारिक उलझनों और ज़िम्मेदारियों में डूबी एलिस मुनरो के लिए उसकी किताब की दुकान वरदान साबित हुई. उन्नीस सौ अड़सठ में एलिस मुनरो ने अपने पति जेम्स के साथ मिलकर एक किताब की दुकान–मुनरो बुक्स–खोली, जो अब भी विक्टोरिया इलाक़े में मौजूद है. उस दुकान के ग्राहकों से बात करते हुए एलिस मुनरो में फिर से लेखन की इच्छा जाग्रत होने लगी. नतीजा यह हुआ कि उन्नीस सौ अड़सठ में उनका पहला संग्रह– डांस ऑफ द हैप्पी शेड्स–प्रकाशित हुआ. इस दौर में एलिस मुनरो की कहानियां नियमित रूप से न्यूयॉर्कर समेत तमाम प्रतिष्ठित पत्र–पत्रिकाओं में छपने लगी थीं. पहले संग्रह के प्रकाशन से ही एलिस मुनरो को कनाडा में पहचान मिली और उस किताब पर ही उनको वहां के प्रतिष्ठित साहित्यि के गवर्नर जनरल पुरस्कार से नवाजा गया. एलिस मुनरो की एक और लंबी कहानी है–द बीयर कम ओवर द माउंटेन. यह कहानी एक ऐसी महिला की है जो अपनी याददाश्त खोने लगती है और अपने पति की इस बात से सहमत होती है कि उसको अस्पताल में भर्ती हो जाना चाहिए. कहानी जैसे–जैसे आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि औरत का पति विवाहेत्तर संबध बनाता रहा है और उसे इसका अफसोस भी नहीं है. इन्हीं हालत के बीच अस्पताल में भर्ती उस औरत को एक शख़्स से प्यार हो जाता है और वो उसमें सुकून तलाशने लगती है.

इनकी कहानियों में साठ के दशक में कनाडा और अमेरिका का उथल–पुथल और उस दौर में वहां रहने वाली लड़कियों के मनोविज्ञान का चित्रण है. एलिस मुनरो की क़िस्सागोई में यथार्थ और अनुभव का बेहतरीन सम्मिश्रण होता है जो उनकी कहानियों को पठनीय तो बनाता ही है, पाठकों को एक नई तरह की अनुभूति से भी भर देता है. एलिस मुनरो की कहानियों में ग्रामीण जीवन और क्षेत्रीय परिवेश मुख्य रूप से उभरकर सामने आता है. मुनरो की कहानियों में कथानक से ज़्यादा घटनाएं और स्थितियां उभर कर आती हैं और पाठकों को चौंकाती हैं. बहुधा एलिस मुनरो की तुलना महान कथाकार एंटन चेखव से भी की जाती है. अपनी कहानियों की वजह से एलिस मुनरो को समकालीन कथा साहित्य में इस विधा के प्रतिनिधि कथाकार का दर्जा हासिल है. मुनरो की अब तक दर्जनभर से ज़्यादा कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं. अमेरिका और कनाडा में उनकी किताबें लाखों में बिकती हैं. नोबेल पुरस्कार मिलने के बाद कई भाषाओं में उनकी रचनाओं का अनुवाद होगा और अन्य भाषा के पाठकों को उनकी रचनाओं से परिचित होने का मौका मिलेगा. एलिस मुनरो को समझने के लिए दो हज़ार दो में छपी उनकी बेटी की किताब अहम है. उनकी बेटी साइला मुनरो ने लाइव्ज ऑफ मदर्स एंड डॉटर्स: ग्रोइंग अप विद एलिस मुनरो लिखी है. इस किताब में उनकी बेटी ने मुनरो के संघर्ष और एक कहानीकार बनने पर विस्तार से लिखा है. इस किताब को पढ़कर मुनरो की कहानियों के विषयों को समझने में मदद मिलती है. हमें यह उम्मीद की जानी चाहिए कि हिंदी का भी कोई प्रकाशक एलिस मुनरो की कहानियां छापने का उद्यम करेगा, ताकि हिंदी के विशाल पाठक वर्ग को भी उनकी कहानियों से परिचित होने का मौका मिल सके. ■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं.)
anant.ibn@gmail.com

कविता

बंजर रिश्ते

पंकज द्विजेंद्र

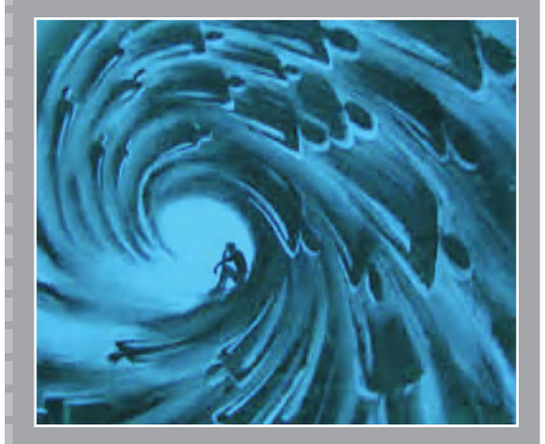

गुमसुम लब और पत्थर चेहरे
लगता है सब बोल चुके हम
या शायद इन सब रिश्तों की
सारी गांठें, खोल चुके हम
एक ख़लिश है, एक ख़ला है
जाने कैसा दर्द पला है
गर्म हवा की टीक दुपहरी
द्वार बंद थे, खोल चुके हम
मेरे सेहन में सुबह-सुबह
इक पत्थर किसने फेंका है
तेरे घर पर भी मैंने इक
निशां लहू का देखा है
बंजर रिश्ते, खंडहर नाते
क़ब्रगाह सा शहर हुआ
नफ़रत के बाज़ार में जैसे
दिल के रिश्ते तोल चुके हम
बचा नहीं कोई बाग़ीचा
फिर ख़ुशबू किसकी आती है
कौन है पगली जंगल में जो
एक तराना गाती है
मत गा तेरे सुर के पीछे
कितने नश्तर लगे हुए हैं
मधुशाला की राह बताते
मील के पत्थर थके हुए हैं
किससे अपनी बात कहें और
किसके घर तक जाएं हम
ऊंचे महलों की बस्ती में
कच्चे घर सब डोल चुके हैं
गुमसुम लब और पत्थर चेहरे
लगता है सब बोल चुके हम
या शायद इन सब रिश्तों की
जितनी गांठें थीं, खोल चुके हम.

किताब मिली

पुस्तक	लेखक
यूं ना होता तो क्या होता	रवि बुले
प्रकाशक	**मूल्य**
हार्परकॉलिंस	199

पत्रकार रवि बुले का यह कहानी संग्रह ख़ामोश बहते तिनके की तरह लगता है. वे अत्यधिक कला संयत, सफल गद्य रचयिता कथाकार हैं जबकि बहुतेरे बाज़ार की शरण में चले गए हैं. वे अपने लैंडस्केप में धीमा बदलाव कर रहे हैं. शांत कौशल, सहानुभूतिपूर्ण बुद्धिमत्ता, कलात्मक संगठन बुले के मौलिक गुण हैं. वह सम्पादक समूहों के कथाकार नहीं है, उनसे स्वतंत्र है. उनकी चाल ठोस, मंथर और घेरती हुई है. रवि बुले उत्तर आधुनिक होड़ में नहीं हैं, वे कहानी की वास्तविक होड़ में हैं. पाठकों को इस कहानी संग्रह में कुछ नई तरह की कहानियां पढ़ने को मिलेंगी.

लेखक और प्रकाशक इस कॉलम के लिए अपनी किताबें हमें भेज सकते हैं.
चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301
ई–मेल: feedback@chauthiduniya.com

पुस्तक चर्चा

सामाजिक विसंगतियों का धर्मक्षेत्र

तबस्सुम जहां

वर्तमान समय में हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है. आगे बढ़ने की इच्छा में वह कितना हासिल करेगा और कितना कुछ गवां देगा, इन सब के बारे में विश्लेषण करने का उसके पास समय नहीं है. आगे बढ़ने की इस प्रक्रिया में प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को धक्का देकर आगे निकल जाना चाहता है. इस पूरी प्रक्रिया में ग़रीब व्यक्ति ही सबसे अधिक धक्के खाने पर विवश है. चाहे वह व्यक्ति रूप में हो या समष्टि के रूप में, उसे किसी गतिशील व्यक्तित्व या समुदाय का ज़ोरदार धक्का खाना ही है और उसे सहन करने पर विवश होना ही है. ग़रीब व्यक्ति विद्रोह नहीं कर सकता, क्योंकि व्यवस्था ने उसे इतना कमज़ोर और लाचार कर दिया है कि वह विद्रोह करने के बारे में सोच ही नहीं सकता. यदि कुछ जीवट प्रकृति के लोग विद्रोह करते भी हैं तो उन्हें साम–दाम–दंड–भेद की नीति द्वारा दमन का शिकार होना पड़ता है.

राजकुमार राकेश कृत धर्मक्षेत्र उपन्यास में इन्हीं सामाजिक सच्चाइयों व विसंगतियों का चित्रण किया गया है. कालाबकरा के लोग इसी गतिशील व्यक्ति के दमन का शिकार होते हैं. ऐसा नहीं है कि यहां लोग अन्याय के खिलाफ लड़ाई में सर उठाना नहीं जानते, लेकिन इसके उपरांत भी लड़ाई में जीत अन्याय करने वालों की ही होती है. उपन्यास की नायिका रश्मि पंडित, जिसका समस्त जीवन बचपन से त्रासदी और विसंगतियों में बीता है, वह समाज की इस व्यवस्था से जूझते–जूझते बाद में स्वयं इस व्यवस्था का ही एक अंग बन जाती है.

धर्मक्षेत्र में एक तरह का द्वन्द विद्यमान है. ऐसा कहा जाए की एक तरह का अवसाद छाया हुआ है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी. मानवीय आज़ादी की बहस को दृढ़ करने वाले राजकुमार राकेश सम्पूर्ण कथा विन्यास में जिस अवसाद को महसूस करते हैं, वह इस पूरे उपन्यास में छाया हुआ है. प्रश्न ये है कि वर्तमान समय में आज जबकि सभी अपने–अपने भरोसे और ढंग से जीवन जीना चाहते हैं और इसी के फलस्वरूप ऊंचाइयों को भी छूना चाहते हैं, क्या ये मानव की सभ्यतागत आजादी का परिचायक है? उपन्यास की नायिका रश्मि पंडित इसी स्वतन्त्र मानव के रूप में इस उपन्यास में दृष्टिगोचर होती है. लेकिन क्या वह स्वयं एक पूरे समुदाय को गुलाम बनाकर रखना नहीं चाहती. यदि मानवीय स्वतंत्रता की बात करें तो एक सम्पूर्ण स्वतन्त्र मनुष्य भी किसी न किसी को अपना गुलाम बनाए रखना चाहता है. वर्तमान समय में जिस वर्चस्व की लड़ाई हम समाज में देख रहे हैं, वही लड़ाई इस उपन्यास के कथा केंद्र में है. सत्ताधारी लोगों की क्रूरतम व्यवस्था के आगे यदि जनसामान्य नतमस्तक होता है तो इसका कारण उसे मानसिक रूप से लाचार बना देना है. स्वयं लेखक के शब्दों में–भाग्य होता है अशिक्षित और अज्ञानी वो तय करता है भविष्य एक पूरी कौम का.

पुस्तक – धर्मक्षेत्र
लेखक – राजकुमार राकेश
प्रकाशन – पंचकूला प्रकाशन
मूल्य – 350 रुपये

धर्मक्षेत्र उपन्यास में कई पात्र इस लचर मानदंड के निर्मित माने जा सकते हैं. उनका शिक्षित पाठक वर्ग इस कथा के पात्र के साथ कहां तक न्याय कर पाते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा. वैसे लेखक ने अपने उपन्यास में कई चरित्रों को समेटने का प्रयास किया है, लेकिन उनका तर्क इन चरित्रों के लिए कमज़ोर सा प्रतीत होता है. लेखक के भाषा का जीवंत प्रवाह उपन्यास को जटिलताओं से निकालने में सफल हो सका है. जैसे–कई औपचारिकताओं को निभा चुकने के बाद जब भीड़ छंटी तो ही वसुंधरा अपनी मां और मौसी के साथ उस मृतात्मा को याद करने के लिए बैठी थी. तब तक जीवन अपनी गति पकड़ने के लिए ललकार रहा था. मन को स्थिर करने में ज़रूरी वक़्त लगा था और इसी बीच उस झूले के बीच प्रस्तुत मौत का वह आतंक लौट आया था.

उपन्यास में लेखक भाषाई प्रवाह और वेग को बनाने में पूरी तरह सफल हुए हैं. इस भूमंडलीकरण और बाज़ारवाद के दौर में व्यक्ति को मानसिक तौर पर इस तरह तैयार किया जाता है कि उसकी ज़रूरतें कम होने का नाम ही नहीं ले रहीं. कुमार बहुलस्व के शब्दों में–बढ़ते बाज़ारवाद ने एक ओर जहां मानवीय जीवन को सुविधाओं से लैस किया है, वहीं दूसरी ओर मानवीय मूल्यों के निरंतर पतन के लिए प्रोत्साहित भी किया है. धर्मक्षेत्र की सबसे सशक्त पात्र मोहतरमा रश्मि पंडित इसी बाज़ारवाद की परिणति हैं. गौर से देखा जाए तो गिरते मानव मूल्य ने व्यक्ति को विभिन्न हथकंडे अपनाने पर विवश किया है. इसी के फलस्वरूप गांव, क़स्बा, नगर या महानगर में हृदयहीनता पैदा होने लगी है, जिसकी तरफ लेखक ने पाठकों का ध्यान आकर्षित कराया है.

धर्मक्षेत्र उपन्यास में राजनीतिक दांव–पेच का प्रस्तुतीकरण विचारणीय है. कांड को कुकांड बनाकर जो खबरें मीडिया द्वारा लोगों तक पहुंचाई जाती हैं, वे केवल निराशाजनक संदेश ही नहीं, अपितु व्यक्ति को हृदयहीन बनने पर भी उकसाती हैं. इन सब बातों के पीछे किसी न किसी रूप में राजनीति समाहित होती है. मानवीय आज़ादी के जिस आयाम की ओर लेखक इंगित करने का प्रयास करता है वह तब तक सफल नहीं हो सकता, जब तक हम स्वयं को इस ढांचे से मुक्त न कर लें.

इस प्रकार संक्षेप में कहा जा सकता है कि धर्मक्षेत्र उपन्यास में राजनीतिक दांव–पेच, बाज़ारीकरण, मीडिया की भूमिका, गिरते मानव–मूल्य से जूझते लोगों व सामाजिक विसंगतियों का चित्रण किया गया है. कहीं–कहीं उपन्यास की भाषा बौद्धिकता से परिपूर्ण है, जो कि तार्किकता से सोचने पर विवश करती है. उपन्यास के नायक पवनदेव करण के द्वारा ही कथा आगे बढ़ती है और विस्तार पाती है. नायक द्वारा लेखक अपने विचारों को दर्शकों के सामने रखता है जो कि सराहनीय है. राजकुमार राकेश द्वारा रचित धर्मक्षेत्र उपन्यास का प्रकाशन आधार प्रकाशन पंचकूला ने किया है, तथा आवरण चित्र भूपिन्दर बराड़ ने तैयार किया है. पुस्तक का मूल्य 350 रुपये है. ■

feedback@chauthiduniya.com

rediff News

> क्रोमकास्ट घर में लगाने के बाद आपके घर के सभी डिवाइसेज के लिए एक्सटेंशन की तरह काम करने लगेगा. यानी आप किसी भी डिवाइस पर यदि कोई मूवी या वीडियो देख रहे हों तो उसे सेकेंड्स में घर के किसी भी टीवी पर देख सकते हैं.

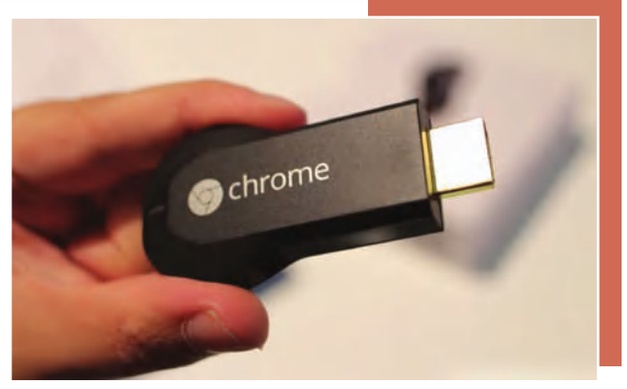

कैमरे में इंटरनेट और वाईफाई का मजा

निकॉन का यह कैमरा ब्लैक, रेड और ग्रे कलर में उपलब्ध है. यह 24.2 मेगापिक्सल का है. इसमें एक्सपीड 4 इमेज प्रोसेसिंग इंजन (इमेज चिप) लगी हुई है. इस चिप के कारण फोटो क्वालिटी काफी अच्छी आती है. खूबसूरत यादों को सहेजने के लिए यह एक बेहतर कैमरा है.

निकॉन ने अपना नया डी 5300 डीएसएलआर कैमरा लॉन्च कर दिया है. यह निकॉन का पहला डिजिटल एसएलआर कैमरा है. इस नये कैमरे में वायरलेस लैन और वाई–फाई कनेक्टिविटी के साथ जीपीएस फंक्शन भी हैं. कैमरे के जरिये इंटरनेट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है. निकॉन का यह कैमरा भारत में ब्लैक, रेड और ग्रे कलर में उपलब्ध है. यह कैमरा 24.2 मेगापिक्सल का है. इसके अलावा, एक्सपीड 4 इमेज प्रोसेसिंग इंजन (इमेज चिप) लगी हुई है. इस नये इमेज चिप के कारण यह कैमरा काफी अच्छी फोटो क्वालिटी देता है. अपनी खूबसूरत यादों को ताजा रखने के लिए यह एक बढ़िया प्रोफेशनल कैमरा साबित हो सकता है. निकॉन के नये डीएसएलआर कैमरे की मदद से पूरी तरह से एचडी रिकॉर्डिंग की जा सकती है. 1920–1080 पिक्सल के रेजोल्यूशन के साथ यह बेहतरीन वीडियो क्वालिटी भी देता है. शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है. इस कैमरे में 9 स्पेशल इफेक्ट फीचर्स हैं, जिनकी मदद से वीडियो रिकॉर्डिंग और भी अच्छी तरह से की जा सकती है. फोटो खींच कर डिवाइस के जरिये तुरंत इसे ट्रांसफर भी किया जा सकता है. यानी फोटो खींचते ही बिना किसी झंझट के तुरंत इंटरनेट पर फोटोज डाली जा सकती हैं. इससे 9 अलग–अलग तरह के स्पेशल इफेक्ट यूजर्स को शानदार फोटो क्वालिटी देते हैं. साथ ही बेहतरीन वीडियो भी बनाए जा सकते हैं. इसमें 3.5 इंच की एससीडी डिस्प्ले स्क्रीन है. इसके अलावा, नये निकॉन कैमरे के साथ कई तरह के लेंस लगाए जा सकते हैं. इसकी कीमत है 54450 रुपये. इसके साथ 18–55 एमएम का लेंस लेने पर कीमत 59950 रुपये होगी और 18–140 एमएम का लेंस लेने पर कीमत 75950 रुपये हो जाएगी. ■

बजाज की नई डिस्कवर

बढ़ते पेट्रोल की परेशानी से निजात देने के लिए ऑटो निर्माता कंपनी बजाज ने नई डिस्कवर 100 एम2 लॉन्च की है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह एक लीटर पेट्रोल में 84 किमी तक का सफर तय कर सकती है. यह बिल्कुल नये रूप–रंग में उतारी गई है, जो कि हीरो मोटोकार्प पैशन, स्प्लेंडर की श्रेणियों की बाइक को तगड़ी टक्कर देगी. बजाज ऑटो के प्रेसिडेंट (मोटरसाइकल बिजनेस) के श्रीनिवास ने कहा कि माइलेज बढ़ाने के लिए बाइक के पॉवर से कोई समझौता नहीं किया गया है. यानी बाइक बेहतर माइलेज के साथ बेहतर पॉवर देगी. इसमें ट्विन स्पार्क 4 वॉल्व 102 सीसी डीटीएस–आई इंजन का इस्तेमाल किया गया है. इसीलिए यह बेहतर माइलेज के साथ बाइक को जबरदस्त पॉवर भी देता है. इसकी टॉप स्पीड 95 किमी/घंटा तक रहेगी. इसमें 4 स्पीड गियर बॉक्स है. नई डिस्कवर नये कलर ऑप्शन में मिलेगी. इनमें फ्लेम रेड, ब्रिलिएंट ब्लू, मिडनाइट ब्लैक हैं.

कंपनी के मुताबिक, यह बाइक अपनी श्रेणी की अन्य बाइक्स के मुकाबले 25 प्रतिशत ज्यादा पॉवर देगी. इसमें फंट्र डिस्क ब्रेक का ऑप्शन भी है. इलेक्ट्रिक स्टार्ट दिया गया है. डिस्कवर 6 अलग–अलग वैरिएंट में मौजूद है. 100, 100 एम, 100टी, 125, 125 एसटी और 125 टी. नई डिस्कवर 100 एम2 की कीमत है 45,9, 96 रुपये. ■

गूगल क्रोमकास्ट टीवी देखना हुआ मजेदार

एक बार क्रोमकास्ट घर में लगाने के बाद आपके घर के सभी डिवाइसेज के लिए यह एक्सटेंशन की तरह काम करने लगेगा. यानी आप किसी भी डिवाइस पर यदि कोई मूवी या वीडियो देख रहे हों तो उसे तत्काल सेकेंड्स में किसी भी टीवी पर देख सकते हैं. क्रोमकास्ट की खूबी यह है कि यह लगाने में बेहद आसान, इंटरनेट से भी तेज और इस्तेमाल करने में पूरी तरह सुरक्षित है.

क्रोमकास्ट एक पेन ड्राइव जैसा छोटा सा डिवाइस है. इसकी सहायता से आपके टीवी पर यूट्यूब और अन्य वीडियो साइट्स को आसानी से देखा जा सकता है. आपके टीवी के साथ क्रोमकास्ट जुड़ा है तो आप अपने किसी भी गैजेट जैसे कंप्यूटर, फोन टैबलेट पर यूट्यूब लोड कर इसे टीवी पर देख सकते हैं. असल में एक बार क्रोमकास्ट घर में लगाने के बाद यह आपके घर के सभी डिवाइसेज के लिए एक्सटेंशन की तरह काम करने लगेगा. यानी आप किसी भी डिवाइस पर यदि कोई मूवी या वीडियो देख रहे हों तो उसे तत्काल सेकेंड्स में अपने टीवी पर देख सकते है. क्रोमकास्ट की खूबी यह है कि यह लगाने में बेहद आसान, इंटरनेट से भी तेज और इस्तेमाल करने में पूरी तरह सुरक्षित है. अभी टीवी पर यूट्यूब या अन्य वीडियो की स्ट्रीमिंग के लिए चार–पांच स्टेप्स से गुजरना पड़ता है. इसमें समय भी काफी लगता है. क्रोमकास्ट में ऐसे स्टेप्स बहुत कम होते हैं और यह काफी तेजी से ऑन हो जाता है. अगर आपके टीवी के साथ क्रोमकास्ट जुड़ा है तो आप अपने किसी भी गैजेट जैसे कंप्यूटर, फोन टैबलेट पर यूट्यूब लोड कर इसको टीवी पर देख सकते हैं. सेट टॉप बॉक्स के मुकाबले इन डिवाइसेज पर यूट्यूब को नेविगेट करना आसान होता है, इसलिए आपको तेजी से इस सुविधा का फायदा मिल जाता है. यही नहीं, अगर आपके पास कई टीवी हैं तो आपको अपने टीवी इनपुट को भी बदलने की जरूरत नहीं होगी. क्रोमकास्ट यह काम खुद ही कर लेगा. क्रोमकास्ट घर में लगाने के बाद यह पूरे घर के सभी डिवाइसेज के लिए एक्सटेंशन की तरह काम करने लगेगा. ■

आ गया छोटा और सस्ता फुल एचडी 3डी टीवी

एचडी 3डी टीवी की चाहत रखने वालों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंपनी एओसी ने भारत का सबसे छोटा फुल एचडी 3डी टीवी लॉन्च किया है, जिसकी कीमत है मात्र 19990 रुपये. 23 इंच के इस 3डी टीवी में कई एडवांस फीचर्स दिए गए हैं. इसके रिमोट में डायरेक्ट 3डी की दी गई है. इसकी मदद से आप 2डी कंटेंट को भी 3डी इफेक्ट के साथ देख सकते हैं.

एचडी 3डी टीवी लेना तो सभी चाहते हैं, लेकिन काफी बड़े साइज और अधिक कीमत के चलते लोग इसे ले नहीं पाते, पर इसके लिए अब आपको अपना मन मारना नहीं पड़ेगा. इलेक्ट्रॉनिक कंपनी एओसी ने भारत का सबसे छोटा फुल एचडी 3डी टीवी लॉन्च किया है. 23 इंच के फुल एचडी 3डी एलईडी रेजर टीवी की कीमत है 19990 रुपये. 23 इंच के इस 3डी टीवी में कई एडवांस फीचर्स दिए गए हैं.

इसके रिमोट में डायरेक्ट 3डी की दी गई है. इसकी मदद से आप 2डी कंटेंट को भी 3डी इफेक्ट के साथ देख सकते हैं. यानी टीवी के साथ आपको अन्य किसी भी प्रकार के उपकरण की आवश्यकता नहीं होगी, जो कि 2डी को 3डी में बदल सके. टीवी ड्रीम सराउंड साउंड से लैस है. इसलिए जब भी आप इस पर कोई प्रोग्राम देखेंगे, आपको न सिर्फ बेहतर बेस मिलेगा, बल्कि डायलॉग भी स्पष्ट सुनाई देंगे. इसमें यूएसबी, एचडीएमआई और वीजीए पोर्ट दिया गया है. इसे आप अपने पीसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं. कंपनी की ओर से टीवी लेने पर आपको 2 सालों की वारंटी भी दी जाएगी. इस टीवी से आपकी बिजली की बचत भी होगी. कंपनी का दावा है कि यह 40 वॉट तक पॉवर की खपत करेगा. इसका वजन अन्य टीवीज के मुकाबले काफी कम, मात्र 3.6 किलो है.■

रेडिफ न्यूज एप पर फ्री न्यूज

रेडिफ डॉट कॉम इंडिया लिमिटेड ने अपनी रेडिफन्यूज एप सर्विस के विस्तार की घोषणा की है. इसके माध्यम से अब 30,000 से ज्यादा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्रोतों की खबरें फ्री उपलब्ध कराई जाएंगी. इसके लिए आपको केवल रेडिफ न्यूज एप को डाउनलोड करना होगा. रेडिफ डॉट कॉम के समाचारों के अलावा, यह नया एप कई अन्य समाचार स्रोतों से भी खबरें उपलब्ध कराएगा. इनमें रॉयटर्स, द न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, द टाइम्स ऑफ इंडिया, दि इकनॉमिक टाइम्स तथा द हिंदू जैसे नेटवर्क भी शामिल हैं. रेडिफ ने विभिन्न मोबाइल डिवाइसेज के लिए इस एप के मल्टीपल वर्जन पेश किए हैं. ये वर्जन

रेडिफ न्यूज एप सर्विस के साथ रॉयटर्स, द न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, द टाइम्स ऑफ इंडिया, दि इकनॉमिक टाइम्स तथा द हिंदू जैसे नेटवर्क भी शामिल हैं. इसके माध्यम से 30,000 से ज्यादा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्रोतों की खबरें फ्री उपलब्ध कराई जाएंगी. इसके लिए आपको केवल रेडिफ न्यूज एप को डाउनलोड करना होगा.

rediff News

अत्याधुनिक आईओएस, ब्लैकबैरी, विन्डोज तथा एन्ड्रॉयड जैसे उपकरणों के लिए तथा उन फोन के लिए पेश किए गए हैं, जिनमें क्लासिकल जावा एवं सिंबियन ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स मौजूद हैं.

हर एक वर्जन को यह ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है, ताकि उपभोक्ता अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पर इससे सर्वश्रेष्ठ अनुभव प्राप्त कर सकें. इसके माध्यम से कई स्रोतों से उपभोक्ता को समाचार सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. रेडिफ डॉट कॉम इंडिया ने बताया कि अत्याधुनिक टाइल्ड इंटरफेस डिजाइन इमेज के साथ यह एप यूजर को सभी प्रकार की खबरों के साथ अपडेट करता है. दुनिया, कारोबार, खेल, क्रिकेट एवं मनोरंजन से जुड़े सभी क्षेत्रों से संबंधित खबरें संक्षिप्त विवरण के साथ आपके लिए उपलब्ध कराई जाती हैं. यूजर समाचार के सारांश को जानने के लिए इमेज पर टैप कर सकता है, जिससे मूल स्रोत के साथ ही पूरी खबर इसके सामने खुल जाती है. यह सर्च फंक्शन इश्तेमाल में बेहद आसान है. बार–बार रीफ्रेश करने के लिए डिफाल्ट मैनुअल सेटिंग को जरूरत के अनुसार इसे बदल भी सकते हैं. आल्सो रीड फीचर की मदद से आप अपनी रुचि के विषय पर ज्यादा से ज्यादा जानकारी सर्च कर सकते हैं.

यह एप पहले से डाउनलोड की जा चुकी समाचार सामग्री को ऑफलाइन भी उपलब्ध कराता है, चाहे यूजर इंटरनेट से कनेक्टेड न हो तो भी. रेडिफ डॉट कॉम के चेयरमैन एवं सीईओ अजीत बालाकृष्णन के मुताबिक, आने वाले समय में भारतीय मोबाइल इंटरनेट यूजर बेस के तेजी से बढ़ने की की संभावना हैं, क्योंकि सरकार और कई शीर्ष टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर इस पर फोकस कर रहे हैं. ऐसे में हमारी ओर से रेडिफन्यूज एप का लॉन्च दुनिया में सभी यूजर को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराएगा. यूजर इसके सर्च फंक्शन की मदद से समाचारों को विस्तार से जान सकेंगे. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

सोनी का नया फोन

सोनी एक्सपीरिया सी में मल्टीमीडिया के लिए 8 मेगापिक्सल का मुख्य कैमरा दिया गया है, जिसमें फेस डिटेक्शन और स्वीप पैनोरमा जैसे फीचर्स शामिल किए गए हैं.

सोनी ने अपना नया स्मार्टफोन एक्सपीरिया सी लॉन्च कर दिया है. यह स्मार्टफोन सोनी के ओमनी बैलेंस डिज़ाइन पर बना है, जिसका इस्तेमाल एक्सपीरिया जेड में किया गया है. एक्सपीरिया सी 1.2 गीगाहर्ट्ज क्वॉड–कोर मीडियाटेक प्रोसेसर, 1 जीबी रैम और 4 जीबी इंटरनल स्टोरेज के साथ काम करता है. माइक्रो–एसडी कार्ड के जरिये मेमोरी को और 32 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है. इसमें 5 इंच का टीएफटी एलसीडी क्यू–एचडी डिस्प्ले है. यह एंड्रॉयड 4.2 जेली बीन पर चलता है. मल्टीमीडिया के लिए 8 मेगापिक्सल मुख्य कैमरा दिया गया है, जिसमें फेस डिटेक्शन और स्वीप पैनोरमा जैसे फीचर्स शामिल किए गए हैं. यह 1080 पी फुल–एचडी विडियो रिकॉर्ड कर सकता है. इसमें 0.3 मेगापिक्सल्स फ्रंट कैमरा भी है. इसमें मोशन गेमिंग, आरडीएस के साथ एफएम रेडियो, वॉकमैन ऐप और स्क्रीन मिररिंग जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं. बैटरी 2330 एमएएच की है. इस स्मार्टफोन की कीमत 21,490 रुपये है. ■

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

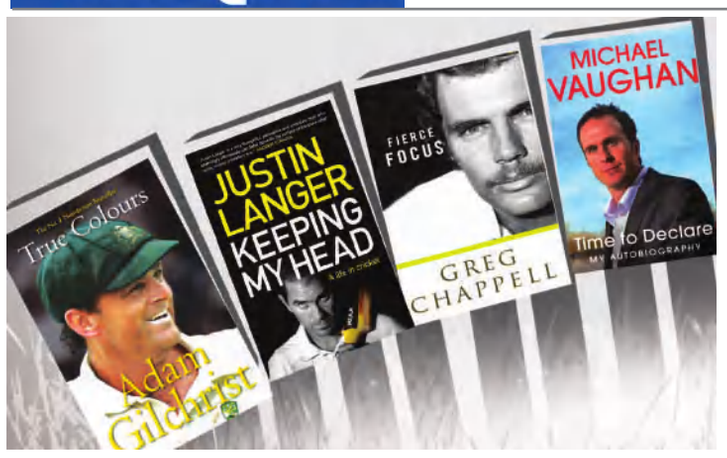

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व प्रारंभिक बल्लेबाज हर्शल गिब्स ने आत्मकथा टू द प्वॉइंट में अपनी टीम के खिलाड़ियों और अधिकारियों पर बहुत से गंभीर आरोप लगाए थे. गिब्स ने उसमें अपने निजी जीवन के बारे में कई बेबाक और सनसनीखेज खुलासे किए थे. इसके साथ ही उन्होंने अपने साथी खिलाड़ियों के निजी जीवन के बारे में टिप्पणियां कर क्रिकेट जगत में बवाल मचा दिया था.

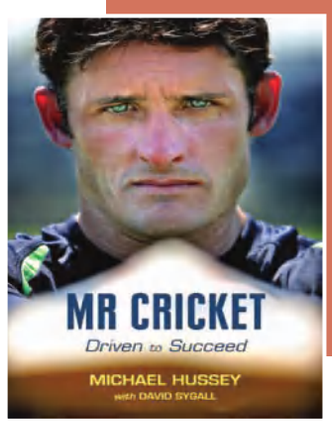

विवादों की आत्मकथाएं

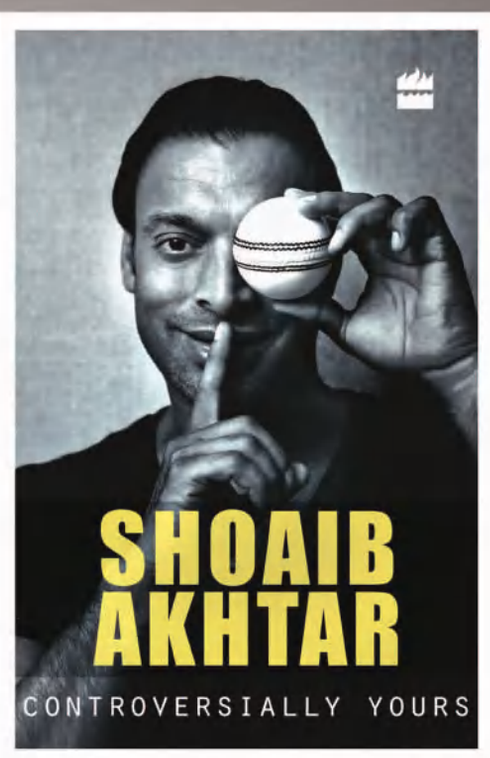

क्या आत्मकथाएं प्राय: विवादों का पुलिंदा होती हैं? आजकल छप रहीं आत्मकथाओं में विवादों को जगह मिलती ही है या कहें कि प्रकाशक उन्हीं आत्मकथाओं को छापने और ऊंची से ऊंची कीमत देने के लिए तैयार होते हैं , जिनमें विवादों को पर्याप्त जगह मिली हो. अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के साथ अवैध संबंध रखने वाली मोनिका लेवेंस्की की आत्मकथा को छापने के लिए हजारों पब्लिशर तैयार थे. यह असर खिलाड़ियों की आत्मकथाओं में भी दिखाई देता है. इसलिए विवादित प्रकरण इस दौर में लिखी जाने वाली आत्मकथाओं का मुख्य हिस्सा बन गए हैं. इसे मार्केटिंग स्ट्रैटजी कहा जाए या कुछ और, लेकिन इससे आत्मकथाओं की विश्वसनीयता पर सवाल तो जरूर खड़ा होता है.

नवीन चौहान

आत्मकथा का मतलब होता है लिखने वाले की अपनी वह कहानी जो अब तक अनकही है, जिसमें अनायास ही इर्द-गिर्द रहने वाले लोग शामिल हो जाते हैं. आत्मकथा लिखने वाले व्यक्ति के आत्मकथा में लेखक एक तरफ तो अपने जीवन का आकलन करता है, लेकिन दूसरी तरफ उनके जीवन में घटित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का अपने नजरिये से उल्लेख करता है, लेकिन सामान्य तौर पर किसी सेलिब्रिटी या कहें कि विशिष्ट व्यक्ति की आत्मकथा में विवादों का पुट आवश्यक रूप से होता है. वे अपनी आत्मकथाओं में उन घटनाओं का जिक्र जरूर करते हैं. विशिष्ट लोगों की किसी विवादित मुद्दे पर राय जानने में लोगों की विशेष रुचि होती है. इन्हीं विवादों की वजह से बाजार में किताबों की मांग होती है. गांधीजी ने अपनी आत्मकथा माइ एक्स-पेरीमेंट विद ट्रुथ में अपनी कमजोरियों या कहें उन पहलुओं का जिक्र किया है, जिनपर सामान्य तौर पर कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता है, लेकिन आजकल लिखी जाने वाली आत्मकथाओं, खासकर खिलाड़ियों द्वारा लिखी जाने वाली आत्मकथाओं में विवादों का पुट कुछ ज्यादा ही नजर आता है.

आजकल पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट कप्तान रिकी पोंटिंग की आत्मकथा एट द क्लोज ऑफ प्ले सुर्खियों में है. सुर्खियों का कारण पोंटिंग की लेखन शैली या क्रिकेट के भविष्य को लेकर प्रकट किए गए उनके विचार नहीं हैं, बल्कि 2007-08 में भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान उपजे मंकीगेट प्रकरण पर सचिन तेंदुलकर की भूमिका है. इस प्रकरण में हरभजन सिंह पर ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर एंड्रयू सायमंड्स के ऊपर नस्लभेदी टिप्पणी करने का आरोप लगा था. हरभजन पर आरोप था कि उन्होंने सायमंड्स को मंकी (बंदर) कहकर पुकारा था. इस प्रकरण पर पोंटिंग ने लिखा है कि मैच रेफरी माइक प्रॉक्टर के समक्ष इस मामले की सुनवाई के दौरान सचिन ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन आईसीसी द्वारा नियुक्त न्यूजीलैंड के जज जॉन हेनसन के सामने सुनवाई के दौरान सचिन ने हरभजन द्वारा हिन्दी भाषा में कुछ कहने वाला बयान दिया था. मेरी समझ में यह नहीं आया कि सचिन ने सुनवाई के दौरान हरभजन का साथ क्यों दिया? वह मैच रेफरी द्वारा हरभजन को निलंबित करने के दौरान चुप क्यों थे? इस प्रकरण के कारण भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट संबंधों के खराब होने का खतरा उत्पन्न हो गया था. भारतीय टीम द्वारा ऑस्ट्रेलियाई दौरा बीच में ही छोड़कर स्वदेश वापसी की अटकलें लगने लगीं थीं. इस बारे में पोंटिंग ने लिखा कि शायद 21वीं सदी की शुरुआत में भारतीय क्रिकेट का इतना दबदबा हो गया था कि उसे हिलाया नहीं जा सकता था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि किस तरह से खेल में कई लोगों ने हमारी मंशा पर सवाल उठाए? कैसे उन्होंने सोचा कि हम उसूलों पर काम करने की बजाय श्रृंखला में फायदा लेना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि तत्कालीन भारतीय कप्तान अनिल कुंबले के इस बयान ने ऑस्ट्रेलियाई टीम की छवि खराब कर दी कि ऑस्ट्रेलिया ने खेलभावना से नहीं खेला. कुंबले के इस बयान को काफी तवज्जो मिली. बाद में यह धारणा तेजी से बन गई कि विवाद प्रॉक्टर के निर्णय से नहीं, बल्कि हमारी वजह से पैदा हुआ. सचिन के ऊपर इस प्रकरण पर ठीक ऐसा ही आरोप पूर्व ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर-बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट ने भी आत्मकथा ट्रू कलर्स में लगाया था. गिलक्रिस्ट ने लिखा कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी खेल के मैदान पर उभरे तनावों को पीछे छोड़ आते हैं, जबकि सचिन और हरभजन सिंह जैसे भारतीय खिलाड़ी तनाव को ड्रेसिंग रूम तक ले जाते हैं. उन्होंने सचिन की ईमानदारी पर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि मंकीगेट प्रकरण के दौरान उन्होंने अपना बयान पूरी तरह बदल दिया था.

पोंटिंग की आत्मकथा में उठे सवालों के जवाब में तात्कालीक भारतीय कप्तान अनिल कुंबले ने कहा कि वह अपनी आत्मकथा में मंकीगेट विवाद की सच्चाई सामने लेकर आएंगे. इसका मतलब तो साफ है कि कुंबले भी अपनी आत्मकथा को बेस्टसेलर बनाना चाहते हैं. यदि ऐसा नहीं होता तो कुंबले उस प्रकरण से जुड़ी सारी बातों का खुलासा अभी कर सकते थे, लेकिन सच्चाई जानने के लिए लोगों को उनकी आत्मकथा के प्रकाशित होने तक इंतजार करना पड़ेगा. इस तरह कुंबले की आत्मकथा प्रकाशित होने से पहले ही सुर्खियों में आ गई है और इसके लिए बाजार भी बन गया है. देरी तो बस किताब के बाजार में आने की है.

खिलाड़ी जब तक मैदान में अपना हुनर दिखा रहा होता है, तब तक बाजार में उसकी मांग होती है, लेकिन संन्यास लेते ही लोग नये सितारे तलाश लेते हैं. अगर वो विवादों को फिर से हवा न दें तो उनकी किताबों को कुछ खेल प्रशंसकों और समीक्षकों के अलावा कोई नहीं खरीदेगा. शायद इसीलिए खिलाड़ी विवादों को हवा देने और किसी समकालिक श्रेष्ठ खिलाड़ी पर उंगली उठाने से भी नहीं चूकते. जिस तरह विवादों में रहने वाले पाकिस्तान के तेज़ गेंदबाज शोएब अख्तर ने अपनी आत्मकथा कंट्रोवर्शियली योर्स में लिखा कि सचिन तेंदुलकर उनसे डरते थे. और राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर मैच विनर्स नहीं हैं. इसके साथ ही शोएब ने यह स्वीकार किया कि वे गेंद से छेड़छाड़ करते थे. इसके अलावा भी अन्य कई मुद्दे शोएब की इस किताब में विवादास्पद थे. इस किताब के विवादों में घिरने के बाद पाकिस्तान के पूर्व कप्तान आमिर सोहेल ने कहा, देखिए, अगर कोई विवाद नहीं होता तो आत्मकथा नहीं बिकती और यह बिल्कुल साफ है कि शोएब इस बात से वाकिफ हैं. इसी तरह पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और राजनीतिज्ञ इमरान खान ने अपने कैंसर अस्पताल को पूरा करने के लिए अपनी आत्मकथा की लेखिका के समक्ष मैच के दौरान गेंद के साथ छेड़छाड़ करने की बात का खुलासा करने बहुत पैसे बटोरे थे. पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ग्रेग चैपल ने भारतीय टीम के कोच के रूप में काम करने का अनुभव अपनी आत्मकथा फियर्स फोकस में लिखा है. उन्होंने सौरव गांगुली को सिरदर्द बताकर इसे हिट बनाने की कोशिश की थी. चैपल ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि भारतीय टीम में ऐसा वर्गीकरण था कि युवा खिलाड़ी सीनियर खिलाड़ियों के सामने टीम बैठक में बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे. युवा खिलाड़ी कहते थे कि मैं उन खिलाड़ियों के सामने नहीं बोल सकता. अगर मैं सीनियर खिलाड़ी के सामने बोलूंगा तो वे हमेशा इसे मेरे खिलाफ अपने दिल में बैठा लेंगे. कुछ डरे हुए थे और उदाहरण के लिए अगर किसी बैठक में तेंदुलकर ने कुछ बोला है तो वह कुछ भी बोलने से साफ इंकार कर देते थे.

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व प्रारंभिक बल्लेबाज हर्शल गिब्स ने आत्मकथा टू द प्वॉइंट में अपनी टीम के खिलाड़ियों और अधिकारियों पर बहुत से गंभीर आरोप लगाए थे. गिब्स ने उसमें अपने निजी जीवन के बारे में कई बेबाक और सनसनीखेज खुलासे किए थे. इसके साथ ही उन्होंने अपने साथी खिलाड़ियों के निजी जीवन के बारे में टिप्पणियां कर क्रिकेट जगत में बवाल मचा दिया था. उन्होंने दक्षिण अफ्रीकी टीम के प्रदर्शन में गिरावट के लिए खिलाड़ियों द्वारा मादक पदार्थों के सेवन को जिम्मेदार ठहराया था. साथ ही गिब्स ने इस बात का भी खुलासा किया कि दिसंबर 1997 से जनवरी 1998 के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हर रात हमारे साथ महिलाएं होती थीं.

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज मैथ्यू हेडन ने अपनी आत्मकथा स्टैंडिंग माइ ग्राउंड में लिखा कि 2004 में ऑस्ट्रेलियाई टीम के भारत दौरे में नागपुर की घासवाली पिच देख गांगुली और हरभजन डर के मारे टीम से बाहर हो गए थे. हेडन ने इस बात पर भी आश्चर्य जताया है कि कैसे मैच से ठीक पहले हरभजन को फूड प्वॉइजनिंग हो गई. इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को जबरदस्त शिकस्त दी थी.

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कोच मिकी ऑर्थर ने अपनी आत्मकथा टेकिंग द मिकी-द इन साइड स्टोरी में लिखा कि मखाया एंटिनी को 2008-09 में जब उनकी खराब फॉर्म को लेकर राष्ट्रीय टीम से बाहर किया गया था, उस समय एंटिनी ने मेरे अलावा टीम के कप्तान ग्रीम स्मिथ पर नस्लभेदी होने का आरोप लगाया था. जब एंटिनी को टीम से बाहर किया गया था, उस समय टीम के सभी खिलाड़ी खासतौर पर वरिष्ठ खिलाड़ी काफी निराश थे, मैं इसलिए ज्यादा निराश था, क्योंकि मखाया प्रभावशाली प्रशासकों से यह कह रहे थे कि मैं और ग्रीम स्मिथ टीम में काले खिलाड़ियों को टीम में नहीं लेना चाहते थे.

पिछले कुछ सालों में क्रिकेट पर जितनी किताबें आई हैं, चाहे वह किसी भी क्रिकेट हस्ती द्वारा लिखी गई हों, उसमें टीम इंडिया, बीसीसीआई और भारतीय क्रिकेटर्स को पर्याप्त स्थान मिला है. इससे यह बात तो पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है कि भारत विश्व क्रिकेट की धुरी बन चुका है. भारत में जितने क्रिकेट प्रशंसक हैं, उतने दुनिया के अन्य किसी देश में नहीं हैं. इसलिए लेखक और प्रकाशक की नज़र भारत पर होती है. इसलिए क्रिकेटरों द्वारा लिखी किताबों में भारत से जुड़े विवादों का जिक्र जरूर होता है. भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व मुख्य चयनकर्ता दिलीप वेंगसरकर भी ऐसा ही मानते हैं कि क्रिकेटर्स जिस तरह अपनी किताबों में भारतीय क्रिकेटरों को निशाना बनाते हैं, वो विशुद्ध रूप से केवल मार्केटिंग फंडा के कारण ही होता है.

आत्मकथा लिखने के लिए किसी भी तरह की शैक्षणिक योग्यता का बंधन ठीक उसी तरह नहीं है, जिस तरह हमारे सांसद या विधायक बनने के लिए नहीं है. जीवन सबसे बड़ी पाठशाला है, जो अपने कटु अथवा मीठे अनुभवों से बहुत कुछ सिखा देती है. अगर जीवन के अनुभवों को पूरी ईमानदारी के साथ लोगों के समक्ष नहीं परोसा गया तो आत्मकथाओं को लोग काल्पनिक कथाओं के रूप में लेने लगेंगे, जैसा कि लांस ऑर्मस्ट्रांग ने अपनी आत्मकथा में डोपिंग के बारे में कुछ नहीं कहा. लेकिन कुछ महीने पहले उनके डोपिंग में लिप्त पाए जाने के बाद उनके सारे खिताब वापस ले लिए गए. वह एक ही पल में हीरो से जीरो हो गए.

वास्तव में कथा सबकी बनती है, लेकिन उस कथा का असल मायने तब सामने आता है, जब उसे सार्वजनिक रूप दिया जाता है. तब असली चुनौती तो यही है कि क्या बताएं और क्या छुपाएं. बताएं तो किस तरह, छुपाएं तो किस तरह. इस मुश्किल की सीमा तब और बढ़ जाती है, जब बताने और छुपाने का पैमाना पाठक नहीं, बाजार बन जा रहा है. इस हकीकत को फ्रांसीसी समाजशास्त्री लियोटार्ड के माध्यम से और बेहतर समझा जा सकता है, जब वे कहते हैं कि बाजारीकरण उत्तर आधुनिक समाज की वह हकीकत है, जिसमें विवाद बिकता है, सवांद नहीं.■

navinchauhan@chauthiduniya.com

पोंटिंग की आत्मकथा में उठे सवालों के जवाब में उस समय के भारतीय कप्तान अनिल कुंबले ने कहा कि वह अपनी आत्मकथा में मंकीगेट विवाद की सच्चाई सामने लेकर आएंगे. इसका मतलब तो साफ है कि कुंबले भी अपनी आत्मकथा को बेस्टसेलर बनाना चाहते हैं. यदि ऐसा नहीं होता तो कुंबले उस प्रकरण से जुड़ी सारी बातों का खुलासा अभी कर सकते थे, लेकिन सच्चाई जानने के लिए लोगों को उनकी आत्मकथा के प्रकाशित होने तक इंतजार करना पड़ेगा.

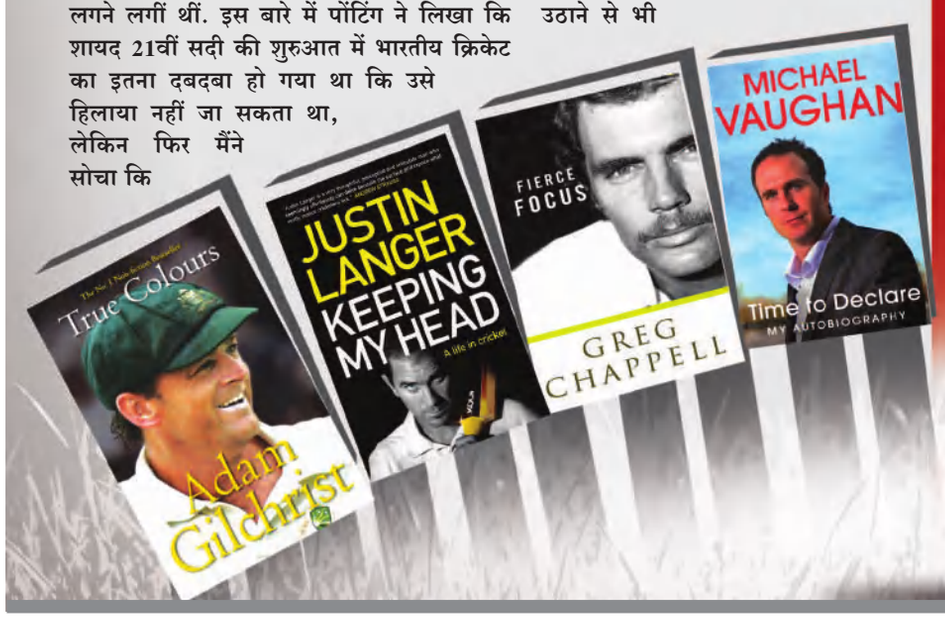

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया
जगमग दुनिया
Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467
04 नवंबर–10 नवंबर 2013

तब्बू ने प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला के साथ सगाई की, लेकिन शादी नहीं की. साजिद दिव्या भारती के पति थे और तब्बू दिव्या की काफी अच्छी दोस्त. तब्बू इस बात से बाहर नहीं निकल पा रही थीं कि वह साजिद के जीवन में दूसरी औरत हैं और वह भी उस आदमी के जीवन में, जो उनके मरहूम दोस्त का पति है. तभी उनके जीवन में नागार्जुन आए. दोनों की नजदीकियां बढ़ती गईं.

हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता

तब्बू बॉलीवुड की उन प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों में से हैं, जिन्हें जहां जगह मिली, वहीं फिट हो गईं. उन्होंने अपने करियर में कभी विजयपथ और बीवी नंबर वन जैसी कॉमर्शियल फिल्में कीं, तो कभी चांदनी बार और अस्तित्व जैसी लीक से हट कर फिल्मों में अभिनय का लोहा मनवाया.

प्रियंका तिवारी

आम बॉलीवुड अभिनेत्रियों से बेहद अलग हैं तब्बू. उनके बारे में काफी कम पढ़ने, देखने और सुनने को मिलता है. वह टेलीविजन पर कम आती हैं, मीडिया से भी दूर रहती हैं. स्वभाव से भी बेहद शांत और एकांत पसंद हैं तब्बू. विजय पथ की दिलफेंक रुक-रुक गर्ल, साजन चले ससुराल में गोविंदा की दूसरी पत्नी, माचिस में सिख बग़ावत में फंसी परेशान पंजाबी लड़की से लेकर, कई फिल्मों में संजीदा माशूका तक हर तरह के किरदार को उन्होंने इस तरह निभाया कि वह पर्दे पर जीवंत हो उठा.

फिल्मों में आदर्श प्रेमिका और पत्नी का किरदार निभाने वाली तब्बू अपने असल जीवन में इन रिश्तों से अंजान ही रहीं. 44 साल की तब्बू अब तो यहां तक कहती हैं कि डॉन्ट आस्क मी अबाउट मैरिज. हालांकि तब्बू ने शादी करनी चाही. अपनी गृहस्थी बसानी चाही, पर इसमें वह कामयाब नहीं हो पाईं. वह प्यार में तो यकीन करती हैं, लेकिन शादी को लेकर वह किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाईं. काफी लंबे समय तक वह प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला के साथ रिलेशनशिप में रहीं, लेकिन उन दोनों का रिश्ता शादी तक नहीं पहुंच पाया. दरअसल, साजिद अभिनेत्री दिव्या भारती के पति थे और तब्बू दिव्या की काफी अच्छी दोस्त थीं. उस दौरान साजिद और तब्बू दोनों ही दिव्या भारती के मौत के सदमें में थे. तभी साजिद ने अपने होम प्रोडक्शन की पहली फिल्म जीत में तब्बू को कास्ट किया. फिल्म के शूटिंग के दौरान ही दोनों करीब आए. एक इंटरव्यू के दौरान साजिद ने कहा कि यह पहली नजर का प्यार नहीं था, बल्कि एक-दूसरे के लिए फिलिंग धीरे-धीरे डेवलप हुई. दोनों का रिश्ता इतना आगे बढ़ा की उन्होंने सगाई भी कर ली. पर कहीं न कहीं, तब्बू इस बात से बाहर नहीं निकल पा रही थीं कि वह साजिद के जीवन में दूसरी औरत हैं और वह भी उस आदमी के जीवन में, जो उनके मरहूम दोस्त का पति है. यही वह समय था, जब उनके जीवन में नागार्जुन आए. दोनों की नजदीकियां बढ़ती जा रही थीं. इस बात से साजिद काफी दुखी थे. इधर, साजिद का परिवार भी नागार्जुन के साथ तब्बू के रिश्ते को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था. परिस्थितियों को देखते हुए साजिद ने अपनी मंगेतर तब्बू के साथ अपने रिश्ते को कुछ और समय दिया. उसी दौरान तब्बू नागार्जुन के साथ एक महीन के लिए अमेरिका चली गईं. इस एक महीने में तब्बू ने एक बार भी साजिद से संपर्क नहीं किया. तब्बू का सेक्रेटरी और उनका परिवार भी तब्बू का कोई कॉन्टैक्ट नंबर साजिद को उपलब्ध नहीं करा सका. इस घटना के बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया. साजिद ने शादी कर ली और आज वह खुशहाल शादीशुदा जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन आज भी तब्बू और साजिद अच्छे मित्र हैं. उधर, नागार्जुन के साथ रिश्ते में तब्बू इतना आगे बढ़ चुकी थीं कि उन्होंने निर्णय लिया कि वह हैदराबाद में ही शिफ्ट हो जाएंगी. बाद में यह भी खबरें आईं कि नागार्जुन उनके लिए सुटेबल एरिया में फ्लैट देख रहे हैं और तब्बू के लिए उन्होंने जुबली हिल्स एरिया सेलेक्ट किया है. उनके रिश्ते ने मीडिया में खुब सुर्खियां बटोरीं, जिसके बाद तब्बू वापस मुंबई शिफ्ट हो गईं.

तब्बू मानती हैं कि नागार्जुन के लिए उनकी जिंदगी में खास जगह है, लेकिन नागार्जुन उन्हें एक मुक्कमल जहां नहीं दे सकते थे. वह उनसे शादी नहीं कर सकते थे. तब्बू से लगभग 10 साल बड़े नागार्जुन की पहली शादी प्रोड्यूसर रामा नायडू की बेटी लक्ष्मी से हुई थी. उनसे डायवोर्स के बाद उन्होंने अभिनेत्री अमला से शादी की. नागार्जन और लक्ष्मी से एक बेटा नागा चैतन्य है और अमला से उन्हें एक बेटा अखिल है. तब्बू ने खुद से समझौता कर लिया. वह आज भी मन से नागार्जुन के साथ हैं. नागार्जुन तब्बू के लिए अपनी बसी-बसाई गृहस्थी नहीं तोड़ सकते थे. यह एक मूक समझौता था तब्बू के लिए, जिसमें उन्होंने अकेले ही रहना पसंद किया. हालांकि उनके इस निर्णय के पीछे एक वजह और भी हो सकता है, उनका रिश्तों पर से यकीन खत्म हो जाना. उन्होंने अपनी मां और अपनी बहन फराहा की तलाकशुदा जिंदगी देखी थी. जब वह बेहद छोटी थीं, तभी उनके पिता ने उनकी मां को तलाक दे दिया था. उनकी बहन फराहा को भी अभिनेता बिंदू दारा सिंह ने तलाक देकर दूसरी शादी कर ली थी.

तब्बू एक बेहद संवेदनशील अभिनेत्री हैं. 4 नवंबर, 1971 को जन्मी तब्बू का असली नाम तब्बसुम हासमी है. तब्बू के जन्म के कुछ समय बाद ही उनके माता-पिता अलग हो गए. उनकी मां स्कूल शिक्षिका थीं. उन्होंने शुरुआती पढ़ाई हैदराबाद में की और आगे की पढ़ाई उन्होंने सेंट जेवियर स्कूल से की. अभिनेत्री शबाना आजमी उनकी आंट हैं. मात्र 9 साल की उम्र में उन्होंने फिल्म बाजार में काम किया. 14 साल की उम्र में उन्होंने हम नौजवां में काम किया, इस फिल्म में वह देव आनंद की बेटी की भूमिका में थीं. एक अभिनेत्री के तौर पर उनकी पहली फिल्म तेलगु में कुली नंबर वन थी. इसमें उनके अपोजिट थे वेंकटेश. बोनी कपूर ने उन्हें लेकर एक फिल्म बनाई प्रेम. इस फिल्म में उनके हीरो थे संजय कपूर. उसी दौरान वह रूप की रानी और चोरों का राजा भी बना रहे थे. फिल्म के निर्माण में कुल आठ साल का समय लगा. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई. यह बोनी कपूर के करियर की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म थी. इसके बाद उन्हें दूसरी फिल्म मिलने में काफी समय लगा. उन्हें कामयाबी मिली अजय देवगन के साथ फिल्म विजय पथ से. इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट फिमेल डेब्यू अवॉर्ड भी मिला. इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा. उनकी फिल्में एक के बाद एक हिट होती गईं. उन्होंने तेलुगू, तमिल, मलयालम, मराठी, बंगला और हॉलीवुड फिल्में भी कीं. उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवॉर्ड भी मिल चुका है. हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी की, जब उन्होंने बॉलीवुड में शुरुआत किया था, तब उन्हें फिल्मकार यह कह कर भी फिल्में नहीं देते थे कि वह काफी लंबी हैं. तब्बू बिना रुके-थके आज भी फिल्मों में काम कर रही हैं. वह कहती हैं कि वह वही फिल्में करना पसंद करती हैं, जिनमें उनकी भूमिका उन्हें पसंद आती है या फिल्म की यूनिट उन्हें पसंद आती है. वह हॉलीवुड, बॉलीवुड, तमिल और बंगला फिल्मों में सक्रिय हैं. बॉलीवुड में सलमान की फिल्म मेंटल में वह सलमान की बहन की भूमिका में नजर आएंगी. गौरतलब है कि वह इससे पहले सलमान की भाभी की भूमिका में फिल्म साथ-साथ में नजर आ चुकी हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

प्रीव्यू

निर्देशक : संजय लीला भंसाली
निर्माता : किशोर लूला, संजय लीला भंसाली
आधारित : सेक्सपियर के रोमियो ऐंड जूलियट पर
कलाकार : रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, रिचा चड्ढा, सुप्रिया पाठक, बरखा बिष्ट, शरद केलकर, अभिमन्यु शेखर सिंह
म्यूजिक : संजय लीला भंसाली
डिस्ट्रीब्यूटर : इरोज इंटरनेशनल
रिलीज डेट : 15 नवंबर, 2013
भाषा : हिंदी

संजय लीला भंसाली की फिल्म रामलीला शेक्सपियर के नॉवेल रोमियो जुलियट का गुजराती वर्जन है. इस फिल्म में रणवीर सिंह राम नाम के एक गांव के एक टपोरी छाप लड़के की भूमिका में हैं. दीपिका पादुकोण गुजराती लड़की लीला की भूमिका में हैं. दोनों के बीच प्यार हो जाता है, लेकिन यह पहली नजर का प्यार नहीं है. लीला सीधी सादी लड़की नहीं है, बल्कि वह काफी बहादुर, तेज-तर्रार और न्यायप्रिय लड़की है. राम और लीला की मुलाकात छोटी-मोटी नोंकझोंक से शुरू होती है और कभी न खत्म होने वाले प्यार तक जा पंहुचती है. यहीं से दोनों के जीवन में कुछ अलग परिस्थितियां घटने लगती हैं. दोनों के प्यार में काफी बाधाएं आती हैं, लेकिन वे रामलीला के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं. माना जा

रहा है कि यह संजय लीला भंसाली की और फिल्मों से बिल्कुल अलग है. रिचा चड्ढा एक अनोखे किरदार में नजर आएंगी. रिचा के किरदार में प्यार और नफरत दोनों है. प्रियंका के आइटम सॉन्ग के अलावा इस फिल्म में कई बेहतरीन गाने भी हैं. दीपिका की भूमिका काफी हद तक हम दिल दे चुके सनम में निभाई ऐश्वर्या से मेल खाती है, लेकिन उनके रोल का यहां ट्रीटमेंट अलग किया गया है. फिल्म को गुजरात में शूट किया गया है, जबकि कुछ हिस्सा उदयपुर में भी शूट हुआ है. ■

अलविदा मन्ना डे

ज़िंदगी कैसी है पहेली

संगीत जगत ने मशहूर पार्श्वगायक मन्ना डे के रूप में अपना कोहिनूर खो दिया है. पूरब का भगवान और बंगाल के किंग जैसे नामों से नवाजे गए मन्ना डे की आवाज अमर रहेगी, क्योंकि संगीत कभी मरता नहीं, वह तो अमर है.

महान गायक मन्ना डे का असली नाम था प्रबोध चंद्र डे. मन्ना डे का जन्म 1 मई, 1919 को कोलकाता में हुआ था. उनकी पत्नी श्रीमती सुलोचना कुमारण केरला की थीं. उनकी दो बेटियां शुरोमा और सुमिता हैं. मुंबई मे लंबा समय बिताने के बाद मन्ना डे बेंगलुरु में अपनी बेटी के पास शिफ्ट हो गए थे. 24 अक्टूबर, 2013 को 94 साल की उम्र में मन्ना डे के निधन से फिल्म जगत का एक स्वर्णिम अध्याय समाप्त हो गया.

1950 से 70 का दशक हिंदी सिनेमा का ऐसा स्वर्णिम युग है, जिसमें मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, किशोर कुमार और मन्ना डे ने अपनी गायकी से फिल्म जगत को जादुई सुरों से लबालब कर दिया. पांच दशक के अपने लंबे गायकी के सफ़र में उन्होंने हिंदी, बांग्ला, असमी, गुजराती, मराठी कन्नड़ समेत कई भारतीय भाषाओं में अपनी गायकी की इबारत लिखी. उन्होंने सभी भारतीय भाषाओं में लगभग 4000 गीत गाए. शास्त्रीय संगीत में उनकी बेहद रूचि थी. रवींद्र संगीत में वे माहिर थे. मन्ना डे ने शैलेंद्र के दर्जनों अमर गीत गाए. शैलेंद्र को याद करते हुए उन्होंने कहा था, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैंने महान गीतकार शैलेंद्र के गीतों को गाया. उनके शब्द मर्मस्पर्शी होते थे. उनके गीतों में साहित्य और लोकमानस की खुशबू होती थी.

मन्ना डे जब कोलकाता से मुंबई आए तो उनके लिए राह आसान नहीं थी, क्योंकि वे शास्त्रीय संगीत के कायल थे, लेकिन उन्होंने खुद को सिनेमा के संगीत में ऐसे ढाला कि एक तरफ उन्होंने शास्त्रीय टच लिए हुए अमर गीत गाए. वहीं रोमांटिक गीतों को गाकर उन्हें अमर कर दिया. साठ के दशक में संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन ने अपने मेलॉडियस संगीत से धूम मचा रखी थी. ऐसे में शंकर जयकिशन ने उनमें प्रेम गीतों को गाने की अद्भुत शैली देखा और उनसे एक के बाद एक रोमांटिक गाने गवाए. मन्ना डे ने अपनी जीवनी जीबोनेर जोलशाघोरे मेमोरीज कम्स अलाइव में संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन का आभार जताया है.

अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया, संगीत की दुनिया के महान समर्थक मन्ना डे आज हमारे बीच नहीं रहे, पर उनके बेशुमार गानों की यादें हमारे साथ हैं.
-अमिताभ बच्चन

मन्ना दा नहीं रहे, पर उनकी आवाज़ हमेशा गूंजती रहेगी. आज फिल्म इंडस्ट्री के हर आदमी के दिल में मन्ना दा के लिए दुख है.
-महेश भट्ट

मन्ना डे एक अनूठी आवाज थी, वो अपने गीतों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे.
-शबाना आज़मी

मन्ना डे ने 1943 में फिल्म तमन्ना से अपने गायन करियर की शुरुआत की. इस फिल्म की धुनें उनके चाचा कृष्ण चंद डे ने तैयार की थी. उनका गाया गीत सुर न सजे क्या गाऊं मैं... सुपर हिट हुआ. 1950 में मशाल उनकी दूसरी फिल्म थी. इस फिल्म में मन्ना डे को एकल गीत ऊपर गगन विशाल का मौका मिला. इसके संगीतकार थे सचिन देव बर्मन, यह गीत भी हिट हुआ. मन्ना डे ने अपनी भारतीय शास्त्रीय संगीत की शिक्षा उस्ताद अमान अली ख़ान और उस्ताद रहमान अली ख़ान साहब से प्राप्त की. 1942 से शुरुआत कर 2013 तक उन्होंने 3,500 से अधिक रोमांटिक, गाथागीत सहित गाने, जटिल राग आधारित गीत, कव्वाली, हास्य गीत गाए. मन्ना डे सिंगिंग में ना सिर्फ एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया, बल्कि अपने सफर का इतिहास लिखा है. भारत सरकार ने मन्ना डे को उनके सराहनीय योगदान के लिए पदमश्री, पदम भूषण और फिल्म जगत के सबसे बड़े सम्मान दादा साहब फाल्के अवॉर्ड से नवाज़ा.

हास्य गायकी में भी उनका जवाब नहीं था. एक चतुर नार करके सिंगार... चलत मुसाफिर मोह लियो रे पिंजरे वाली मुनिया... फिल्मों मे जितने भी गाने सेमी क्लासिकल और क्लासिकल संगीत पर आधारित हैं, उनमे सबसे ज़्यादा गाने मन्ना डे ने ही गाए. लागा चुंदरी मे दाग... झनक झनक पायल बजे... पूछो ना मैंने कैसे रैन बिताई... आजहू ना आए बालमा... ये रात भीगी भीगी... इत्यादि. मन्ना डे ने दर्जनों भाषाओं में गाया, जितनी ईमानदारी और संजीदगी से उन्होंने शास्त्रीय संगीत के गाने गाए, उतनी ही सच्चाई और लगन से उन्होंने हास्य गानों को भी मनोरंजक बनाया.

मन्ना डे की अंदाज से सभी संगीतकार प्रभावित थे. वे गाने को एक्ट करके गाते थे. मन्ना डे इंडस्ट्री का हर दौर देखा. जब से फिल्मों का जन्म हुआ, तब से लेकर अब तक. वे इस बात के चश्मदीद गवाह थे कि भारतीय संगीत ने फिल्मों के अपने सुनहरे दौर की बुलंदियों को छुआ. उन्होंने भारत से लेकर विदेशों में भी अपने वर्चस्व का बोलबाला बनाए रखा. उस दौर के बड़े संगीतकारों में मदन मोहन, नौशाद, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, शंकर जयकिशन, हेमंत कुमार, एस डी बर्मन सरीखे संगीतकार अपने गानों को बच्चे की तरह पालते थे. मन्ना दा ने आज के संगीत का दौर भी देखा, जहां संगीतकार संगीत का बुरा हश्र कर रहे हैं. कट पेस्ट का ज़माना चल रहा है. एक रेडियो साक्षात्कार में पांच छ: साल पहले उन्होंने कहा था कि मुझसे बेहतर इस संगीत को बदलते किसने देखा होगा. मैंने इस दौर में मौसीक़ी को मरते देखा है, लेकिन मुझे उम्मीद है की ऐसे संगीतकार दोबारा ज़रूर आएंगे. ऐसा संगीत फिर से ज़रूर बनेगा और वैसे ही मेलॉडीज के कंपोसर और अरेंजर फिर से संगीत को नई और सदाबहार रूह देंगे. संगीत कभी मरता नहीं, वह तो अमर रहता है ■

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

04 नवंबर–10 नवंबर 2013

बिहार–झारखंड

वोट की राजनीति में गुम होते श्रीबाबू

बिहार केसरी के नाम से प्रसिद्ध बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉ. श्री कृष्ण सिंह उर्फ श्रीबाबू की पहचान राजनीतिज्ञों के द्वारा अपने–अपने लाभ के मद्देनजर भुमिहार नेता की गढ़ी जा रही है. हर दल अपने हिसाब से श्री बाबू को परिभाषित करने में लगा हुआ है.

अरुण कुमार

इन दिनों वोट बैंक की राजनीति के तहत स्वतंत्रता सेनानी श्रीबाबू को राजनीतिक पार्टियां याद कर रही हैं, लेकिन हकीकत यह है कि श्रीबाबू की पहचान स्वतंत्रता आंदोलन के समय गांधी जी के आह्वान पर नमक आंदोलन मे कूदे उस युवा की है, जिसने नमक बनाने से रोकने आए अंग्रेज सिपाही के सामने खौलते हुए कड़ाहे पर अपना सीना अड़ा दिया. श्रीबाबू की पहचान अपने धुर राजनीतिक विरोधी अनुग्रह बाबू को सर्वाधिक मान–सम्मान देने वालों के रूप में है. श्रीबाबू की पहचान एक समाज सुधारक के रूप में है, जिन्होंने देवघर के मंदिर में दलितों का प्रवेश कराया, जमींदारी उन्मूलन के लिए सार्थक पहल की. श्रीबाबू की पहचान बिहार को गढ़ने वाले उस चितेरे के रूप में है, जिसकी झलक आज भी बरौनी सहित अन्य जगहों पर देखी जा सकती है. कभी बरबीघा के विधायक रहे वर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष अशोक चौधरी, उनके पौत्र सुरेश शंकर सिंह और राष्ट्रवादी किसान सभा के अध्यक्ष इंदूभूषण सिंह या फिर जदयू सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, कभी राजद और अब कांग्रेस में भूमिहार नेता माने जाने वाले अखिलेश सिंह और दूसरे नेताओं ने श्रीबाबू को अपने–अपने हिसाब से भुनाने का प्रयास भर ही किया. किसी ने उनके सपनों को साकार करने की दिशा में पहल तक नहीं की. आज श्री बाबू की पहचान को उनसे छीना जा रहा है और ऐसा महज राजनीतिक लाभ के लिए ही किया जा रहा है. इसी का परिणाम रहा कि श्रीकृष्ण सर्वजन सभा के बैनर तले इंदूभूषण सिंह एवं डॉ. सहजानंद सिंह सरीखे कई नेताओं ने उनकी जयंती 21 अक्टूबर की बजाय 20 को ही मना दी और इतना ही नहीं इस सभा में श्री बाबू के कृतित्व और व्यक्तित्व पर चर्चा कम हुई, नीतीश कुमार पर हमला अधिक हुआ. कांग्रेस अध्यक्ष अशोक चौधरी ने पहले बरबीघा में जयंती समारोह धूम–धाम से मनाने की घोषणा की और यहां तैयारी भी प्रारंभ कर दी गई, पर यहां भी वही लाभ की राजनीति के तहत कार्यक्रम को रद्द कर पटना में बड़ा आयोजन किया गया. राजनीति के हिसाब से पटना में अधिक पॉलीटिकल माइलेज मिलने की उम्मीद थी और इसका परिणाम यह हुआ कि बरबीघा में पार्टी की तरफ से किसी ने जयंती मनाने की औपचारिकता तक नहीं की.

वहीं जदयू सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के साथ राजनीतिक कदमताल मिलाने वाले डॉ. श्रीकृष्ण सिंह के पौत्र हीरा सिंह ने भी अपने पैतृक आवास पर जयंती समारोह की औपचारिकता तक नहीं निभाई. जहां बिहार की पहचान श्रीबाबू से की जाती है और उनकी जयंती के बहाने भूमिहार जाति के वोटों के ध्रुवीकरण की राजनीति होती है, वहीं श्रीबाबू के गांव माइर सहित स्थानीय लोगों में उनके प्रति उपेक्षा का भाव देखने को मिलता है. ग्रामीण गुड्डू सिंह कहते हैं कि जब अपने परिजन ही उनके प्रति श्रद्धा भाव नहीं रखते तो गांव के लोगों से क्या अपेक्षा की जा सकती है. रही बात स्थानीय जदयू विधायक गजानंद शाही की तो उनके द्वारा श्रीबाबू की उपेक्षा जग जाहीर है. उन्होंने सार्वजनिक जगहों पर श्रीबाबू की उपेक्षा करते हुए यहां तक कहा है कि अब पुराने श्रीबाबू को छोड़िये और इस श्रीबाबू (श्री महतो, जदयू नेता) को पकड़िए. उनके इस कथन को यहां के लोग एक जुमले की तरह प्रयोग करते हैं. नवादा लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद भोला सिंह ने आज तक श्रीबाबू को लेकर कोई पहल नहीं की है. वहीं सांसद ललन सिंह की पहल पर नवादा जिले के खनबां (श्रीबाबू का ननिहाल, जहां उनका जन्म हुआ था) में 5 नवंबर को मुख्यमंत्री का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं. वहीं नवादा लोकसभा चुनाव लड़ चुके लोजपा के मसीदुद्दीन कहते हैं कि यह महज राजनीतिक स्टंट है. खनबां गांव आज भी वहीं है, जहां 126 साल पूर्व श्रीबाबू के जन्म के समय था, विकास से बहुत दूर. एक तरफ जहां नीतीश कुमार के गांव कल्याणबीघा में विकास की झड़ी लगा दी गई है, वहीं खनबां और माइर गांव की उपेक्षा राजनीति में पक्षपात ही दर्शाती है. वहीं भाजपा नेता एवं पूर्व प्राचार्य डॉ रामविलास सिंह ने श्रीकृष्ण रामरूची कॉलेज में आयोजित जयंती समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि नालांदा जिले के विकास पर अरबों खर्च किया जा रहा है, पर बगल के शेखपुरा जिले में विकास की एक भी किरण नजर नहीं आती. श्रीबाबू का एकमात्र सपना अनुमंडल बनाने की दिशा में नीतीश कुमार ने बरबीघा में घोषणा कर भी कोई पहल नहीं की. ऐसे में आज श्रीबाबू ज्यादा प्रासंगिक नजर आ रहे हैं, वह भी तब जबकि उनके नाम पर तरह–तरह के आयोजन तो किए जा रहे हैं, पर न तो उनके आदर्शों को अपनाने की पहल हो रही है और न ही उनकी यादों से जुड़ी धरोहरों को सहेजने की कवायद. इसी कड़ी में उनका पैतृक गांव माइर और पैतृक घर अपने को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं. शेखपुरा जिले के बरबीघा प्रखंड के तहत माइर गांव बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉ. श्रीकृष्ण सिंह का पैतृक गांव है. इस गांव की पहचान श्रीबाबू के नाम से चर्चित बिहार केसरी के नाम से होती है, पर गांव के साथ–साथ स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले श्रीबाबू की यादों से जुड़ी वस्तुओं को उपेक्षित रखा गया है.

श्रीबाबू के पैतृक आवास में आज भी उनकी यादों से जुड़ी हुई वस्तुएं रखी हुई हैं, पर जैसे की तैसे. श्रीबाबू का वह मकान जहां उन्होंने अपना बचपन बिताया तथा पूजा घर जिसमें रोज वे पूजा करते थे, आज भी मौजूद हैं. उनके ड्रेसिंग टेबल, कुर्सी तथा पलंग भी मौजूद हैं, पर बेतरतीब. कोई उनकी यादों को संजोने का प्रयास नहीं करता. बिहार के नवनिर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले श्रीबाबू के यादों को सहेजने की मांग सालों से की जा रही है, पर किसी ने इसकी पहल नहीं की. रालोसपा के प्रदेश उपाध्यक्ष शिवकुमार कहते हैं कि श्रीबाबू महज एक मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि एक विचारधारा थे और इसलिए उनकी यादों को सहेजने के लिए उनसे जुड़ी चीजों का एक संग्राहालय माइर में बनाया जाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी इनसे प्रेरणा ले सके. माइर गांव में अब तक पूर्व प्रधानमंत्री स्व राजीव गांधी, स्व. चंद्रशेखर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कई मुख्यमंत्री पधार चुके हैं, पर सभी ने महज उनकी प्रतिमा पर माथा टेका और घोषणाएं की, पर साकार किसी ने नहीं किया. श्रीबाबू को आज भी यहां के लोग याद करते हुए खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं, पर उनकी यादों को सहेजने के लिए सामाजिक पहल नहीं होती है. और न ही इस गौरव के एहसास को जिंदा करने के लिए कोई कदम उठाया जाता है. श्रीबाबू ने बिहार के साथ–साथ अपने गृह क्षेत्र के विकास का सपना देखा था, पर राजनीतिक सुचिता और आदर्श ने उनके सपने को रोके रखा. इसीलिए यहां के कुछ लोग श्रीबाबू को लेकर तल्खी से कहते है कि उन्होंने यहां के लिए क्या किया? पर शिवकुमार इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हुए कहते है कि श्रीबाबू का घर पूरा बिहार था और वे नीतीश कुमार की तरह उथली राजनीति नहीं करते थे, जिसकी वजह से आज उनके कद तक पहुंचने की बात भी कोई नहीं सोच सकता, लेकिन हां बाद की पीढ़ियों ने उनके सपने को पूरा करने का काम नहीं किया. हालांकि यहां के किसानों का दर्द समझकर उन्होंने बरबीघा तक नवादा से सकरी नहर लाई, जिसकी वजह से यहां के किसानों के लिए धान की खेती सहज हो सकी तथा बरबीघा को अनुमंडल बनाने के लिए उनके द्वारा अपने प्रथम कार्यकाल में ही समिति का गठन किया और समिति ने बरबीघा को अनुमंडल बनाने की रिपोर्ट 1956 में ही सौंप दी थी पर बरबीघा के लोग आज तक बरबीघा को अनुमंडल बनाने की बाट जोह रहे हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

श्रीबाबू का जन्म 21 अक्टूबर, 1887 को इनको नवादा जिले के खनवां ग्राम मे हुआ था. उनके पिता का नाम श्री हरिहर सिंह था. श्रीबाबू की प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव की पाठशाला में हुई एवं उच्च शिक्षा जिला स्कूल मुंगेर में हुई. श्री बाबू जब पांच साल की उम्र के थे तो उनकी मां का निधन हो गया. उनका नामांकन 1906 में पटना कॉलेज में हुआ जहां से लॉ की पढ़ाई कर उन्होंने 1915 में मुंगेर से वकालत की शुरुआत की. वहीं 1916 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज वाराणसी तथा 1920 में मुंगेर के शाह मोहम्मद जुबैर हाउस में उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई, जिसके बाद वे आजादी की लड़ाई में कूद पड़े.1922 में उन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया और 1923 को रिहा हुए. 1927 में वे लेजिस्लेटिव कॉन्सिल के सदस्य बने. वहीं 20 जुलाई,1937 को बिहार के मुख्यमंत्री बने और 1939 को उन्होंने इस्तीफा दे दिया. पुन: 1946 में श्रीबाबू बिहार को बिहार का मुख्यमंत्री चुना गया. 1952 में पहली बार वे बरबीघा विधानसभा से चुनाव लड़े और जीते. 22 नबंवर, 1940 से 26 अगस्त, 1941 तक श्री बाबू जेल में रहे. 10 अगस्त ,1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें फिर गिरफ्तार किया गया, फिर हजारीबाग जेल से 1944 को रिहा हुए, जहां वे गंभीर रूप से बिमार हो गए. उनका निधन 31 जनवरी, 1961 को हो गया.

मुंगेर

गरीबों के निवाले पर बाबुओं का डाका

कुमार कृष्णन

एक सर्वेक्षण के मुताबिक गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वाली आबादी का एक बड़ा हिस्सा पहले अनाज जुटाता है और फिर भोजन तैयार करता है. केंद्र और राज्य सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं. इन योजनाओं का लाभ वास्तविक लोगों तक नहीं पहुंच पाता है.

बीपीएल परिवार, अंत्योदय योजना या फिर अन्य सरकारी योजना के लाभान्वितों के लिए अनाज की खरीदारी भारतीय खाद्य निगम करती है. यहां गेहूं का बोरा छोड़कर 50 किलो के हिसाब से खरीदा जाता है. इसी का मूल्य किसानों को दिया जाता है. इसी अनाज को राज्य खाद्य निगम के द्वारा जनवितरण और पैक्स के माध्यम से योजना के लाभान्वितों को दिया जाता है. लाभान्वितों तक अनाज पहुंचने से पहले बाबुओं का डाका पड़ जाता है. किस प्रकार इस योजना के तहत लूट होती है, इसका नजारा देखना हो तो सफियावाद स्थित राज्य खाद्य निगम के गोदाम में अनाज बांटे जाने के समय देखा जा सकता है. घरहरा पैक्स के अध्यक्ष ऋषिदेव कुमार के मुताबिक लंबे अरसे से राज्य खाद्य निगम द्वारा अनाज निर्धारित मापदंड से काफी कम दिया जाता है. तय मापदंड के मुताबिक बोरा सहित 52.500 किलो गेंहू या जाना है, लेकिन मिलता है काफी कम. इस लूट पर तो यकीन ही नहीं होता है. इस बात की पुष्टि के लिये सफियाबाद गोदाम से ही अनाज ले जा रहे जमालपुर शहरी क्षेत्र के एक जनवितरण विक्रेता आनंद कुमार के पांच बोरे अनाज की दोबारा गोदाम के ही तराजू पर तौल कराई गई तो हर बोरे में पांच से सात किलो अनाज निर्धारित मापदंड से कम था. अपनी कारगुजारियों को छिपाने के लिए राज्य खाद्य निगम, सफियाबाद के सहायक गोदाम प्रबंधक का जवाब भी अजीबोगरीब था.

लंबे अरसे से राज्य खाद्य निगम द्वारा अनाज निर्धारित मापदंड से काफी कम दिया जाता है. तय मापदंड के मुताबिक बोरा सहित 52.50 किलो गेहूं दिया जाना है, लेकिन मिलता है काफी कम. इस लूट पर तो यकीन ही नहीं होता है.

अपनी गलती को छिपाने के लिये वे ठीकरा दूसरों के सिर फोड़ने से बाज नहीं आए. उनके मुताबिक भारतीय खाद्य निगम से कम अनाज मिलता है. इसलिये प्राप्त अनाज का औसत निकाल कर उसी हिसाब से अनाज दिया जाता है.

थोड़ी देर के लिए उनकी बात मान भी ली जाए, लेकिन जो अनाज पैक्स या डीलर को उपलब्ध कराया जाता है तो निर्धारित मापदंड पर क्यों लिया जाता है. वहीं राज्य खाद्य निगम के सहायक महाप्रबंधक रणवीर सिंह ने सारे मामले पर पर्दा डालते हुए संसाधनों का रोना रोया. इसके अलावा, वे कुछ भी कहने से बचते रहे. अनुमंडलस्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक में यह मामला उठा. अनुमंडल पदाधिकारी सदर डॉ. कुंदन कुमार से यह शिकायत की गई कि सहायक गोदाम प्रबंधक द्वारा अनाज कम दिया जाता है. अनुमंडल पदाधिकारी का कहना था कि अगर सहायक गोदाम प्रबंधक द्वारा खुले पैकेट में अनाज दिया जाता है तो इसे स्वीकार नहीं करें. इस बोरे पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी तथा अनुमंडलाधिकारी का टैग लगा होने के बाद ही स्वीकार करें. यदि सहायक गोदाम समय से गोदाम खोलकर खाद्यान्न मापकर नहीं दिया जाता है, तो कालाबाजारी का मुकदमा किया जाएगा.

राज्य खाद्य निगम के गोदाम में किस प्रकार यह लूट हो रही है. इस लूट की सीडी फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के मुंगेर शाखा के अध्यक्ष जयप्रकाश साह ने मुंगेर जिलापदाधिकारी नरेंद्र कुमार सिंह और राज्य के खाद्य आयुक्त को सौंपी है. उनके मुताबिक सीडी में लूट के प्रर्याप्त साक्ष्य हैं. सरकार इस मामले को गंभीरता ले. मामला चाहे जो भी हो. यूपीए खाद्य सुरक्षा को लेकर चुनाव में गरीबों का वोट बटोरने के लिये गंभीर है और इसके प्रचार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से अन्य जगहों आ रहे हैं. सबसे अहम सवाल है कि इस लूट पर कैसे लगाम लगाई जाए.■

feedback@chauthiduniya.com

मौत से जूझती दुष्कर्म पीड़िता और लापरवाह पुलिस

अवधेश कुमार शर्मा

बगहा इन दिनों महिलाओं के साथ हो रहे सामुहिक दुष्कर्म को लेकर सुर्खियों में है. आए दिन इस इलाके में बलात्कार की घटनाएं घट रही हैं और पुलिस मूकदर्शक बनी हुई है. ऐसे में सवाल उठता है कि महिलाएं अपनी सुरक्षा के लिए किससे गुहार लगाएं.

बीते दिनों बथवरिया थाना क्षेत्र के सेरवा बाजार गावं की श्वेता (काल्पनिक नाम) नामक एक विवाहिता के साथ हुई घटना ने एक तरफ जहां मानवता को शर्मसार किया, वहीं दूसरी तरफ इस घटना से पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया है. सामूहिक दुष्कर्म की लोमहर्षक घटना के बाद महिला की हालत काफी गंभीर हो गई है.

महारानी जानकी कुंवर अस्पताल में मौजूद पीड़िता की मां के अनुसार, 5 अक्टूबर की रात को वह अपनी विवाहिता बेटी के साथ घर से बाहर पानी के लिए निकली थी, तभी अचानक तीन नकाबपोश लोगों ने श्वेता को उठा लिया. मां के शोर मचाने के बाद ग्रामीण जुटे और विवाहिता को ढूंढ़ना शुरू किया. करीब एक घंटे के बाद गांव के बाहर एक खेत में वह महिला बेहोशी की हालत में मिली. परिजन उसे लेकर बगहा अस्पताल गये, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक चिकित्सा के बाद बताया कि पीड़िता के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया है. हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि घटना के नौ दिन गुजरने के बाद भी पीड़िता ने आंख तक नहीं खोली थी. पीड़िता की स्थिति यह है कि उसके शरीर के बाएं हिस्से ने काम करना बंद कर दिया था. परिजन इसमें डॉक्टरों की लापरवाही बता रहे हैं. पीड़िता ने अपना जो बयान दर्ज कराया है, उसमें उसी गांव के विन्ध्याचल महतो के दामाद भूलन चौधरी, रेयाज मियां पिता अनवारुल मियां और दो अन्य लोगों का नाम बताया है, जिसे वह पहचानती है. हालांकि बलात्कार में शामिल कुछ लोगों को वह नहीं जानती है.

सबसे चौंकाने वाला तथ्य तो यह है कि खबर लिखे जाने तक पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर सकी थी और आरोपी खुलेआम घूम रहे थे. इधर छात्र समागम बिहार के उपाध्यक्ष मनौवर आलम ने अपराधियों की गिरफ्तारी अविलम्ब करने की मांग एसपी से की है. बगहा स्थित महिला थाना के थानाध्यक्ष राजन पांडेय के अनुसार, घटना के बाद अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है. दूसरी तरफ सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी मिलती है कि तथ्य को छुपाने, समुचित चिकित्सा का अभाव व डॉक्टरों की लापरवाही के कारण ही श्वेता की हालत और बिगड़ी है. यक्ष प्रश्न यह है कि श्वेता को गम्भीर स्थिति में पीएमसीएच क्यों नहीं रेफर किया गया और पुलिस ने बिना बयान के घटनास्थल पर पहुंच कर दुष्कर्मियों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया, यह जांच का विषय है. सामूहिक दुष्कर्म की शिकार श्वेता 5 अक्टूबर से जिन्दगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही है. अस्पताल परिसर में मौजूद लोगों का कहना है कि उसकी हालत बहुत गंभीर है. लोगों का कहना है कि न जाने क्यों इस अस्पताल के डॉक्टरों ने इस महिला के बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर नहीं किया.

इस गंभीर घटना के बाद भी जिला पुलिस का रवैया टाल–मटोल करने जैसा ही है. बगहा एसपी हरि प्रसाद एस ने बताया कि पीड़िता के परिजनों ने महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है. अभी संबंधित थाना ही आपको जानकारी देगा. पीड़िता के बयान के बाद विशेष जानकारी के लिए बगहा एसडीपीओ के मोबाइल पर जब संपर्क किया गया तो उनके रीडर ने बताया कि साहब नहीं हैं. जिला पुलिस के इस रवैये से साफ है कि पुलिस मामले को किसी तरह रफा–दफा करना चाहती है. यही वजह है कि प्रशासन मामले में सिर्फ खानापूर्ति कर रही है.■

सामूहिक दुष्कर्म की शिकार श्वेता 5 अक्टूबर से जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रही है. अस्पताल परिसर में मौजूद लोगों का कहना है कि उसकी हालत बहुत गंभीर है, न जाने क्यों यहां के डॉक्टरों ने इसे बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर नहीं किया. इस घटना में जिला पुलिस का रवैया भी टाल-मटोल करने जैसा ही है. बगहा एसपी हरि प्रसाद एस ने बताया कि पीड़िता के परिजनों ने महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी है.

feedback@chauthiduniya.com

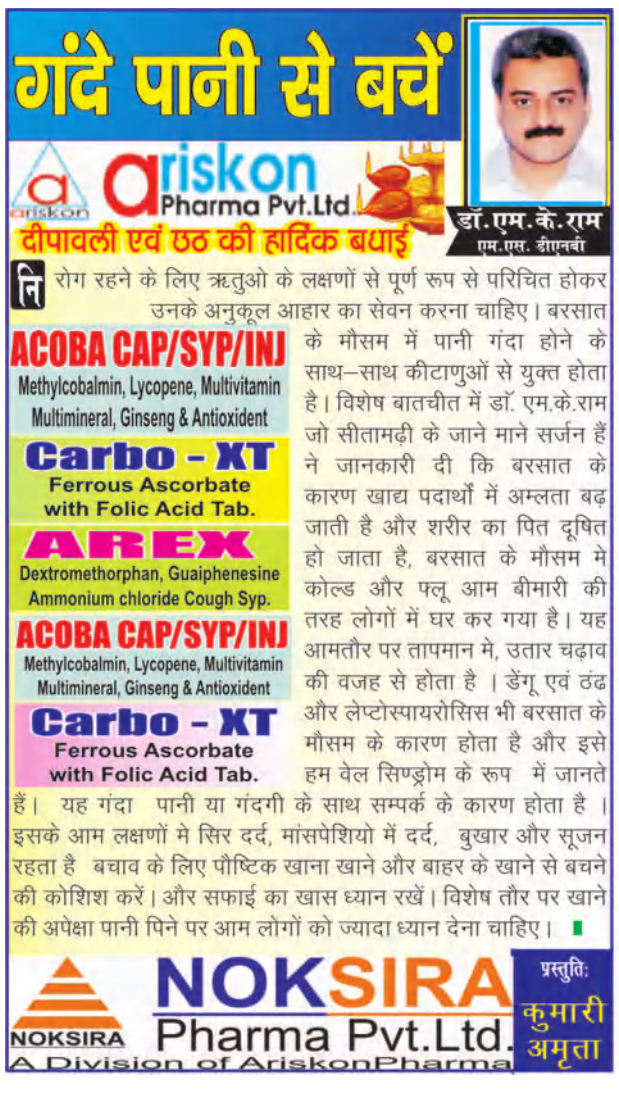

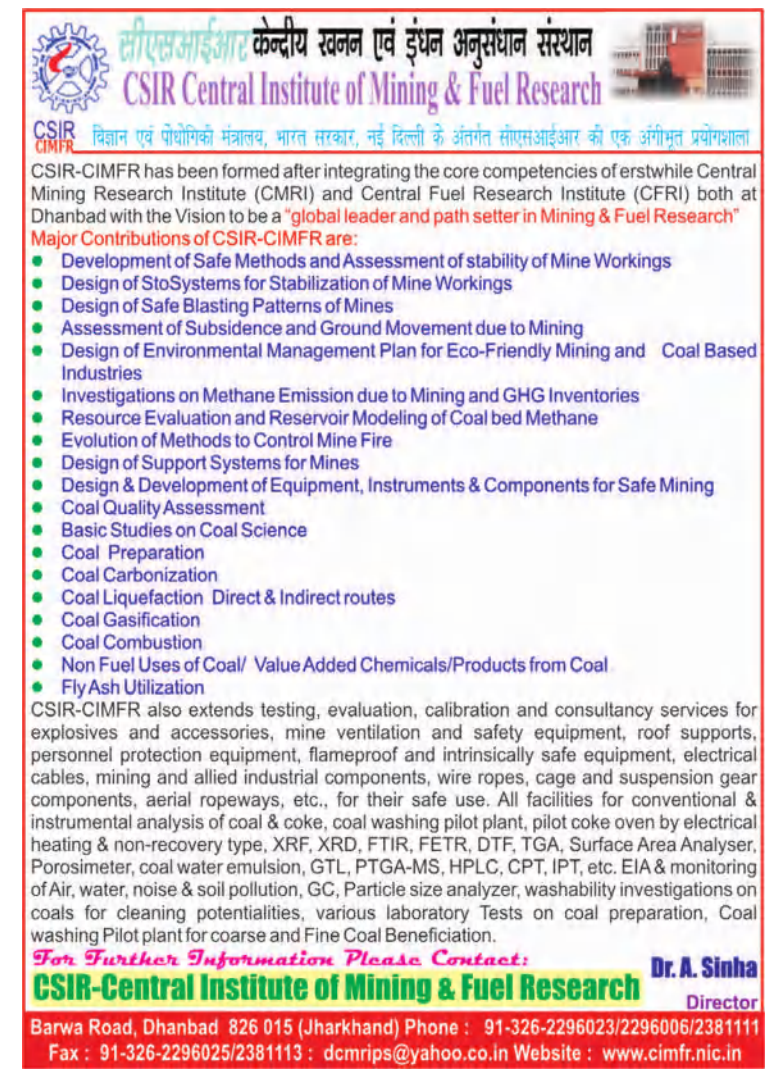

अपनी ही व्यवस्था के खिलाफ़ जदयू विधायक

नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह बेगूसराय के मटिहानी विधानसभा से जदयू के विधायक हैं. विधायक जी इन दिनों अपनी ही व्यवस्था के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं. उन्हें अपनी ही व्यवस्था में खोट दिख रहा है. सरेआम उन्होंने कहा कि इस सिस्टम पर अफसरशाही हावी है और जिला प्रशासन तो पूरी तरह भ्रष्ट है.

सुरेश चौहान

अनशन पर बैठे विधायक बोगो सिंह एवं फल का रस पिलाकर अनशन समाप्त कराते डीएम

पिछले दिनों मटिहानी विधायक आमरण अनशन पर बैठ गए. पांच दिनों तक लगातार विधायक जिला प्रशासन को भ्रष्ट करार देते रहे, खुलकर कोसते रहे. इसके बाद जिला प्रशासन की नींद टूटी और उसने मांगों को पूरा करने के लिए अधिकतम 90 दिनों का समय विधायक से लिया और तब अनशन समाप्त हुआ. बोगो सिंह कहते हैं कि हमारा अनशन सरकार के खिलाफ नहीं वरन जिला प्रशासन की कार्य संस्कृति में बदलाव लाने के लिए है. बताते चलें कि इससे पूर्व भी विधायक अनशन पर बैठ चुके हैं. उस समय भी जिला प्रशासन के आश्वासन के बाद अनशन टूटा. लेकिन अब देखना है कि क्या इस बार के अनशन का कोई असर होगा या जिला प्रशासन अपनी की गति से चलती रहेगी.

वैसे पूर्व के अनुभवों के आधार पर कहें तो इस अनशन का नतीजा भी ढाक के तीन पात जैसा ही होने वाला है. प्रश्न उठता है कि जब एक सत्तारूढ़ दल के विधायक को अनशन पर बैठना पड़ रहा हो तो आम लोगों की क्या स्थिति होगी? स्वर्ण जयंती केन्द्रीय पुस्तकालय परिसर में महात्मा गांधी की आदमकद प्रतिमा के समक्ष अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे थे विधायक बोगो सिंह. उनकी मांग है कि पिछले 20 वर्षों से गंगा नदी के कटाव से विस्थापित हुए सैकड़ों परिवार को पुनर्वासित किया जाए, भ्रष्टाचार को समाप्त करते हुए उचित मूल्य एवं माप–तौल द्वारा उपभोक्ता को राशन उपलब्ध कराया जाए व बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के परिवारों को चिन्हित कर राहत सामग्री मुहैया कराई जाए. इसके साथ ही विधायक द्वारा पूर्व में दिए गए कल्याणकारी योजनाओं (इंदिरा आवास, वृद्धावस्था पेंशन, कबीर अंत्येष्टि, कन्या विवाह योजना की राशि का भुगतान आदि) से संबंधित आवेदनों का निष्पादन नहीं करनेवाले पदाधिकारियों के दायित्व का निर्धारण करते हुए 15 दिनों के अन्दर इसका निष्पादन किया जाए.

अनशन के दौरान ही विधायक ने बताया कि 20 वर्ष पूर्व ही मटिहानी प्रखंड के सैकड़ों परिवार गंगा नदी के भीषण कटाव से विस्थापित होकर गुमा लखमिनियां बांध पर आकर बसे थे. तब से अब तक वे खानाबदोश की तरह जीने को विवश हैं और अपनी पहचान खोते जा रहे हैं. लगातार प्रशासन उन्हें पुनर्वासित करने का सिर्फ आश्वासन देता आ रहा है. दो वर्ष पूर्व ही उन्हें पुनर्वासित करने के लिए भूखंड चिन्हित कर ली गई थी और राज्य सरकार ने राशि का आवंटन भी कर दिया है. बावजूद इसके इन्हें जमीन का पर्चा नहीं दिया गया. विधायक बोगो सिंह का आरोप है कि डीलर द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक राशि लेकर, कम वजन तौलकर कार्डधारकों को राशन दिया जा रहा है, जिसकी लिखित शिकायत वे कई बार जिला प्रशासन से कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन ने कार्रवाई करना तो दूर पत्र प्राप्ति की सूचना तक नहीं दी है.

इसी तरह विधायक ने सामाजिक कल्याण योजना पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया. विधायक ने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन के लिए एक विधवा औरत के आवेदन की अनुशंसा कर उसे उन्होंने खुद जमा करवाया था, लेकिन अब तक इसका सत्यापन नहीं हो पाया. पेंशन की आशा में उक्त महिला दुनिया ही छोड़कर चली गई, लेकिन जिला प्रशासन की नींद नहीं टूटी. कबीर अंत्येष्टि योजना, कन्या विवाह योजना जैसे कल्याण योजनों की राशि भी समय पर उपलब्ध नहीं कराई जा रही है. उन्होनें डीएम को पत्र लिखकर कई बार अनुरोध किया कि इन सब मामले में पदाधिकारियों का दायित्व निर्धारित कर कार्रवाई की जाए, लेकिन जिलाधिकारी ने भी ध्यान नहीं दिया.

पिछले दिनों जिले के आठ प्रखंडों बछवाड़ा, तेघड़ा, मटिहानी, साम्हो, बरौनी बलिया, एवं साहेबपुरकमाल तथा बेगूसराय नगर निगम की आबादी गंगा नदी के भीषण बाढ़ से प्रभावित हुई. देर से ही सही सरकार द्वारा राहत कार्य प्रारंभ किया गया जिसके तहत प्रत्येक पीड़ित परिवार को 50 किलो गेहूं, 50 किलो चावल एवं 1500 रु. नगद देना था. वर्षों पूर्व के पारिवारिक सूची पर राहत प्रदान करने से सैकड़ों नए परिवार इससे वंचित रह गए.

दूसरी खामी रही कि राहत केंद्र काफी दूर लगाया गया, जहां तक पहुंचने के लिए पीड़ितों को 3 से 4 किलोमीटर की यात्रा पानी में चलकर करनी पड़ी जो जोखिम से भरी थी. बाढ़ की विभीषिका कम होने पर भी इन परिवारों को राहत सामग्री नहीं मिल पाई. विधायक की मांगों में यह भी शामिल था कि राहत से वंचित परिवारों को चिन्हित कर 15 दिनों के अन्दर राहत उपलब्ध कराई जाए. अनशन के पांचवे दिन जिलाधिकारी मनोज कुमार, आरक्षी अधीक्षक हरप्रीत कौर, एसडीओ सत्यप्रकाश मिश्र, सीएस सोना लाल अकेला, एएसपी अजित कुमार सिन्हा की टीम ने बोगो सिंह को फलों का रस पिलाकर अनशन समाप्त कराया. अनशन समाप्ति के बाद मेडिकल चेकअप में विधायक पीलिया से पीड़ित पाए गए और वे इलाजरत हैं. अनशन समाप्ति के समय बोगो सिंह ने डीएम से स्पष्ट कहा कि यदि 90 दिनों के अन्दर आश्वासन का परिणाम नहीं निकलता है तो वे पुनः अनिश्चितकालीन अनशन प्रारंभ कर देंगे. विधायक के इस अनशन को कुछ लोगों ने नाटक करार दिया, लेकिन आलोचकों ने यह भी स्वीकार किया कि मांगें जायज हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

www.chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

04 नवंबर–10 नवंबर 2013

कांग्रेसी नेता रामबाबू यादव नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहते हैं कि किसानों के नाम पर सरकार प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये पानी की तरह बहाती है, लेकिन बदहाल पसाह नदी की बेहतरी के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती. वे किसानों को ठगने का आरोप भी नीतीश सरकार पर लगाते हैं.

तिरहुत स्नातक

आमने- सामने होगी भाजपा- जदयू

लोकसभा चुनाव के साथ ही तिरहुत स्नातक निर्वाचन को लेकर भी चुनावी तापमान बढ़ने लगा है. एक मंच से महंगाई, बेरोजगारी व भ्रष्टाचार समेत अन्य मामलों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधने वाले एनडीए के नेता गठबंधन टूटने के बाद अब आर-पार की लड़ाई के मूड में हैं. तिरहुत स्नातक क्षेत्र के विधान पार्षद देवशचंद्र ठाकुर जहां सभी वर्गों के मतदाताओं का समर्थन मिलने का दावा करते हैं, वहीं पूर्व विधान पार्षद राम कुमार सिंह इस बार भाजपा के समर्थन पर किला फतह करने की तैयारी में हैं. वैसे चुनाव का अभी वक्त है, लेकिन दोनों ही प्रत्याशियों की सक्रियता तिरहुत क्षेत्र के स्नातक मतदाताओं को ठोस निर्णय के लिए प्रेरित करने लगी है.

वाल्मीकि कुमार

बिहार में राजनीतिक उथल–पुथल के बीच लोकसभा चुनाव की तैयारी लगभग शुरू हो चुकी है. सभी दलों के संभावित प्रत्याशियों ने पार्टी दफ्तर से लेकर शीर्ष नेताओं तक की गणेश परिक्रमा करना शुरू कर दी है. खास कर इस बार बिहार में एनडीए का 17 साल पुराना गठबंधन दरकने के बाद राजनीतिक पैतरा नया रंग लेने लगा है. महज चंद माह पूर्व तक एक साथ रहे एनडीए नेता अब एकदूसरे की औकात को तोलने का बाट लेकर सभी जिलों में कार्यकर्ताओं के बीच अपनी डफली बजा रहे हैं. इसी बीच तिरहुत स्नातक क्षेत्र के सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर व वैशाली जिले में स्नातक निर्वाचन को लेकर चुनावी तापमान बढ़ना शुरू हो गया है.

देवेशचंद्र ठाकुर

राम कुमार सिंह

जदयू के विधान पार्षद देवशचंद्र ठाकुर जहां एक ओर चुनावी तैयारी को लेकर सीतामढ़ी शिवहर समेत क्षेत्र के अन्य जिलों में मतदाताओं व कार्यकर्ताओं के बीच अपनी जीत सुनिश्चित कराने को लेकर उपस्थिति दर्ज कराने लगे हैं. वही पूर्व विधान पार्षद व भाजपा समर्थित प्रत्याशी राम कुमार सिंह ने भी अपनी पूरी ताकत चुनावी तैयारी में लगा दी है. बिहार में एनडीए गठबंधन में दरार के बाद पिछले महीने मुजफ्फरपुर के जिला स्कूल मैदान में आयोजित विश्वासघात रैली के दौरान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मंगल पांडेय ने राम कुमार सिंह के नाम की विधिवत पार्टी समर्थित प्रत्याशी होने की घोषणा की थी. हालांकि यह पहला मौका था, जब किसी दल की ओर से प्रत्याशी की घोषणा स्नातक क्षेत्र के लिए की गई. कार्यकर्ताओं ने भी सिंह के पक्ष में अपना समर्थन व्यक्त किया. अब तिरहुत स्नातक क्षेत्र के मतदाताओं के बीच दो विकल्प हैं. पहला, पार्टी आधार पर नरेंद्र मोदी लहर में बहते हुए भाजपा समर्थित सिंह को वोट दें या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जदयू के विधान पार्षद ठाकुर को मत दें. अगर नही तो क्षेत्र के विकास व स्नातकों के हित में किए गए कार्यों का आकलन करते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग करें. वैसे चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन स्नातक मतदाताओं में खास चहलकदमी चुनाव को लेकर अभी नहीं देखी जा रही है, जबकि प्रत्याशियों द्वारा मतदाता बनाने को लेकर अभियान शुरू जरूर किया गया है. चुनाव को लेकर विधान पार्षद देवेशचंद्र ठाकुर के सीतामढ़ी जिला मुख्यालय डुमरा स्थित आवास पर पिछले महीने आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में मौजूद पूर्व सांसद नवल किशोर राय, बिहार विधान परिषद के सदस्य राज किशोर कुशवाहा समेत अन्य लोगों ने जो उत्साह दिखाया, अगर उसमें कोई हेरा–फेरी नहीं हुई तो पलड़ा फिलहाल भारी जरूर नजर आ रहा है. इसी प्रकार मुजफ्फरपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान भाजपा समर्थित स्नातक मतदाताओं की सक्रियता से सिंह की स्थिति भी कम मजबूत नहीं आंका जा सकता.

विधान पार्षद देवेशचंद्र ठाकुर ने चुनावी तैयारी के संबंध में चर्चा करते हुए बताया कि वर्ष 2000 से पूर्व तिरहुत स्नातक क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या महज 3 हजार थी. वर्ष 2002 में जागरूकता अभियान की बदौलत संख्या 50 हजार एवं 2005 में 63 हजार हुई. अबकी बार यह संख्या 1 लाख को पार कर सकती है, उन्होंने कहा कि स्नातक निर्वाचन में दलगत राजनीति का कोई मतलब नहीं होता है. ऐसे में गठबंधन टूटने का कोई असर नहीं पड़ सकता. ठाकुर ने माना कि अब भी स्नातकों के लिए बेरोजगारी की समस्या गंभीर है, जबकि सूबे कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समस्या निदान का प्रयास जरूर किया है. बावजूद इसके रोजगार सृजन की दरकार है. उन्होंने कहा कि वित्त रहित शिक्षा पर सरकार की सकारात्मक मंशा के बाद भी वेतन व मानदेय समेत अन्य मसलों पर कार्य करने की जरूरत है. ठाकुर ने स्नातक निर्वाचन के साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव में भी तिरहुत स्नातक क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाले पांच में से एक सुरक्षित क्षेत्र को छोड़कर चार में से किसी क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ने की मंशा व्यक्त की. उन्होंने कहा कि अगर सीतामढ़ी से मौका मिला तो और भी बेहतर हो सकता है. उन्होंने पशुपालन घोटाला मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की जल यात्रा को गोरखधंधे में संलिप्त राजनीतिक लोगों के लिए एक सबक बताया. एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद के जेल जाने के बाद राजद के टूटने की कल्पना नहीं की जा सकती है. कारण कि लालू प्रसाद के चहेतों की बिहार में अब भी कमी नहीं है. दूसरी ओर पूर्व विधान पार्षद राम कुमार सिंह ने भी इस बार अपनी जीत को लेकर हर संभव प्रयास शुरू कर दिया है. पूर्व की अपेक्षा इस बार उनके चुनावी अभियान में विशेष मशक्कत की गुंजाइश नजर नहीं आ रही है. कारण कि भाजपा खेमा तकरीबन सभी क्षेत्र में सिंह के पक्ष में एकजुट होने लगा है. सिंह का दावा है कि दलगत घोषणा के बाद भी सभी तबके के मतदाताओं का व्यापक समर्थन मिल रहा है. स्नातक मतदाता इस बार बदलाव के मूड में है. खास कर युवा स्नातकों का रुझान अपने पक्ष में होने का सिंह दावा कर रहे हैं. इन तमाम चुनावी ताम–झाम के बाद भी स्नातक मतदाताओं की मंशा क्या है? फिलहाल कहना मुश्किल प्रतीत हो रहा है. स्नातक मतदातओं के बीच चर्चा यह भी है कि चुनाव में स्नातकों का मत बटोरने वाले प्रतिनिधि चुनाव के बाद किसी खास दल के प्रति समर्पित होकर रह जाते हैं. नतीजतन स्नातकों की समस्या का निदान एक गंभीर चुनौती बन कर रह जाती है. चर्चाओं पर भरोसा करें तो अधिकतर स्नातक मतदाता अबकी बार परिवर्तन के मूड में हैं. वैसे चुनाव में अभी काफी वक्त है. चुनावी चक्रव्यूह के बीच स्नातक मतदाताओं की मंशा अंतिम चरण में क्या होगी? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

भ्रष्टाचार का अड्डा बना पूर्णिया समाहरणालय

नीरज कुमार सिंह

बिहार सरकार में कोई भी कर्मचारी तीन साल से अधिक एक ही जगह पदस्थापित नहीं रह सकता है. इसके पीछे यह तर्क दिया जाता है कि इससे बढ़ते भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी, लेकिन पूर्णिया समाहरणालय में वर्षों से एक ही पद पर जमे अनेकों पदाधिकारी एवं कर्मचारी सरकार के इस कानून की पोल खालने के लिए काफी हैं.

पूर्णिया में कई जिलाधिकारी आए और गए, लेकिन उनके सेहत और शोहरत पर कोई असर नहीं पड़ा. विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अधिकारी मनोज कुमार झा राजस्व एवं गोपनीय शाखा में लगभग 05–06 वर्षों से ज्यादा समय से पूर्णिया में पदास्थापित हैं. इसी तरह जिला स्थापना शाखा प्रभारी पदाधिकारी अशोक कुमार झा 05 वर्षों से भी अधिक समय से पूर्णिया में ही पदास्थापित हैं. जिला योजना एवं विकास शाखा के प्रभारी पदाधिकारी अहमद महमूद लगभग 05–06 वर्षो से पूर्णिया समाहरणालय में पदास्थापित हैं. बताते चलें कि पूर्ववर्त्ती जिलाधिकारी एन. सरवन कुमार के कार्यकाल में महमूद जिला योजना एवं विकास शाखा के प्रभारी पदाधिकारी थे और वर्तमान जिला पदाधिकारी के कार्यकाल में भी जिला योजना एवं विकास शाखा के प्रभारी पदाधिकारी बने हुए हैं.

पूर्व जिलाधिकारी के कार्यकाल के समय ही जिले के सौंदर्यीकरण के नाम पर पार्कों और तलाबों का सौंदर्यीकरण किया गया. इसमें 1 करोड़ 75 लाख की राशि से राजेंद्र बाल उद्दान का जिर्णोद्धार किया जाना प्रमुख है. विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अहमद महमूद के संरक्षण में ही पूर्णियां में तलाबों और पार्कों का भी जिर्णोद्धार किया गया, लेकिन स्थानीय लोगों में यह चर्चा है कि राजेंद्र बाल उद्यान के सौंदर्यीकरण के नाम पर बड़े पैमाने पर राशि के वारे न्यारे किए गए हैं. जिला सामान्य शाखा के प्रभारी पदाधिकारी रमेश चंद्र चौधरी चार वर्षों से भी अधिक समय से पूर्णियां में पदास्थापित हैं, उनके पास जिला अभिलेखागार के अलावा सांख्यिकी विभाग का भी अतिरिक्त प्रभार है. जिला नजारथ पदाधिकारी संतोष श्रीवास्तव 05 वर्षों से पदास्थापित हैं. अपर समहार्त्ता विभागीय जांच एवं क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी पूर्णिया प्रमंडल लगभग 03 वर्षों से भी अधिक समय से इसी जिले में अपनी सेवा दे रहे है. जिला जनसंपर्क पदाधिकारी 4 वर्षों से यहीं पदास्थापित हैं.

बात वरीय उपसमहर्त्ता स्तर के पदाधिकारी के स्थानांतरण एवं पदास्थापन तक सिमित नहीं है. जिले में कुछ ऐसे पहुंच वाले कर्मचारी भी हैं जो अपने अपने शाखा के पदाधिकारियों की पैठ के बल पर जिला में एक ही जगह पर 08–10 वर्षों से भी अधिक समय से पदास्थापित है. वहीं कुछ ऐसे भी कर्मचारी हैं, जिनकी कोई पहुंच नहीं है. वे लगातार स्थानांतरण का दंश झेलते हैं. हाल में ही सैकड़ों कर्मियों का स्थानांतरण हुआ, लेकिन प्रधान नाजिर तौसिफ आलम 08–10 वर्षों से लगातार अपनी पहुंच के बल पर समाहरणालय में ही जमे हुए हैं. नाम नहीं छापने के शर्त पर एक समाहरणालय कर्मी ने जानकारी दी कि हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी में लेख लिखने के सवाल पर उन्होंने महिलाओं को ताना मारा. उन्होंने कहा कि हिंदी में कबड्डी कैसे खेली जाता है. इस पर लेख लिखें. हालांकि इसकी शिकायत महिलाओं ने प्रतिष्ठा के चलते किसी से नहीं की. सामान्य शाखा में ही तौकिर आलम 08–10 वर्षों से जमे हुए हैं. विधिक शाखा में दिलीप झा भी वर्षों से एक ही जगह पर हैं. स्थापना शाखा में जयकृष्ण दास भी 08–10 वर्षों से अधिक समय से यहीं डटे हुए हैं. जिला आपूर्ति शाखा में रंजीत कुमार एवं सपना डे कई सालों से यहीं अपनी सेवा दे रहे हैं. इस तरह से वर्षों से एक ही जगह जमे अधिकारी और कर्मचारी सुशासन के सच पर सवाल खड़ा कर रहे हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

रक्सौल

पसाह नदी विभागीय उपेक्षा की शिकार

नेपाल की पहाड़ियों से निकलकर बिहार में प्रवेश करने वाली पसाह नदी का अस्तित्व खतरे में है. सरकारी उपेक्षा की शिकार यह नदी कभी इलाके के किसानों के लिए लाभकारी हुआ करती थी. जब यह नदी अपने यौवन पर थी तो यहां के किसानों को कभी भी सिंचाई की समस्या नहीं हुई.

राजहंस तिवारी

बिहार सरकार और जलसंसाधन विभाग हर साल सिंचाई के नाम पर कारोड़ों खर्च करती है, लेकिन इस नदी की जिर्णोद्धार की दिशा में अब तक विभागीय स्तर पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है. स्थानीय लोग और इलाके के किसान पसाह नदी की इस समस्या को लेकर कई बार विभागीय लोगों से मिल भी चुके हैं. विभागीय उपेक्षा के कारण किसानों की खेती तो प्रभावित हो रही है, वहीं पानी समय पर नहीं मिलने से हजारों हेक्टेयर भूभाग बंजर होने के लिए छोड़ दिए जाते हैं. जानकार बताते हैं कि नेपाल के नीजगढ़ पहाड़ व जंगल से निकली यह नदी तराई क्षेत्र से होकर रक्सौल अनुमंडल के आदापुर प्रखंड के मुर्तिया, कोरैया समेत दर्जनों गांवों से गुजरते हुए छौड़ादानो प्रखंड के लोहरिया, बैशखवा, पुरैनिया, बेलाहिया, भतनहिया आदि गावों को लांघती हुई रामपुर के निकट दुधौरा नदी में मिल जाती है. यह नदी जिस इलाके से भी गुजरती है, वहां के किसानों के लिये लाभकारी साबित होती रही है. कांग्रेसी नेता रामबाबू यादव नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहते हैं कि किसानों के नाम पर सरकार प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये पानी की तरह बहाती है, लेकिन इस बदहाल पसाह नदी की बेहतरी के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती है. वे किसानों को ठगने का आरोप भी नीतीश सरकार पर लगाते हैं. दूसरी तरफ राजद के जिला उपाध्यक्ष कपिलदेव प्रसाद यादव, देवेंद्र यादव, आदापुर राजद प्रखंड अध्यक्ष रमेश सिंह, परमानंद साहनी, बसपा नेता चंद्रकिशोर पाल, सामाजिक कार्यकर्ता वीरेंद्र यादव, राजद नेत्री श्रीमति देवी, पूर्व मुखिया देवेंद्र यादव, सपा नेता जयप्रकाश नारायण यादव, भाजपा नेता सुरेंद्र तिवारी आदि नेताओं ने भी नदी के इस हालत के लिये बिहार सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि यह किसानों के साथ सौतेला व्यवहार है. स्थानीय लोगों का भी मानना है कि किसानों के कल्याण के लिये घोषणा तो होती है, लेकिन जमीन पर इसका असर नहीं दिखता है. बहरहाल नदी की इस स्थिती से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके के किसान हैं, सिंचाई के अभाव में उनकी खेती प्रभावित हो रही है. ■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

04 नवंबर–10 नवंबर 2013

उत्तर प्रदेश – उत्तराखंड

यूपी में चुनावी रोडमैप तय कर गए मोदी

अजय कुमार

भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेन्द्र मोदी उत्तर प्रदेश में पार्टी लाइन तय कर गए हैं. पहली बार यूपी में केन्द्रीय कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल के संसदीय जिले कानपुर में दहाड़े मोदी ने न तो हिन्दुत्व का राग अलापा, न ही राम मंदिर के बारे में कुछ बोले. मंच पर राम मंदिर के नायक पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह मौजूद थे, फिर भी हवा का रुख बदला हुआ था. इससे एहसास हो गया कि करीब दो दशकों के बाद पार्टी का नजरिया बदल गया है. वहीं यह भी तय हो गया है कि दंगों की सियासत से भी भाजपाई दूर रहेंगे. भले ही इसके कई विधायक दंगों के आरोप में जेलों में बद हैं, लेकिन इसको मुद्दा बनाने से पार्टी को नुकसान हो सकता है, इसलिए इस मसले पर फूंक-फूंक कर कदम रखा जाएगा. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों तक ही इसे भाजपा सहेज कर रखना चाहती है. पार्टी का सारा जोर विकास और भ्रष्टाचार के अलावा कांग्रेस-सपा और बसपा को एक ही पाले में खड़ा दिखाने की होगी. कोशिश इस बात की भी कि जाएगी जनता को तीसरे मोर्चे की हकीकत बताई जाए. इनके दिमाग में यह बात बैठा दी जाएगी कि दरअसल, तीसरे मोर्चे का राग अलापने वाले नेता हमेशा चुनाव के बाद कांग्रेस की गोद में बैठ जाते हैं. यही इनकी हकीकत है. ऐसा एक-दो बार नहीं अनेक बार देखने में आया है. कांग्रेस-सपा और बसपा को मोदी ने तिकड़ी की उपाधि दी.

मोदी के भाषण की शुरुआत भारत माता की जय से और समापन वंदे मातरम से हुआ. मोदी के राज्य में पहले चुनावी भाषण से यह भी तय हो गया है कि भाजपा आलाकमान यूपी में में ऐसे हालात नहीं पैदा करना चाहता है, जिससे उसके खिलाफ वोटों के ध्रुवीकरण की स्थिति पैदा हो. इसे पता है कि विरोधी दलों के तमाम नेता लगातार प्रयासरत हैं कि किसी भी तरह से मोदी का हौवा दिखाकर मुसलमानों को अपने पाले में खड़ा किया जा सके. इसकी काट के लिए मोदी हिन्दुओं को अच्छा हिन्दू तो मुसलमानों को अच्छा मुसलमान बनने का पैगाम देते हैं. इसके पीछे का संदेश साफ है कि उन्हें किसी जाति-धर्म से परहेज नहीं है. यूपी में भी वह 'नेशन फस्ट' की थ्योरी पर ही आगे बढ़ते दिखे. मोदी को पता है कि यूपी वालों के दिमाग में अटल की छवि एक नायक की तरह थी, वह हिन्दुओं-मुसलमानों के बीच सर्वमान्य नेता थे, इसीलिए उन्होंने खुद को अटल जैसा दिखाने की कोई कसर नहीं छोड़ी. उनके बारे में वह खूब बढ़-चढ़कर बोले. मोदी और भाजपा की बदली सोच ने कांग्रेस और सपा-बसपा को अपनी चुनावी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया है. वह इस बात से हैरान हैं कि मोदी के मुंह से साम्प्रदायिक शब्द नहीं सुनाई दे रहे हैं, विरोधी दलों के नेता लगातार इस कोशिश में हैं कि मोदी किसी विवादित मुद्दे पर बोले और वह इसे लपक लें, ऐसा होता न देख विरोधी दलों के नेता तिलमिलाए हुए हैं. मोदी के खिलाफ असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं.

बहरहाल, उत्तर प्रदेश में मोदी के आगाज की बात की जाए तो उन्हें अच्छे नंबर दिए जा सकते हैं. कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी कि रैलियों के बाद कानपुर में जिस तरह मोदी को सुनने के लिए हुजूम उमड़ा वह कांग्रेस के लिए किसी सदमे से कम नहीं रहा. उसे नरेन्द्र मोदी की रणनीति समझ में आने लगी हैं. वे विकास के मसले पर खुद को केंद्रित कर रहे हैं. मोदी के पास केन्द्र पर हमला करने के लिए मानो पूरा आसमान खुला पड़ा है. वहीं कांग्रेस के पास गुजरात राग के अलावा कुछ नहीं है. कांग्रेस मोदी के गुजरात के नाम पर घेरना चाहती है तो मोदी कहते हैं कि यह चुनाव तो केन्द्र के हैं तो केन्द्र की बात क्यों न हो. गुजरात की जनता ने तो उन्हें गुजरात में तो पास (जीता) कर दिया था.

मोदी तमाम अड़चनों और विरोध को अनदेखा कर हिंदुत्व के मुद्दों से अपने आप को परे रखने की कोशिश कर रहे है. वह जानते और समझते हैं कि इनकी रैलियों में युवाओं की अच्छी खासी भागेदारी रहती है, जो मजबूत वोट बैंक भी है. यह वर्ग धर्म की बजाय रोजगार की बात सुनना चाहता है. इसीलिए उनके ऐसे बयान भी आ रहे हैं, जो उनकी पार्टी के कुछ कट्टर छवि वाले नेता और भाजपा के दूसरे संगठनों के आकाओं को शायद ही मंजूर हों. उनके शौचालय पहले देवालय बाद में वाले बयान पर हंगामा मचा, लेकिन मोदी निश्चिंत दिखे. उनका उन्नाव में खजाने की खुदाई पर जो रुख था, वह भी उनकी पार्टी लाइन से थोड़ा अलग था. बात यूपी की ही कि जाए तो 19 अक्टूबर को कानपुर में शंखनाद रैली में अपने भाषण से उन्होंने यूपी में विकास का एजेंडा तय कर दिया है. विपक्ष को समय रहते संभल जाना चाहिए. वह जितनी जल्दी यह बात समझ लेंगे कि मोदी अपनी जीत पक्की करने के लिए जातिवाद और धर्मवाद की दीवार गिरा देना चाहते है, उतना ही उनके लिए अच्छा होगा. मोदी की कट्टर हिन्दू वाली छवि बदल रही है, इस बात का अहसास कुछ मुस्लिम धर्म गुरुओं के मोदी को लेकर आए हालिया बयान स्पष्ट संकेत देते हैं. मौलाना मदनी के बाद प्रसिद्ध शिया धर्म गुरु मौलाना कल्बे सादिक का यह कहना कि अगर मोदी अपनी कथनी-करनी में

(शेष पृष्ठ 18 पर)

मोदी की रैली का 'पोस्टमॉर्टम'

भाजपा के पीएम पद के उम्मीदवार नरेन्द्र मोदी के यूपी आगमन के साथ ही उनकी रैलियों और उनका 'पोस्टमॉर्टम' करने में विरोधी जुट गए हैं. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मी कांत वाजपेयी ने मोदी की कानपुर रैली को ऐतिहासिक करार दिया और छह लाख की भीड़ का दावा किया. वहीं सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने मोदी का नाम लिए बिना कहा कि गुजरात से आए कई लोग यूपी में घूम रहे हैं,जिनका कोई वजूद नहीं है. वहीं कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने मोदी की रैली की तुलना सर्कस से कर डाली, जबकि प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता जीशान हैदर, जो गत दिनों राहुल की रैली को सफल बताते हुए ताल ठोंक रहे थे, मोदी की रैली से नाखुश दिखे. उनका कहना था कि मोदी ने देश में गरीबों की सरकार बनाने का वादा किया है, जबकि उनकी गुजरात सरकार को कॉरपोरेट जगत और अमीर लोग चला रहे हैं. जीशान ने आरोप लगाया कि जबसे मोदी ने अमित शाह को यूपी में भेजा है, तब से प्रदेश में दंगे हो रहे हैं. वहीं केन्द्रीय इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने मोदी की रैली की सफलता का सेहरा मुलायम के सिर बांध दिया. बेनी का कहना था कि मुलायम चाहते हैं कि केन्द्र में भाजपा की सरकार बने, लेकिन यदि केन्द्र में यूपीए की सरकार आएगी तो सपा सरकार को बर्खास्त कर दिया जाएगा.

मोदी की रैली का सबसे कायदे से पोस्टमॉर्टम समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र चौधरी ने किया. उनका कहना था कि कानपुर में भाजपा के दूसरे नम्बर के पीएम इन वेटिंग नरेन्द्र मोदी की विजय शंखनाद रैली पूरी तरह ढपोरशंख रैली बनकर रह गई. लाखों की भीड़ बटोरने का दावा करने वाले कुछ हजार ही लोगों को ला सके. 10 करोड़ से भी ज्यादा की धनराशि फूंककर भाजपा ने जो तमाशा खड़ा किया, इसमें प्रदेश के किसानों, गरीबों और आम जनता का अता-पता नहीं था. भीड़ पूरी तरह प्रायोजित थी और संघ, विहिप तथा भाजपा जैसे संगठनों का काम मोदी की सभाओं के लिए भीड़ के ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करना रह गया है. यही प्रायोजित भीड़ सभी सभाओं में ले जाई जाती है. एक तरह से यह जनता विहीन रैली थी. करोड़ों के खर्च पर भीड़ जुटाने की यह प्रवृत्ति राजनीति में आई विकृति की सूचक है.

चौधरी का कहना था कि संघ ने मोदी को पीएम बनाने की जो मुहिम चलाई है, इसे कहीं से जनसमर्थन नहीं मिल रहा है. समाज के सभी वर्ग इन रैलियों से दूर हैं. केवल संघ के गणवेशधारी, विहिप, बजरंग दल के लोगों को लेकर भाजपा का भौकाल बनाया जा रहा है. इस भौकाल पर जब प्रदेश में रैलियों के नाम पर ही 400 करोड़ रुपये खर्च करने का मोटा अनुमान है तो पूरे देश में मोदी के नाम पर हजारों करोड़ का खर्च आना स्वाभाविक है. इतना धन बड़े कॉरपोरेट घराने ही देने में सक्षम हैं और उन्होने ही मोदी को गोद लिया हुआ है. राजनीति और सत्ता पर पूरी तरह काबिज होने का यह कॉरपोरेट षड़यंत्र चिन्ताजनक है.

भाजपा नेतृत्व अब पूरी तरह अपनी फासिस्ट प्रवृत्तियों को उजागर करने लगा है. कानपुर की रैली में गणेश शंकर विद्यार्थी द्धार बनाकर उसने कानपुर की जनता और सम्पूर्ण स्वतंत्रता आंदोलन के साथ गहरा विश्वासघात किया है. श्री गणेश शंकर विद्यार्थी ने हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिए ख़ुद को बलिदान कर दिया था. ■

feedback@chauthiduniya.com

मुलायम राजनीति : एक बयान के कई अफ़साने

संजय सक्सेना

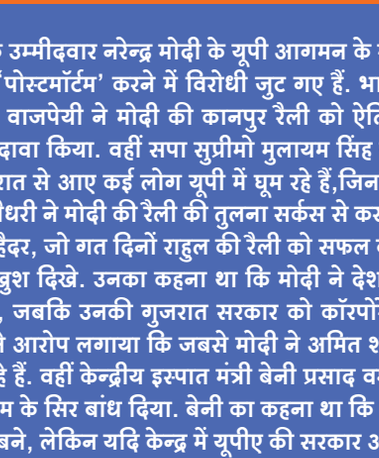

राजनीति भी बड़ी बेवफा होती है. नाते-रिश्ते बेमानी हो जाते हैं. नेताओं को अपने स्वार्थ और महत्वाकांक्षा के अलावा कुछ दिखाई-सुनाई नहीं देता है. अगर ऐसा न होता तो सपा प्रमुख मुलायम सिंह एक कार्यक्रम में सार्वजनिक रूप से अपने पुत्र की सरकार के संबंध में यह कहने की हिमाकत नहीं करते कि अखिलेश सरकार के मंत्रियों और सपा विधायकों से नाराजगी की सजा जनता उन्हें न दे. सपा प्रमुख खुद को सरकार और संगठन से अलग दिखा कर न जाने किस सोच को आगे बढ़ा रहे हैं. लगता है कि प्रधानमंत्री बनने के अति उत्साह में वह यह भी भूल गए हैं कि सपा सरकार और संगठन उन्हीं के संरक्षण में चल रहा है. वह संगठन के घोषित तो सरकार के अघोषित मुखिया हैं. समय-समय पर वह दोनों को ही दिशा-निर्देश देते रहते हैं. उन्होंने ही सपा को इस मुकाम तक पहुंचाया है. अगर सपा की कामयाबी का सेहरा उनके सिर बंधता है तो नाकामयाबी की कीमत भी उन्हें ही चुकानी पड़ेगी. मुलायम जितने भोलेपन से खुद को अपनी ही सरकार और उसके मंत्रियों, विधायकों के बुरे आचरण से परे रखने की साजिश रच रहे हैं, जनता उतनी ही चालाकी से उनकी राजनीति को भांप रही है.

सपा प्रमुख में जिस तरह की हताश दिखाई दे रही है, उससे तो यही लगता है कि विजय 2012 के बाद उन्हें मिशन 2014 दूर दिखाई दे रहा है. समाजवादी सरकार के दो साल भी पूरे नहीं हुए हैं और वह तमाम विवादों में घिर गई है. समाज से लेकर अदालत तक में इसकी थू-थू हो रही है. ऐसे में मुलायम का खुद को सपा के मंत्रियों और विधायकों की कार्यशैली से अलग दिखाने की कोशिश वाला उनका बयान कहीं न कहीं उनकी निराश और असहाय स्थिति को स्पष्ट करता है. यह तो 2014 के नतीजे ही बताएंगे कि मतदाता राज्य सरकार सरकार के कर्मों की सजा मुलायम को देगी या नहीं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि इससे पार्टी प्रमुख अछूते रह पायेंगे.

मतदाता शायद मुलायम की बातों पर गौर कर भी लेता, लेकिन वह यह नहीं भूला है कि आज जैसे अखिलेश सरकार की आलोचना हो रही है, वैसा ही समय उसने मुलायम काल में भी देखा है. पिता-पुत्र दोनों की ही सरकारों में कोई अंतर नहीं है. मुलायम राज में भी गुंडागर्दी चरम पर थी और अखिलेश राज में भी ऐसा ही हो रहा है. राजनीति के मैदान में पिता-पुत्र कार्बन कापी लगते है. इसके अलावा यह तथ्य भी सत्य है कि अखिलेश सरकार खुद उनके निर्देशन में ही चल रही है. इसके अतिरिक्त जनता को यह भी याद है कि कई बार विवादित फैसले लेने के बाद भी सपा प्रमुख अपने पुत्र की सरकार को क्लीन चिट् देने का काम कर चुके हैं. समय-समय पर सब कुछ दुरुस्त कर देने का दावा करने के साथ ही अखिलेश सरकार के मंत्रियों को ठीक करने की भी घोषणा भी वह अक्सर करते रहते है. मुजफरनगर दंगों के दौरान भी उन्होंने ऐसा ही किया.

यह सच है कि नेताजी कई मौकों पर राज्य के मंत्रियों को सुधरने की हिदायतें दे चुके है. वह प्रदेश की समस्याओं के लिए नौकरशाही को कई बार कोस चुके हैं, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया, जिससे यह लगे कि वह सरकार की छवि बदलने को बेचैन हैं. उनकी सारी राजनीति एक वर्ग विशेष को खुश करने में खप रही है. चाहे अयोध्या में पंचकोशी परिक्रमा का मामला हो या फिर नवरात्र के दौरान मूर्ति विसर्जन के कार्यक्रमों पर रोक का मामला अथवा दंगों के समय किया गया उनकी सरकार का भेदभाव पूर्ण आचरण किसी भी समय उन्होंने अखिलेश सरकार को यह हिदायत नहीं दी कि वह राज धर्म अपनाएं. मुलायम की राजनीति आज दोराहे पर खड़ी हैं तो इसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार हैं. यह इत्तेफाक नहीं हो सकता है कि एक तरफ तो वह प्रदेश के मंत्रियों और नौकरशाहों के कामकाज से असंतुष्ट नजर आते हैं और दूसरी तरफ सरकार को कामयाब बताते है. क्या ऐसा संभव है कि किसी सरकार के मंत्री सही ढंग से काम न कर रहे हों और फिर भी वह कामयाबी की ओर बढ़ रही हो.

उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार से नाराजगी के बाद भी इस सरकार को समर्थन की बात तो समझ में आती है, लेकिन यही रवैया केन्द्र को लेकर भी है. हाल में ही मुलायम ने बयान दिया था कि केन्द्र में कांग्रेस सरकार के रहते देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं रह गई हैं. देशवासी बेरोजगारी, मंहगाई और भ्रष्टाचार से त्रस्त हैं. घोटालों में केन्द्र के कई मंत्री हटाए गए हैं. केद्र सरकार ने सच्चर कमेटी बनाई थी, जिसने मुस्लिमों की हालत दलितों से भी बदतर बताते हुए अपनी रिपोर्ट में इन्हें विशेष सुविधाएं तथा आरक्षण देने की सिफारिश की थी, इसे भी लागू नहीं किया गया. यहां भी वह मूक दर्शक बने हुए हैं. दोनों जगह उनकी चुप्पी को जनता समझती है. ऐसे में वह यह कैसे सोच सकते हैं कि मतदाता उनके भोलेपन पर निछावर हो जाए. मुलायम के एक बयान के कई अफसाने राजनीति के गलियारों में सुनाई दे रहे हैं. विपक्ष हमलावर है तो उनकी पार्टी और सरकार इस मसले पर असहज महसूस कर रही है. ■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

आवश्यकता है

संवाददाता, विज्ञापन प्रतिनिधि, प्रसार प्रतिनिधि

चौथी दुनिया के लिए उत्तर प्रदेश के सभी मंडल और जिला मुख्यालयों पर अनुभवी संवाददाताओं, विज्ञापन और प्रसार प्रतिनिधियों की. पारिश्रमिक योग्यता अनुसार. शीघ्र आवेदन करें.

E-mail- konica@chauthiduniya.com
ajaiup@chauthiduniya.com
चौथी दुनिया F-2, सेक्टर 11, नोएडा
(गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश-201301,
PH : 120-6450888, 6451999

गंगा के साथ हो रहा है छल

रेनु शर्मा

गंगा की सफाई का सवाल एक बार फिर राजनेताओं के छल का शिकार हुआ. इस अवसर पर भी उत्तराखण्ड के दो दिग्गजों की आपसी कलह सतह पर दिखी. मीडिया सम्मेलन का उद्घाटन करने पहुंचे उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने अपने हाथों अपनी पीठ थपथपाते हुए तालठोक कर दावा किया की पूरे उत्तराखण्ड में गंगा प्रदूषित नहीं है. हम देश के अन्य भागों में प्रदूषण मुक्त गंगा देते हैं. मुख्यमंत्री बहुगुणा के दावे की केंद्रीय जल मंत्री हरीश रावत ने हवा निकालते हुए सहज रूप से स्वीकार किया कि हम उत्तराखण्ड से ही स्वच्छ गंगा नहीं दे रहे है. उत्तराखण्ड में ही गंगा प्रदूषित होकर आगे बढ़ रही है. रावत ने कहा कि हम अविरल गंगा के बहने के समर्थक हैं. गंगा जैसी नदी का दूषित होना हमें दुखी करता है. उन्होंने धर्मगुरुओं को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि हमें गंगा का जयकारा लगाकर इसको प्रदूषित करने की नीति का परित्याग करना चाहिए. उन्होंने कहा कि गंगा में मूर्ति विसर्जन, गंदा तेल, प्लास्टिक और कचरा डालने से बचना चाहिए. उन्होंने सर्वोच्च न्यायलय के आदेश (गंगा नदी के दो सौ मीटर के दायरे में हुए निर्माण को हटाने और निर्माण पर कड़ाई से रोक) का पालन करने की बात कहते हुए कहा कि इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए कि हिमालय में आई आफत में भी सर्वाधिक क्षति गंगा की कोख में बनाए गए भवन, होटल, मकानों की हुई है. इस घटना से हमें अपनी आंखे खोल लेनी चाहिए. इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने भी अपने आदर्श डॉ.राम मनोहर लोहिया और गांधी के नाम का सहारा लेकर खूब राजनीतिक भाषण दिया और कहा कि गंगा में जितनी नदियां मिल रही हैं, उन्हें भी साफ किया जाना चाहिए. उन्होंने घोषणा की कि कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा से यमुना की सफाई का काम उत्तरप्रदेश सरकार शुरू करेगी. मथुरा में हम एक भी सीवर (गन्दा नाला) नहीं गिरने देंगे. उन्होंने दिल्ली सरकार से यमुना में गिरने वाले अठ्ठारह गन्दे नालों को तत्काल रोकने की मांग की. इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बीएल जोशी काफी भावुक दिखे, उन्होंने धर्मिक भावना से गंगा में दी जाने वाली जल समाधि को बन्द करने की मांग की. इस अवसर पर मीडिया के मध्य गंगा के अधिकार हमारे अधिकार है, का नारा देने वाले परमार्थ आश्रम के संत चिदानन्द मुनि सबसे अधिक बेपर्दा हुए. मंच से आईएफडब्लूजे के राष्ट्रीय महासचिव परमानन्द पाण्डेय ने साफ-साफ कहा कि गंगा की आरती करने वाले सबसे ज्यादा गंगा को प्रदूषित कर रहे हैं. इन ढोंगियों के ढोंग को पचकार साथी उजागर करें. पाण्डेय का इतना कहना था कि देश-विदेश से आए कई नामचीन पत्रकारों के कैमरे का मुंह परमार्थ आश्रम की ओर घूम गया. पत्रकारों के समक्ष मुनी जी का दोहरा चरित्र उजागर हुआ. परमार्थ घाट से लगे आश्रम के नाले से आ रही सड़ान्ध और गंगा की छाती पर परमार्थ आश्रम द्वारा किए गए अवैध निर्माण की चर्चा रही थी. होटल नहीं हट संस्कृति की बात करने वाले मुनिजी द्वारा सर्वाधिक सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन कर कंकरीट का जंगल उगाने और मंच पर हरियाली, हर्बल, हरी पट्टी बनाने की बात पूरी तरह खोखली दिखी. श्रीलंका से आए पत्रकारों को मुनी जी की कथनी-करनी पर सबसे ज्यादा हैरानी हुई. स्थिति यह रही की मीडिया को गंगा की सफाई की घुट्टी पिलाने वाले मुनि जी नज़र चुराते नज़र आए. मीडिया का नदी पर आयोजित यह सम्मेलन कितना सफल-असफल रहा, इसका आकलन करना अभी जल्दबाजी होगी, पर इतना जरूर रहा कि देश विदेश से आए पत्रकारों को देवभूमि के राजनेताओं और संतों के दोहरे चरित्र से दो-चार होने का मौका मिला. इस ऐतिहासिक सम्मेलन की अध्यक्षता यूनीवन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के.विक्रम राव ने की. सभी अतिथियों को विभिन्न प्रान्तों से आए पत्रकारों ने अपने स्मृति उपहार भेंट किया. इस प्रकार उत्तराखण्ड की देवनगरी ऋषीकेश के परमार्थ आश्रम गंगातट पर तीन दिवसीय आईएफडब्लूजे का गंगा की सफाई में मीडिया की भूमिका विषय पर आयोजित सम्मेलन सम्पन्न हुआ. ■

यूपी में चुनावी रोडमैप तय कर गए मोदी

पृष्ठ 1 का शेष

फर्क खत्म कर देते हैं तो वह इन्हें खुद वोट देंगे, सादिक का बयान बताता है कि मोदी को लेकर मुस्लिम धारणा बदल रही है. मोदी अपनी छवि बदलने के लिए जनता के बीच में मूलभूत सुविधाओं की कमी और भ्रष्टाचार को लेकर विपक्षी दलों पर लगातार करारा प्रहार कर रहे है. वह सभी को साथ लेकर चलने की बात करते हैं. भाजपा मुसलमानों में पैठ बनाने की भी कोशिश करना चाहती है, पर अभी यह दूर की कौड़ी है. अयोध्या की चर्चा के बिना मोदी की रणनीति को समझना सही नहीं होगा. भाजपा के पीएम पद के उम्मीदवार घोषित होने के बाद चर्चा शुरू हुई कि मोदी यूपी में अयोध्या से ही चुनावी बिगुल फूंकेंगें. इसका कारण भी था. मोदी के दूत अमित शाह (उत्तर प्रदेश भाजपा के चुनाव प्रभारी) ने यूपी आते ही रामलला के दरबार में माथा टेका था. विरोधियों ने तब इसको खूब हवा भी दी थी. मोदी ने रामलला को राजनीतिक मुद्दा नहीं बना कर अपने लिए तो राह आसान की ही, भाजपा को हंसी का पात्र बनने से भी बचा लिया, क्योंकि अब जनता को भाजपा नेताओं के मुंह से राम लला का नाम अच्छा नहीं लगता है. वह राम राज्य की भी कल्पना नहीं कर रहे हैं. उन्हें पता है कि इससे कुछ लोगों को आपत्ति होती है. अब इनके द्वारा भारतीय संविधान और राष्ट्रभक्ति को ही धर्म के रूप में परिभाषित किया जाता है. पार्टी के कुछ जिम्मेदार नेता, जो पार्टी की दुर्दशा से दुखी थे, वह कहते हैं कि अटल जी के समय पार्टी के पास हिंदुत्व के साथ विकास का मुद्दा भी था. इनसे सभी जाति धर्म और मजहब के लोगों का लगाव था. मोदी भी कुछ ऐसी ही छवि बनाने की कवायद कर रहे हैं तो कुछ लोग हिन्दुत्व से भागते मोदी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं. इन लोगों का दो टूक कहना है कि जब तक राम मंदिर निर्माण मुद्दे की कमान भाजपा के अनुवांशिक संगठन विश्व हिंदू परिषद के हाथ में है, तब तक मोदी की सारी कोशिशें बेकार जाएंगी. मोदी शायद यह भरोसा देशवासियों में जगाने में कामयाब नहीं होंगे कि वे बदल गए हैं या बदल रहे हैं. एक और बात नरेन्द्र मोदी की कानपुर रैली की सफलता ने पीएम इन वेटिंग के अलावा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह को भी गदगद कर दिया है. कानपुर की रैली की सफलता को लेकर राजनाथ सिंह काफी चिंतित थे. वह जानते हैं कि यूपी में भाजपा का झंडा ऊंचा होगा तो उन्हें भी इसका श्रेय मिलेगा. केन्द्र की राजनीति में इनकी ताकत में चार चांद लगेंगे. यूपी राजनाथ का गृह राज्य है और यहां भाजपा को संकट से उबारने के लिए राजनाथ काफी गंभीरता से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उनके सामने चुनौती कम नहीं है. ■

नगर सहकारी बैंक लि. गोरखपुर

नगर सहकारी बैंक लिमिटेड, गोरखपुर के समस्त अंशधारकों, ग्राहकों एवं कर्मचारियों के की तरफ से जनपदवासियों को दीपावली, छठ व कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं.

जितेंद्र बहादुर सिंह
अध्यक्ष

अजय कुमार सिंह
सचिव

प्रत्याशी बदल कर सपा चल रही जीत का दांव

जयप्रकाश ओझा
feedback@chauthiduniya.com

संतकबीरनगर में मिशन 2014 की तैयारियों में जुटी समाजवादी पार्टी ने संतकबीरनगर लोकसभा सीट के लिए अपना तय प्रत्याशी बदल दिया है. पूर्व विधायक अब्दुल कलाम को बदल कर सपा ने इस सीट से पूर्व सांसद भालचंद यादव को टिकट थमा दिया है. इस खबर के आम होते ही जैसे जिले का राजनीतिक तापमान अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गया है और सभी दलों ने अपनी रणनीति नये सिरे से बनाने का काम भी शुरू कर दिया है. संतकबीरनगर की लोकसभा सीट पूर्वांचल की बेहद महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है. तीन-तीन मंडलों में फैली इस लोकसभा सीट का अपना एक अलग मिजाज है. लगातार चार बार से हुए चुनावों में यह सीट बारी-बारी से भालचंद यादव और फिर बसपा से सांसद भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी के हाथों में आती रही है. अल्पसंख्यक मतदाताओं की मजबूत संख्या वाली इस लोकसभा सीट पर सपा ने इसके पहले पूर्व विधायक अब्दुल कलाम को टिकट दिया था. तब भालचंद यादव बसपा में थे, लेकिन इसी बीच तेजी से घटनाक्रम बदला और बसपा से भालचंद को बाहर कर दिया गया तो उन्होंने सपा से दोबारा टिकट पाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी. अब जबकि इस सीट पर सपा ने अब्दुल कलाम के बदले भालचंद यादव को टिकट दे दिया है तो ऐसे में राजनीतिक समीक्षक इस बदलाव को सपा के हित में मान रहे हैं.

भालचंद यादव को प्रत्याशी बनाने के साथ ही सपा हाई कमान ने इस निर्णय की जानकारी सपाइयों को देने के लिए 17 अक्टूबर को जिला मुख्यालय पर एक बड़ी रैली की. इस रैली में जिस तरह से बिन बुलाए ही हजारों की भीड़ ने पूरे दम खम से भालचंद यादव की घर वापसी का स्वागत किया और इस सीट को सपा को जिताने का वादा किया इससे यह तो तय हो गया कि भालचंद यादव का जादू आज भी मतदाताओं पर बरकरार है.

सपा का साइकिल से पुराना नाता

रवि प्रकाश

समाजवादी पार्टी की नीतियों और सरकार की उपलब्धियों को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए 14 मार्च 2013 से प्रारंभ प्रदेश के सभी 75 जनपदों की 10 हजार किलोमीटर की यात्रा पूरी कर लखनऊ वापस आने पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने समाजवादी साइकिल यात्रा दल के नायक रणजीत बच्चन तथा नायिका सुश्री कालिन्दी निर्मल शर्मा का लखनऊ में स्वागत किया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी का साइकिल से पुराना नाता रहा है. अन्य सभी दलों से ज्यादा युवा समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं. वे आधुनिक तकनीक के भी जानकार है. वैसे युवाओं के सामने बड़ी चुनौती है. उन्हें समानता खुशहाली और बेहतर जीवनस्तर के लिए काम करना है. समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी उपलब्धि यह भी है कि हमने जनता का धन जनता तक पहुंचाया है. सरकार की योजनाओं से गरीबों, पिछड़ों, मुस्लिमों, नौजवानों सभी को लाभ पहुंचा है. हमने लैपटाप बांटे, 10वीं पास मुस्लिम लड़कियों को 30 हजार रुपये, 12वीं कक्षा पास को 30 हजार रुपये दिए. मुफ्त सिंचाई, किसान की कर्ज माफी, 108 एम्बुलेंस सेवा, मुफ्त दवाई की व्यवस्था की. इतना कुछ दूसरे राज्य नहीं कर पाए है. आर्थिक संसाधन जुटाकर और धन की फिजूलखर्ची रोककर हमने अपने चुनावी वायदे भी पूरे किए है. प्रदेश में बिजली के 4 हजार मेगावाट के प्लांट लगने जा रहे हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश जनहित की योजनाओं में मदद करने में पीछे नहीं है, लेकिन कुछ दल राजनीतिक बेईमानी कर रहे हैं. हम इनसे लोकतांत्रिक तरीके से निपटेंगे. लोकतंत्र में जनता जवाब देती है. ऐसी ताकतों से समाजवादी पार्टी भी लड़ेगी. उन्होंने कहा 108 एम्बुलेंस सेवा में केन्द्रीय मदद इसलिए रोकी गई, क्योंकि इसके आगे समाजवादी शब्द लगा है. समाजवादी शब्द तो संविधान सम्मत है. हमने अपने बूते इस सेवा को न केवल चलाने, अपितु बड़े जनपदों में एम्बुलेंस बढ़ाने का भी निश्चय किया है. इस सेवा से सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों को मदद मिलती है. हम स्वास्थ्य सेवा को बेहतर करना चाहते हैं. एमबीबीएस की सीटें बढ़ाई हैं. इस मौके पर साइकिल यात्री रणजीत बच्चन ने कहा कि वे 2014 में भी समाजवादी पार्टी की जीत के लिए काम करेंगे. उन्होंने कहा कि वह मुख्यमंत्री के व्यक्तित्व एवं समाजवादी सरकार के जनहित में विकासपरक कार्यों से प्रभावित हैं. दोनों साइकिल यात्रियों को शाल ओढ़ाकर और 5-5 लाख रुपये देकर सम्मानित किया गया. ■

feedback@chauthiduniya.com

यूपी:अनसुलझा नहीं रहेगा चर्चित सीएमओ हत्याकांड

रवि प्रकाश, लखनऊ

उत्तर प्रदेश के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ विनोद आर्य हत्याकांड की गुत्थी अनसुलझी नहीं रहेगी. डॉ आर्य की मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के लिए सीबीआई ने एसटीएफ से इस मामले में की गई तफतीश व साक्ष्य का ब्यौरा मांगा है. अदालत के आदेश के बाद जांच एजेंसी नये सिरे से इन साक्ष्यों के परीक्षण में जुट गई है. सीबीआई की लखनऊ परिक्षेत्र की क्राइम ब्रांच को जांच का काम सौंपा गया है. जांच टीम ने पूर्व सीएमओ डॉ एके शुक्ला की विभिन्न लोगों से बातचीत का टेप हासिल कर लिया है. एसटीएफ से मिले इस टेप का सीबीआई केंद्रीय प्रयोगशाला में परीक्षण कराकर दूध का दूध और पानी का पानी करेगी. डॉ आर्य हत्याकांड को चर्चित स्वास्थ्य घोटाले से जोड़कर देखा जाता रहा है. मायाराज में हुए इस घोटाले में कई मंत्रियों और नौकरशाहों को अपनी कुर्सी गवांना पड़ी थी और कई की जान भी चली गई थी.

गौरतलब है कि हाल में ही उच्च न्यायालय ने सीएमओ डॉ विनोद आर्य हत्याकांड में डॉ ए के शुक्ला को वलीन घिट देने वाली सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट खारिज कर दी थी और नये सिरे से जांच शुरू करने के आदेश दिए थे. अदालत ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट पर कई सवाल उठाए थे.आर्य हत्याकांड का एक दुखद पहलू यह भी है कि सीबीआई ने प्रारंभ में तो हत्या की साजिश के पीछे पूर्व सीएमओ डॉ एके शुक्ला, डिप्टी सीएमओ डॉ वाई के सचान व अन्य की संलिप्तता की आशंका वाली बात कही थी. जांच टीम ने डॉ शुक्ला को मुख्य साजिशकर्ता मानते हुए इन्हें गिरफ्तार भी किया था. सीबीआई द्वारा रिमांड मांगते समय तर्क दिया था कि डॉ शुक्ला हत्या में प्रयोग किए गए असलहे की बरामदगी के अलावा और कई राजफाश कर सकते हैं. इसके बाद सीबीआई ने अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी और कहा कि डॉ शुक्ला के खिलाफ हत्या की साजिश रचने कोई सबूत नहीं मिले हैं. अदालत ने जांच एजेंसी के इस रवैये पर सख्त रवैया अपनाया और क्लोजर रिपोर्ट पर प्रश्न चिन्ह लगा कर फिर जांच शुरू करने को कहा. लिहाजा सीबीआई ने नये सिरे से मामले की जांच शुरू कर दी. अब सीबीआई अधिकारी एसटीएफ और पुलिस की जांच रिपोर्ट का पुनर्परीक्षण कर रहे हैं. इसमें उन बिंदुओं को तलाशा जा रहा है, जिन पर पहले अधिक विस्तार से नहीं सोचा गया था. ■

महाराजगंज में भितरघात की राजनीति

पूजा श्रीवास्तव

भारतीय जनता पार्टी में भी यहां भितरघात की शिकार है. लंबे समय से इस लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है. वर्तमान समय में यहां एकबार फिर भाजपा की लहर चल रही है. चार बार लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके पंकज चौधरी भी अपनों के भितरघात के ही शिकार हो रहे हैं. एक दल से पूरी निष्ठा लगन के साथ पंकज चौधरी ने 1991 से अब तक प्रत्याशी रहे हैं और चार बार सांसद चुने गए हैं. उन्होंने अपनी व्यवहार कुशलता और परिश्रम से पार्टी को एक नया आयाम दिया जिसका नतीजा था कि आम जनमानस और पार्टी में किंगमेकर के रूप में जाने जाते रहे हैं, लेकिन इस बार उनको भी विरोधियों ने घेरना शुरू कर दिया है.

इस लोकसभा चुनाव की तिथि जैसे-जैसे पास आती जा रही है. वैसे-वैसे महाराजगंज जनपद का सियासी पारा चढ़ता जा रहा है. सभी राजनीतिक दल अपनी सक्रियता बढ़ाते जा रहे हैं. सपा-बसपा ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा काफी पहले ही कर दी हैं. वहीं कांग्रेस और भाजपा ने अभी तक अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है, लेकिन इन सबके बाद जो दिलचस्प बात नजर आ रही है. वह यह है कि जनपद में सभी दलों में भयानक भितरघात की स्थिति बनी हुई है. जिससे जनता ही नहीं, खुद घोषित प्रत्याशी भी हताशा के शिकार हो रहे हैं. यदि समाजवादी पार्टी पर नजर डाले तो सपा से एक बार सांसद रह चुके कुंवर अखिलेश सिंह को पार्टी ने इस बार फिर लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है. सिंह, सपा से सांसद थे और अपने को निष्ठावान समाजवादी मानते थे, लेकिन पिछले कई वर्षों से सपा से दूरी बना रखी थी क्योंकि उनके धुर विरोधी पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी सपा में जब से शामिल हुए तभी से उन्होंने पार्टी से किनारा कर लिया था. सपा की राजनीति में अमरमणि के परिवार का वर्चस्व रहा है और उनके परिवार की सपा में सक्रियता का नतीजा यह रहा कि अपने को निष्ठावान समाजवादी मानने वाले अखिलेश सिंह ने छोटे बेटे कुंवर सिंह को कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जिताकर लंबे समय के बाद अमरमणि के परिवार को पटखनी दी, क्योंकि इस विधानसभा सीट पर लंबे समय से अमरमणि त्रिपाठी का कब्जा रहा है. इस जीत के बाद एक बार फिर अखिलेश सिंह ने अपनी किस्मत आजमानी शुरू की है. उन्होंने रामगोपाल के पुराने नजदीकी होने का लाभ उठाते हुए मणि परिवार को एक और शिकस्त दी. एक दशक बाद फिर सपा की राजनीति में सक्रिय होकर और लोकसभा प्रत्याशी घोषित हुए. लेकिन इस शह-मात के खेल में अखिलेश खुद फंस गए, क्योंकि एक दशक बाद सपा के निष्ठावान उन्हें पचा नहीं पा रहे हैं. इस अवधि में अखिलेश सिंह ने अपने को अलग कर रखा था. इसका नतीजा यह हुआ जनपद में सपा दोनों विधायकों (सुदामा प्रसाद और शिवेंद्र सिंह) ने आज भी अखिलेश से दूरी बनाई हुई है. वहीं अमरमणि त्रिपाठी के चाचा व पूर्व मंत्री श्यामनारायण त्रिपाठी, अजितमणि त्रिपाठी और लक्ष्मीपुर विधानसभा के प्रत्याशी व बेटे अमनमणि त्रिपाठी तो शुरू से ही विरोध में हैं. संगठन भी इन दोनों की लड़ाई में फंसा है, क्योंकि उसे लगता है कि लोकसभा के सभी विधानसभाओं में सपा दो भागों में बटी हुई है और अखिलेश अपने लोगों से ही भयभीत हैं. आए दिन अफवाहों का बाजार गरम रहता है कि सपा प्रत्याशी बदल दिए गए जिससे जनता और खुद सपा जिला संगठन भी असमंजस में दिखता है और संगठन के पदाधिकारी यह कह कर बचते नजर आते हैं कि यह ऊपर वालों की लड़ाई है. वहीं बहुजन समाज पार्टी ने साल भर पहले ही इस लोकसभा में ब्राह्मण मतों को सहेजने के लिए काशीनाथ शुक्ला को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया था जो पूर्व में लोकसेवक थे. वर्तमान में वे एक स्थापित बिल्डर बताए जाते हैं और कई देशों में अपना कारोबार फैला रखा है.

ऐसे में पार्टी के कार्यकर्ता व जनता उन्हें बाहरी मानकर चल रहे हैं और वहीं उनके क्रिया-कलाप उनको विवादों के घेरे में खड़ा कर दे रहा है, क्योंकि वे ब्राह्मण वोटों को सहेजने में मूल बसपा कैडर से दूर होते जा रहे हैं और संगठन दो भागों में नजर आने लगा है. संगठन के लोगों का आरोप है कि वे संगठन और बसपा के कार्यकर्ताओं कि उपेक्षा कर रहे हैं वहीं ब्राह्मण समाज ने भी उनसे दूरी बना रखी है. उनका कहना कि बसपा ने पूर्व लोकसभा चुनाव में गणेश शंकर पांडेय को प्रत्याशी बनाया था, जो मूलतः यहां के रहने वाले बड़े व्यक्ति थे और ब्राह्मण समाज उनके साथ रहा पर बसपा के मूल वोटरों ने साथ नहीं दिया. ऐसी स्थिति में काशीनाथ शुक्ला को बसपा का वोट कैसे मिल पाएगा?

वहीं एक तरफ से ब्राह्मणों के बड़े नेता गणेश शंकर पांडेय के लोग भी काशीनाथ शुक्ला को पचा नहीं पा रहे हैं. इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि पूर्वांचल में सपा की राजनीति में तिवारी जी के खेमे का वर्चस्व है. गणेश शंकर सभापति हैं ऐसी स्थिति में में गुट भी किसी ब्राह्मण को पूर्वांचल में जमने नहीं देगा. जिसका परिणाम है कि रोज बसपा में भी नए-नए प्रत्याशियों का नाम आता रहता है. काशीनाथ शुक्ला के अच्छे संबंध बसपा सुप्रीमो मायावती व उनके भाई आनंद के साथ होने के नाते वह मजबूती से ऊपर पैर जमाए हुए हैं. अब देखना होगा कि गुटबाजी खत्म कर कर जनाधार बना पाते हैं कि नहीं. कांग्रेस पार्टी में सर्वाधिक गुटबाजी और भितरघात खुलकर नजर आती है. चाहे संगठन हो या इनके जनप्रतिनिधि सभी स्वंयभू नेता हैं. इस समय इस लोकसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा है. पिछले चुनाव में कर्जमाफी, मनरेगा और सहानुभूति की आंधी ने हर्षवर्धन सिंह को चुनाव जिताकर यह सीट कांग्रेस की झोली में डाली थी और कांग्रेस के टिकट बंटवारे पर नजर डालें तो वर्तमान सांसद ही पुनः लोकसभा प्रत्याशी हो सकते हैं, लेकिन उनका चुनाव जीतना बहुत कठिन होगा, क्योंकि उन्होंने विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी को लेकर बहुत ही हो-हल्ला मचाया पर उनके इच्छा के विपरीत प्रत्याशी उतारे गए. वे भी अपने उनसे दो-दो हाथ करने को खड़े दिख रहे हैं. इस लोकसभा क्षेत्र से लक्ष्मीपुर विधानसभा क्षेत्र से कुंवर कौशल सिंह कांग्रेस के विधायक भी हैं और उनके सगे बड़े भाई कुंवर अखिलेश सिंह सपा के लोकसभा के प्रत्याशी हैं. वर्तमान सांसद और इस परिवार से वैचारिक पुराना मतभेद है. ऐसी स्थिति में कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ भितरघात होनी ही है. वहीं वर्तमान सांसद के मजबूत किले के रूप में मशहूर विधानसभा क्षेत्र फरेन्दा में सांसद के विरोध के बाद भी विधानसभा प्रत्याशी के रूप में विरेंद्र चौधरी ने अपनी किस्मत आजमाई और भितरघात के कारण चुनाव हार गए. उनकी अपनी टीस भी वर्तमान सांसद से है. वहीं पनियरा विधानसभा से आलोक प्रसाद और सिसवीं विधानसभा क्षेत्र से 10 जनपथ के निकट रहने वाले पूर्व सांसद जितेंद्र सिंह के पुत्र जय सिंह ये सभी वर्तमान सांसद के विरोध के शिकार हुए थे. जो अभी वर्तमान सांसद के विरोध को भूल नहीं पाए हैं. ऐसी स्थिति में कांग्रेस के वर्तमान सांसद के लिए हर तरफ मुश्किलें ही मुश्किलें हैं. ऐसी स्थिति से कांग्रेस आला कमान अवगत भी है, लेकिन प्रत्याशी जो भी हो संगठन कई धड़ों में बंटा हुआ है.

कुछ ऐसा ही हाल इस बार भारतीय जनता पार्टी में भी देखा जा रहा है. लंबे समय से इस लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है. वर्तमान समय में यहां एकबार फिर भाजपा की लहर चल रही है. चार बार लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके पंकज चौधरी भी अपनों के भितरघात के ही शिकार हो रहे हैं. एक दल से पूरी निष्ठा लगन के साथ पंकज चौधरी ने 1991 से अब तक प्रत्याशी रहे हैं और चार बार सांसद चुने गए हैं. उन्होंने अपनी व्यवहार कुशलता और परिश्रम से पार्टी को एक नया आयाम दिया, जिसका नतीजा था कि आम जनमानस और पार्टी में किंगमेकर के रूप में जाने जाते रहे हैं, लेकिन इस बार उनको भी विरोधियों ने घेरना शुरू कर दिया है. भाजपा में पिछड़ों के बड़े नेता के रूप में उनकी छवि रही और पार्टी में ऊपर तक उनकी हनक को कम करने के लिए अब पार्टी के ही गोरखपुर के कुछ बड़े नेता उनकी घेराबंदी कर रहे हैं, जिसका परिणाम है कि पार्टी के रीतियों-नीतियों से जिन लोगों को कोई लेना-देना नहीं है, वे लोग भी टिकट की लाइन में लगे दिख रहे हैं. इसी क्रम में एनजीओ माफिया जो पूर्व में बसपा और पीस पार्टी से विधानसभा चुनाव लड़कर हार चुका है, उनके बैनर पोस्टर शहर में जहां-तहां देखे जा सकते हैं और बैनर-पोस्टर में लगे फोटो खुद बयान कर रहे हैं कि महाराजगंज में कौन हस्तक्षेप करके वहां का माहौल बिगाड़ रहा है. पंकज चौधरी के बढ़ते कद को रोकने के लिए जहां गोरखपुर में पार्टी के कुछ बड़े नेता खुरपेच कर रहे हैं. वहीं खुद संगठन के कुछ पदाधिकारी और पूर्व पदाधिकारी भी भितरघात में लगे हुए हैं. संघ की अपनी नाराजगी भी भीतरघात को बढ़ावा दे रही है, जबकि पंकज चौधरी की कार्यकर्ताओं और जनता में अपनी मजबूत पकड़ और मोदी की घोषणा के बाद जिले में भाजपा का ग्राफ आज भी सबसे ऊपर है. कार्यकर्ताओं और जनता का पंकज और पार्टी में विश्वास है. पार्टी के अंदर के इस भितरघात को और बाहरी हस्तक्षेप को रोका न गया तो इसका लाभ विरोधी दलों को मिल सकता है. अब देखना ये है कि अपनों के भितरघात से ये राजनीतिक पार्टियां कैसे लोहा लेती हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

कम्बल छोटा पड़े तो पैर मोड़ कर सो जाएंगे

संदीप कश्यप

उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार को अपने वायदे पूरे करने में काफी दांव-पेच लगाने पड़ रहे हैं. चुनाव के समय जनता को लुभाने के लिए समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में तमाम वायदे किए गए थे. बेरोजगारी भत्ता, इंटर पास लड़कियों को कम्प्यूटर, हाईस्कूल पास लड़कियों को लैपटॉप, सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू करना, सभी विश्वविद्यालयों मे छात्र संगठन का गठन और न जाने क्या-क्या वायदे. मगर सत्ता में आते ही ये वायदे सपा सरकार को कचोटने लगे. इतना पैसा सरकार के पास था नहीं कि तमाम वायदों को ह-ब-ह निभाए. इसके लिए वह इसमें कांट-छांट करने लगी है. आज की तारीख में यह बात दावे से कही जा सकती है कि शायद ही कोई ऐसा वायदा होगा, जो घोषणा पत्र के अनुरूप पूरा किया गया हो. समाजवादी सरकार की बदनीयती से गरीब भी नहीं बच पाए हैं. सरकार की तरफ से यह खबर छन-छन कर आ रही है. अंदरखाने की बातों पर विश्वास किया जाए तो गरीबों के हाथ में घोषणा पत्र के अनुरूप साड़ी और कम्बल आने से पहले ही इसके आकार में कटौती की चर्चा शुरू हो गई है. गरीबों को दी जाने वाली साड़ी-कम्बल का जो साइज तय किया गया था, इसे अब घटाया जा रहा है. बताते हैं कि साड़ी-कम्बल के आकार में कटौती का प्रस्ताव पंचायती राज विभाग राज्य जल्द ही मंत्रिमंडल के सामने पेश कर सकता है, ताकि इसकी मंजूरी मिलने के बाद साड़ी-कम्बल की खरीद प्रक्रिया शुरू करके लोकसभा चुनाव से पूर्व गरीबों में बांट दी जाए.

अखिलेश सरकार की मंशा के अनुरूप गरीबी रेखा के नीचे के परिवार की 18 साल से ऊपर की सभी महिलाओं को दो-दो साड़ियां. 60 साल से अधिक उम्र के पुरुषों को साल मे एक-एक कम्बल फ्री दिया जायेगा. बताते हैं पंचायती राज विभाग ने गरीब महिलाओ को दी जाने वाले कम्बल और महिलाओं की साड़ियों के लिए जो मापदंड तय किये थे उसके अनुसार साड़ी की लंबाई 5.50 मीटर और चौडाई 1.10 मीटर रखी गई थी.

की सभी महिलाओं को दो-दो साड़ियां. 60 साल से अधिक उम्र के पुरुषों को साल मे एक-एक कम्बल फ्री दिया जायेगा. बताते हैं पंचायती राज विभाग ने गरीब महिलाओं को दी जाने वाले कम्बल और महिलाओं की साड़ियों के लिए जो मापदंड तय किए थे, उसके अनुसार साड़ी की लंबाई 5.50 मीटर और चौडाई 1.10 मीटर रखी गई थी. इसके अलावा साड़ियों का वजन तथा अन्य तमाम मानक भी तय किए गए थे. गरीबों के लिए खरीदे जाने वाली कुल साड़ियों और कम्बलों में 75 फीसद खरीद प्रदेश के बुनकरों से की जानी है.

वैसे, इसके पीछे एक तर्क यह भी गढ़ा जा रहा है कि पंचायती राज विभाग ने साड़ियों और कम्बल का जो साइज निर्धारित किया था, इस साइज की साड़ियां और कम्बल यूपी के हथकरघा इद्योग से जुड़े बुनकर नहीं बनाते हैं. इस कारण पंचायती राज विभाग इनके मानक नये सिरे से तय कर रहा है. बहरहाल, कम्बल की लम्बाई छोटी होने से इसके हकदार थोड़ा दुखी तो हैं, लेकिन वह छोटा कम्बल भी छोड़ना नहीं चाहते हैं और चुटकी लेते हुए तर्क देते हैं कि लम्बाई कम होने से कोई खास समस्या नहीं होगी. बस कम्बल के हकदारों को इस कहावत को चरितार्थ करना पड़ेगा, जिसमें कहा जाता है कि इतना पैर पसारिए, जितनी चादर होए. कम्बल छोटा हुआ तो क्या, ठंडक तो मिटाएगा ही, पैर मोड़कर इसे कम्बल के अंदर कर लिया जाएगा. ■

कृषि उत्पादन मंडी समिति, गोरखपुर

जनपद वासियों को दीपावली चित्रगुप्त पूजन, छठ व कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं.

राम केवल तिवार,
सभापति/नगर मजिस्ट्रेट, गोरखपुर

विपुल कुमार,
सचिव

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

www.chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

04 नवंबर–10 नवंबर 2013

प्रदेश के जनपदों में करीब 1082 लाख चूजे पाले जा रहे हैं. इसके बावजूद भी 972 लाख ब्रायलर चूजे अन्य प्रदेशों से आयात करने पड़ते हैं. प्रदेश सरकार ने दूसरे प्रांतों में मुद्रा प्रवाह को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश कुक्कुट विकास नीति 2013 बनाई. इस नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जून 2013 में विशेष सचिव हृदयाशंकर तिवारी ने निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश को इसके उत्पादन के लिए प्रत्येक जिले में फॉर्मों की स्थापना का फरमान जारी किया.

जोर पकड़ रहे चुनावी दौरे

दशरथ प्रसाद यादव

बस्ती से बलिया दस संसदीय क्षेत्रों में स्थानीय क्षत्रपों की स्थिति निश्चित न होने के नाते पूर्वी उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं. भाजपा, सपा के नेतृत्वकर्ता लगातार दौरे पर हैं, तो कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी का दौरा सलेमपुर में निर्धारित होने के बाद स्थगित हो गया. बसपा एवं कांग्रेस के साथ इन चार दलों में प्रत्याशियों की होड़ आपस में भी लगी हुई है. सिर्फ बसपा ने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की थी, जिसे अब सपा ने भी पूरा कर दिया है, लेकिन कांग्रेस और भाजपा अभी साफ तौर पर प्रत्याशियों की घोषणा नहीं कर सकी हैं. अब पेट में बच्चा, शहर भर ढिंढोरा के तर्ज पर घोषणाएं दर घोषणाएं की जा रही हैं. इसे कहते हैं चुनावी मैनेजमेंट, जिसमें काम कम और मतदाताओं को अपने पक्ष में बहलाने का काम अधिक किया जाता है. अब राहुल गांधी 30 अक्टूबर को सलेमपुर आ रहे हैं.

पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश में जहां यादव क्षत्रपों में काट-छांटकर सपा ने अपने प्रत्याशी घोषित किए थे, उसमें इन दस जिलों में कोई यादव नहीं था, जबकि एक मुस्लिम प्रत्याशी था. अब देवरिया एवं संतकबीरनगर (खलीलाबाद) से दो यादवों को प्रत्याशी बनाया गया है. इनमें हैं पूर्व सांसद बालेश्वर यादव एवं भाल चन्द्र यादव. इनके जरिये सपा अपने मतदाताओं को साधने का प्रयास करेगी. भाजपा ने गोरखपुर से सर्वथा अग्रता वाले अपने सांसद योगी आदित्यनाथ के साथ पुराने चेहरों पर ही ज्यादा जोर देती दिख रही है. अलबत्ता पूर्व सांसद राम विलास वेदान्ती को लाने की बात सामने आई हैं और कैसरगंज से सपा सांसद ब्रजभूषण सिंह के सपा से हटने के नाते इस क्षेत्र में भाजपा एवं कांग्रेस ठाकुर मतदाताओं को साधने का प्रयास कर रही है. हालांकि बस्ती में सपा ने कैबिनेट मंत्री राज किशोर सिंह के अनुज बृजकिशोर सिंह डिंपल को प्रत्याशी बनाया है और राजा भैया की कैबिनेट में पुनर्वापसी का भी लाभ सपा को मिलने की सम्भावना है, लेकिन योगी आदित्यनाथ (भाजपा) कुंवर आरपीएन सिंह तथा जगदम्बिका पाल एवं राजा बांसी (तीनों कांग्रेस) को इससे कहीं क्षति होती नहीं दिखती हैं. महराजगंज से अखिलेश सिंह ठाकुर मतदाताओं में पकड़ बनाने में कितना सफल होंगे, वह भाजपा के पंकज चौधरी को जरूर क्षति पहुंचा सकेंगे. ऐसे में पूर्व प्रधानमंत्री स्व. चन्द्रशेखर के पुत्र एवं सपा सांसद नीरज शेखर को बलिया में लाभ मिलेगा, जबकि सलेमपुर में उनके बड़े भाई पंकज शेखर भाजपा एवं रविशंकर सिंह उर्फ पप्पू जी बसपा के बीच मत विभाजन का लाभ पूर्व सांसद हरिवंश सहाय को मिल सकता है.

किन्तु-परन्तु करते हुए डुमरियागंज से विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पाण्डेय जी सपा प्रत्याशी हैं. यहां हवा किसके पक्ष में जाएगी, कहना संभव नहीं है. बांसगांव सुरक्षित में भी भाजपा को योगी जी का समर्थन लाभ पहुचाएंगा. कुशीनगर में राधेश्याम सिंह सपा प्रत्याशी को गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह के साथ योगी जी के प्रत्याशी एवं बसपा के ब्राह्मण प्रत्याशी से दो-दो हाथ करने पड़ सकते हैं. बस्ती मण्डल के संतकबीरनगर (खलीलाबाद) से भालचन्द्र यादव को सपा प्रत्याशी से बस्ती में ठाकुर एवं यादव के समीकरण भी सुधरने के संकेत हैं. देवरिया से बसपा ने कमलेश को बदलकर ब्राह्मण के स्थान पर मुस्लिम प्रत्याशी घोषित कर दिया है. बहरहाल, बस्ती, डुमरियागंज, खलीलाबाद में बसपा का अपना जनाधार कहीं से कम नहीं हुआ है, लेकिन गोरखपुर, देवरिया, महराजगंज एवं बांसगांव में इनका प्रभाव कोई खास बढ़ा नहीं हैं. पुराने प्रत्याशी कितना सफल होते हैं, ये समय ही बताएगा. सलेमपुर में बसपा को पप्पू सिंह के रूप में एक बेहतर प्रत्याशी मिला हुआ है. बलिया में कांग्रेस सपा की प्रतिद्वंद्विता कर सकती है.

अभी मोहन सिंह एवं राम नरेश कुशवाहा तथा पूर्व में कामेश्वर उपाध्याय की मृत्यु होने के अवसर पर मुख्यमंत्री समेत सपा के लोगों का दौरा देवरिया, सलेमपुर के लिए लाभकारी हो सकता है. अमेठी में एम्स की शाखा एवं रेलवे फैक्ट्री के शिलान्यास से कांग्रेस ने पूर्वी जिलों मे पैर फैलाया है तो गोरखपुर मे एम्स एवं इन्जीनियरिंग विश्वविद्यालय एवं सिद्धार्थनगर में सिद्धार्थ विश्वविद्यालय की स्थापना से सपा ने अपने पक्ष में माहौल बनाया है. भाजपा मखौड़ा (बस्ती) से चौरासी कोसी परिक्रमा तथा हिन्दूवादी संगठनों के माध्यम से राष्ट्रवाद के प्रचार के साथ योगी आदित्यनाथ के तेवर का लाभ उठाने को आतुर है तो बसपा अपने मतदाताओं के बीच आरक्षण तथा सुशासन एवं दलितों के हितों को लेकर धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है. स्पष्ट कुछ न कह पाने की स्थिति में भी नेताओं की घोषणाएं जारी हैं. 2014 के निर्वाचन को लेकर सरगर्मियां बढ़ रही हैं. मतदाता मौन हैं. ■

सिद्धार्थनगर में विकास के नाम पर चुप्पी

सुनील मिश्रा

उत्तर प्रदेश का एक जिला-सिद्धार्थनगर है. इसकी अपने आप में एक अलग पहचान है. भगवान गौतम बुद्ध के नाम पर 1989 में इस जिले की स्थापना हुई और अगल-बगल जिलों से हटकर यह जिला माना जाता है. यहां का कालानमक चावल भी जनपद की पहचान कराता रहा है. जनपद में पांच विधानसभा क्षेत्र हैं. कपिलवस्तु, शोहरतगढ़, बांसी, डुमरियागंज तथा इटवा. यहां के विधायक माता प्रसाद पाण्डेय वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष भी हैं. समाजवादी पार्टी की सरकार में इन्हें दूसरी बार इस पद से नवाजा गया है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष महोदय का ध्यान जनपद की विकास की ओर नहीं जा रहा है. जनपद की सड़कें अपने नसीब को रो रही हैं. चाहे इटवा मार्ग हो या बांसी-बस्ती या बांसी-खलीलाबाद अथवा डुमरियागंज मार्ग ये सभी सड़कें खुद अपने आप में ही आने-वाले उच्चधिकारी तथा राहगीरों को रुला देती है, जबकि बड़े-बडे राजनेता भी इस मार्ग से गुजरते रहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य जनपद का कि विकास के नाम पर यहां के नेता भी चुप्पी साधे हुए हैं. सड़कों के अलावा बिजली, पानी और अन्य समस्याएं जनपदवासियों की नींद हराम कर देती है, लेकिन न ही राजनेता और न ही उच्च अधिकारियों का ध्यान इस पर जा रहा है, जबकि लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और 2014 में चुनाव होना निश्चित बताया जाता है. उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी का जनाधार बढ़ने की सम्भावना है, लेकिन देश की राजनीति इस बार मोदी बनाम राहुल पर केंद्रित होती दिख रही है. लड़ाई में इन्हीं दो पार्टियों की भिड़न्त हो सकती है. चुनाव के करीब आते किसका जादू चलेगा, यह तो वक्त बताएगा, लेकिन सभी बड़े राजनेताओं का ध्यान उत्तर प्रदेश के वोटरों पर विशेष रूप से लगा हुआ हैं. प्रदेश में पूर्वांचल का अपना एक अलग महत्व है. गोरखपुर और बस्ती मण्डल के नेताओं का अपना अलग ही राग रहता है. गोरखपुर लोकसभा सदर सांसद योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर की वजह से खास तौर से जाने जाते हैं. पूर्वांचल में गोरखनाथ मन्दिर का विशेष स्थान है, लेकिन गोरखपुर की जनता विकास चाहती है और विकास कोसों दूर दिखाई दे रहा. अब तक गोरखपुर में भाजपा की लहर रही है, क्योंकि सांसद से लेकर नगर विधायक एंव नगर निगम मेयर भाजपा के ही रहे हैं. यहां पर विकास अभी कोसों दूर है. वहीं खलीलाबाद जिले से लोकसभा सांसद बसपा के भीष्मशंकर तिवारी भी परचम लहराए हुए हैं. ऐसे में पूर्व सांसद भालचन्द्र यादव भी मैदान में सपा प्रत्याशी के रूप में दिखेंगे, जबकि भालचन्द्र यादव और सपा के बीच बसपा कार्यकाल मे काफी दूरियां हो गई थीं. पार्टी के नेता एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे, लेकिन समय बदला तो रुख भी बदले जिसका परिणाम यह रहा कि 2014 में खलीलाबाद से भालचन्द्र यादव ने सपा का दामन थाम लिया और पार्टी प्रत्याशी के रूप में सामने आ गए. जबकि भालचन्द्र यादव की नीति कुछ और ही रही है. वे सिद्धार्थनगर से चुनाव लड़ने का सपना देख रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका. भालचन्द्र यादव के लड़के प्रमोद यादव की जिला पंचायत अध्यक्ष सिद्धार्थनगर की कुर्सी भी चली गई. बात डुमरियागंज संसदीय सीट की करें तो गैर जनपद से आए जगदम्बिका पाल ने यहां पर अपना पांव पसार लिया है और पुन: भी सपना देख रहे हैं और डुमरियागंज लोकसभा क्षेत्र में खूब जमकर दौरा भी कर रहे हैं, लेकिन इस बार समीकरण कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि बड़े-बड़े धुरंधर राजनेता मैदान में दिख सकते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष माता प्रसाद पाण्डेय के नाम की भी चर्चा जोरों से चल रही है. और बसपा से मो. मुकीम तथा कांग्रेस से जगदम्बिका पाल तथा भाजपा से राजा जय प्रताप सिंह के नाम चर्चा में हैं. राजा जय प्रताप सिंह की अपनी अलग ही पहचान है. बांसी विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान में विधायक भी है. जनता और अधिकारियों की नजर में उनकी छवि एक अलग ही है. फिलहाल सभी बड़े दल के राजनेताओं का ध्यान उत्तर प्रदेश की सरज़मीं पर दिखाई दे रहा है. क्योंकि उत्तर प्रदेश अपने मे एक बहुत बड़ा राज्य है. कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में मजबूत होना चाहते हैं. लगातार राहुल गांधी का उत्तर प्रदेश की सरजमीं पर खूब तेजी के साथ दौरा करने की सम्भावना दिख रही है और आगामी लोकसभा चुनाव 2014 में कांग्रेस पार्टी के राजकुमार टिकट बंटवारे को लेकर खूब सोच-समझ कर उत्तर प्रदेश में फैसला करते नजर आ रहे हैं. ■

मुर्गीपालन को प्रोत्साहित करेगी सरकार

मारकण्डेय प्रसाद सिंह

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चूजा और अंडा उत्पादन योजना परवान नहीं चढ़ पा रही है. फॉर्म की स्थापना के लिए पशुपालन विभाग को व्यवसायी ढूंढे नहीं मिल रहे. मुद्रा प्रवाह और आयात रोकने की प्रदेश सरकार की मंशा साकार नहीं हो पा रही है. ऐसे में पशुपालन विभाग के माथे पर बल पड़ गया है. प्रदेश में प्रति वर्ष 108 करोड़ अंडे का उत्पादन होता है और 473 करोड़ अंडे का उपभोग होता है. प्रदेश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 365 करोड़ अंडे प्रति वर्ष अन्य प्रदेशों से मंगाने पड़ते हैं. यही हाल कुक्कुट मांस उत्पादन का है. प्रदेश के जनपदों में करीब 1082 लाख चूजे पाले जा रहे हैं, इसके बावजूद भी 972 लाख ब्रायलर चूजे अन्य प्रदेशों से आयात करने पड़ते हैं.

प्रदेश सरकार ने दूसरे प्रांतों में मुद्रा प्रवाह को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश कुक्कुट विकास नीति 2013 बनाई. इस नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के वास्ते जून 2013 में विशेष सचिव हृदयाशंकर तिवारी ने निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश को इसके उत्पादन के लिए प्रत्येक जिले में फॉर्मो की स्थापना का फरमान जारी किया. साढ़े तीन माह पूर्व जारी फ़रमान के सापेक्ष में गोरखपुर जनपद में अभी तक एक भी इकाई की स्थापना नहीं हो सकी, जिसके चलते प्रदेश सरकार की इस योजना पर बट्टा लगता नजर आ रहा है. मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. कृष्णप्रताप सिंह के अनुसार गोरखपुर जनपद में अभी तक कुल सात उद्यमिओं ने आवेदन किया है, इसमें से चार पर शासन की सहमति भी मिल चुकी है. उन्होंने उम्मीद जतायी कि शीघ्र ही चारों उद्यमी अपना व्यवसाय शुरू कर देंगे. पशुपालन विभाग की सूचना के मुताबिक, प्रथम चरण में प्रदेश में अंडे उत्पादन के लिए 5 वर्षों में 123 लाख कॉमर्शियल लेयर्स पक्षियों के फार्म की 410 इकाइयों की स्थापना करनी है. पांच वर्ष के भीतर 370 करोड़ अंडों का उत्पादन प्रति वर्ष होने लगेगा, जिससे दूसरे प्रांतों से अंडे मंगाने नहीं पड़ेंगे और आत्मनिर्भरता बढ़ेगी.

कुक्कुट विकास नीति 2013 के अंतर्गत स्थापित कॉमर्शियल लेयर फार्म योजना पर प्रकाश डालते हुए मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि कॉमर्शियल लेयर फॉर्म पर एक 1.8 करोड़ रुपये खर्च होंगे. अंडों के उत्पादन के लिए इस इकाई में 30 हजार पक्षियों को रखा जाएगा. 70 प्रतिशत यानी 1.26 करोड़ रुपये बैंक ऋण देगा और 30 प्रतिशत यानी 0.54 करोड़ रुपये मार्जिन व्यवसायी को लगाना पड़ेगा. 60 लोगों को रोजगार मिलेगा. उद्यमी एक वर्ष की शुद्ध आय 32 लाख रुपये औसत होगी. एक इकाई से 5 साल में 90 लाख अंडों का उत्पादन होगा. 10 प्रतिशत का ब्याज माफ होगा, बाकी ब्याज बैंक को 60 किस्तों में अदा करना होगा.

ब्रायलर पैरेंट फॉर्म पर 2.065 करोड़ रुपये खर्च होंगे. 1.45 करोड़ रुपये बैंक ऋण के रूप में देगा, बाकी 16.50 लाख रुपये व्यवसायी को खुद लगाना पड़ेगा. इस योजना में भी 10 प्रतिशत का ब्याज मांफ होगा. बाकी ब्याज का भुगतान बैंक को 60 किस्तों में करना होगा. ■

चौथी दुनिया

आवश्यकता है

संवाददाता, विज्ञापन प्रतिनिधि, प्रसार प्रतिनिधि

चौथी दुनिया के लिए उत्तराखण्ड के सभी मंडल और जिला मुख्यालयों पर अनुभवी संवाददाताओं, विज्ञापन, प्रसार प्रतिनिधियों एवं एजेंसियों के लिए शीघ्र आवेदन करें.

E-mail- konica@chauthiduniya.com
arifali@chauthiduniya.com
चौथी दुनिया F-2, सेक्टर 11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर)
उत्तर प्रदेश-201301,
PH : 120-6450888, 6451999

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, सिद्धार्थनगर

सावधान! खतरा! सावधान

कहीं जहरीली शराब के चक्कर में बर्बाद न हो जाए आप की खुशी

अपील

जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अवैध स्थानों/अड्डों से किसी भी प्रकार की शराब न खरीदें क्योंकि इसमें मिथाइल अल्कोहल भी मिला हो सकता है जो घातक जहर है और इसकी बहुत थोड़ी मात्रा पीने से आदमी अंधा हो सकता है एवं उसकी जान जा सकती है. अतः किसी भी दशा में अवैध स्थानों /अड्डों से खरीद कर शराब का सेवन कदापि न करें. यदि कोई अवैध शराब का निर्माण /बिक्री करता है तो इस नंबर पर तुरंत सूचित करें. आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा.

1. जिला आबकारी अधिकारी सिद्धार्थनगर - मो नं 9454465629
2. आबकारी निरीक्षक क्षेत्र1 नौगढ़ - मो नं 9415635031
3. आबकारी निरीक्षक क्षेत्र 2 बॉसी - मो नं 9415825388
4. हेल्प लाइन का नंबर - 05544-222038

सावधान

सस्ते के चक्कर में जान न गवाएं जहरीली शराब पीने से बचें. उत्तर प्रदेश में वैध शराब पाउच में नहीं बिकती है. इसलिए अपना एवं अपने परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अधिकृत आबकारी ठेके से ही होलोग्राम, सील लगी एवं प्रिंटेड मूल्य पर बोतल खरीदें. बिना होलोग्राम वाली शराब किसी भी हालत में न खरीदें क्योंकि यह पूर्णतया नकली एवं जानलेवा है.

गोपाल जी उपाध्याय
जिला आबकारी अधिकारी
सिद्धार्थनगर

श्रीपर्णा गांगुली
पुलिस अधीक्षक
सिद्धार्थनगर

सूर्य प्रकाश मिश्र
जिलाधिकारी
सिद्धार्थनगर

उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के सभी ज़िलों में वितरण एवं विज्ञापन के लिए संपर्क करें : 0120-6450888, 6451999, मोबाइल : 09266627379